हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 2000

खण्ड - 1, अंक - 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 13 मार्च, 2000

	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों को स्वीकृत (एडमिट) करने संबंधी मामला	(5)1
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(5)4
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)5
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	
श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा	(5)9
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)9
वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना	(5)76
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(5)76
वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान	(5)76

मूल्य :

74.00

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 13 मार्च, 2000

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

प्रश्नों को स्वीकृत (एडमिट) करने संबंधी मामला

श्री भजन लाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का बिज़नैस स्टार्ट होने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में एक बात तय हुई थी कि शार्ट नोटिस पर सवाल दिये जा सकते हैं। इसके लिये आपने भी हां भरी थी और सी.एम. साहब ने भी हां भरी थी। कई मैम्बरों ने सवाल लिखकर दिये हुए हैं और आज तीन दिन हो गये हैं। इसलिए इन सवालों को आज लेना चाहिए था। आपने सवाल लिये नहीं हैं। अगर सवाल नहीं लेते तो इसका मतलब यह है कि हाउस की आगे की कार्यवाही शुरू होने से पहले जीरो ऑवर मान कर चलें। अगर आप जीरो ऑवर में बोलने की इज़ाज़त दें तो मैं कुछ कहूं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए। मैं इस बारे में अभी बताता हूँ। किसी मैम्बर ने अपने सवाल पर शार्ट नोटिस के लिये लिखा ही नहीं है। केवल जनरल क्वैश्चन दे दिये हैं। अगर शार्ट नोटिस के लिये लिखा ही न हो तो उसे शार्ट नोटिस में कैसे लिया जाए। जो मैम्बर अपने सवाल शार्ट नोटिस के लिए लिखेगा उसके सवाल को शार्ट नोटिस में लिया जाएगा और जो शार्ट नोटिस सवाल पर लिखेगा ही नहीं तो उसे डिस-आलउ करना अनिवार्य है। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर तो है ही नहीं। यह तो अन्डरस्टुड है कि वह सवाल शार्ट नोटिस के लिये है।

श्री अध्यक्ष : अन्डरस्टुड कुछ नहीं होता। सवाल के ऊपर कलम से शार्ट नोटिस लिखकर रूल के मुताबिक देना होता है। (शोर)

श्री भजन लाल : बी.ए.सी. की मीटिंग आपकी अध्यक्षता में हुई और आपने ही यह फैसला लिया कि शार्ट नोटिस पर क्वैश्चन लिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, ऐसी बात नहीं है कि शार्ट नोटिस न लिखे या दस्तखत न किये हों तो शार्ट नोटिस में सवाल लिये जाएं। आज शार्ट नोटिस पर सवाल दीजिए और परसों आपके सवाल सम्बन्धित मंत्री की कनसैन्ट से लग जाएंगे। (शोर) अगर नोमिनेशन पेपर पर भी दस्तखत न हों तो नोमीनेशन पेपर भी रिजैक्ट हो जाते हैं। उसमें भी बाकायदा नाम, बाप का नाम व सारी चीजें पूरी होनी चाहिएं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर सवाल पर दस्तखत नहीं है तो उसके लिये तो हम आपको नहीं कहते। (शोर) अध्यक्ष महोदय, आप जो जनरल बात कहते हैं वह तो ठीक है लेकिन यह जनरल बात नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक फरमाया है। यह तो आपको मालूम होगा कि आपके पास किस किस्म के क्वैश्चन आए हैं और किस नोटिस के अन्डर आएं है लेकिन मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास रूल्ज ऑफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिज़नैस इन हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली अप्रैल, 1998 के अपटूडेट रूल्ज हैं। इन रूल्ज में रूल 40 में जो क्वैश्चन्ज के बारे में दिया हुआ है और रूल 40-ए में इनको क्लासीफाई किया गया है कि इस रूल के पार्ट 40-ए में शार्ट नोटिस क्वैश्चन और पार्ट-बी में स्टार्ड क्वैश्चन्ज तथा पार्ट-सी में अनस्टार्ड क्वैश्चन्ज का वर्णन है। यह तो स्पीकर साहब को पता होगा कि शार्ट नोटिस क्वैश्जन्ज आये हैं या स्टार्ड क्वैश्चनज़ आए हैं अथवा अन-स्टार्ड क्वैश्चन्ज आये हैं लेकिन शार्ट नोटिस सवाल जो है That is a separate. अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी जो कह रहे हैं कि बी.ए.सी. में शार्ट नोटिस सवालों की बात हुई थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने भी फरमाया कि शार्ट नोटिस के जो क्वैश्चन्ज आयेंगे वे आगे सरकार को कनसैन्ट के लिये भेजे जाएंगे। बी.ए.सी. में यह भी बात हुई थी कि जिस सवाल के जवाब को देने के लिये मंत्री तैयार होगा उस हिसाब से अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन्ज हाउस में रखेंगे। हम उनका रिप्लाई भी देंगे। लेकिन स्पीकर साहब ने फरमाया कि शार्ट नोटिस के सवाल नहीं हैं। शायद किसी न किसी वजह से वह डिसअलाउड हुए हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी ने नोर्मल हाउस की बात कही है वह तो ठीक है लेकिन यह एबनोर्मल है क्योंकि मैम्बरों के पास पहले से कोई इत्तलाह न होने की वजह से वे कोई क्वैश्चन्ज दे नहीं सकते थे। इसीलिये हमने बिज़नैस एडवाइजरी कमेटी में प्रार्थना की थी कि शार्ट नोटिस क्वैश्चन्ज लगाए जाएं और शार्ट नोटिस का मतलब तीन दिन है। तीन दिन पहले जिन्होंने सवाल दिये हैं उनके सवाल हाउस में लगने चाहिएं। अगर किसी सवाल पर दस्तखत न हो तो उसे मत लें लेकिन बाकी कंडीशन्ज पूरी होने पर तो ये सवाल लगने चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, जो भी डोकूमैंट मेरे पास आता है वह पब्लिक डोकूमैंट हो जाता है। मैं अपनी मर्जी से किसी नोटिस को शार्ट नोटिस बना दूं या किसी नोटिस को किसी और शेप में कंवर्ट कर दूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग जो लिखेंगे उसी के अनुसार ही मुझे कार्यवाही करनी है। अगर आज शार्ट नोटिस पर सवाल दिये जाएंगे तो उनको जवाब के लिये डिपार्टमैन्ट्स को भेजना पड़ेगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर होता है। आप इस बात का भी जवाब दें दे कि क्वैश्चन ऑवर न हो तो उसके बाद जीरो ऑवर में हम अपनी बात कह सकते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन ऑवर नहीं होता तो जीरो ऑवर भी नहीं हो सकता as there are co-related.

श्री सम्पत सिंह : चौधरी भजन लाल जी ठीक फरमा रहे हैं। हमें तो इन्होंने गाईड करना है। अभी इन्होंने हाउस को ठीक एडवाइस दी है। जहां तक मैम्बर्ज के बोलने की बात है, बोलने के बहुत

से अवसर आएंगे। अभी गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, इस पर भी मैम्बर्ज अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से सप्लीमेन्टरी डिमाड्ज आनी हैं, उन पर मैम्बर्ज अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा अभी बजट भी पेश होना है और उस पर भी चर्चा होनी है। बजट पर भी सभी साथी अपनी बात कह सकते हैं। स्पीकर साहब ने बोलने के लिए सभी मैम्बर्ज को काफी समय दिया है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से स्पीकर साहब सभी साथियों को बोलने का समय देते रहेंगे। आपको याद होगा कि शुक्रवार वाले दिन स्पीकर साहब ने सभी को कहा कि जो भी सदस्य बोलना चाहे बोल लें। हुड्डा साहब को भी लॉबी से बुलाकर कहा गया कि आप बोलें लेकिन ये बोले नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब की तरफ से समय देने में कोई कमी नहीं रही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि अभी सम्पत सिंह जी ने कहा है कि मुझे हाउस की लॉबी से बुला कर बोलने के लिए कहा गया था, यह गलत बात है। लॉबी से मुझे कोई बुला कर नहीं लाया।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने के लिए कहा था।

श्री भूपेन्द्र सिंह : ठीक है, आपने कहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आज नहीं, सोमवार को बोलूंगा। मेरा तो कहना यही है कि सम्पत सिंह जी को गलत तथ्य हाउस में नहीं रखने चाहिएं कि मुझे हाउस की लोबी से बोलने के लिए बुलाया गया था।

श्री अध्यक्ष : यह तो सही है कि मैंने आपको बोलने के लिए कहा था।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सम्पत सिंह जी ने कहा कि बोलने के बहुत सारे अवसर आएंगे, यह बात तो ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें कई अवसर ऐसे आएंगे जिन पर हम अपनी बात कह सकेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि जो जीरो ऑवर होता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जीरो ऑवर में सदस्य अर्जेन्ट मैटर उठाता है। अब जीरो ऑवर न होने की वजह से वह अपनी अर्जेन्ट मैटर की बात कह नहीं पायेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि क्वैश्चन ऑवर नहीं हो सकता तो कम से कम जीरो ऑवर की जो आप इजाजत दे ही दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : यदि आप कोई अर्जेन्ट मैटर समझते हैं तो उसके लिए आप काल अटैन्शन नोटिस भी दे सकते हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर का सम्बन्ध क्वैश्चन ऑवर से नहीं है। जीरो ऑवर में अलग इशु उठाये जाते हैं। जीरो ऑवर में वे मुद्दे भी हम उठा सकते हैं जिनका कोई नोटिस आदि देने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम अर्जेन्ट मैटर के कोई भी मुद्दे हाउस में उठा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जीरो ऑवर में जो कोई मैम्बर बोलना चाहे उसे बोलने की इजाजत दी जाये।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर की अभी तक एक ट्रेडीशन रही है कि क्वैश्चन ऑवर के बाद ही जीरो ऑवर होता है। जब क्वैश्चन ऑवर ही नहीं हो रहा तो पिछली ट्रेडीशन के हिसाब से जीरो ऑवर नहीं हो सकता। ट्रेडीशन हर आदमी फॉलो करता रहा है। जैसा कि आपने कहा है शार्ट नोटिस के आप क्वैश्चन दें, वे लगाये जा सकते हैं। यदि मैम्बर्ज शार्ट नोटिस के क्वैश्चन देंगे तो उन

[श्री सम्पत सिंह]

क्वैश्चन को स्पीकर साहब सरकार के पास भेजेंगे। मैं भी हाउस के सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार के पास आये हुए क्वैश्चन का जवाब सरकार देने की भरपूर कोशिश करेगी। अभी भी आप शार्ट नोटिस के क्वैश्चन दे सकते हैं, इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि मैम्बर्ज़ के शार्ट नोटिस के सवाल आयेंगे तो फिर यहां पर क्वैश्चन ऑवर हो सकता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि पार्लियामेंट का प्रोसिजर हमारी विधान सभा से अलग हो। हुड्डा साहब पार्लियामेंट में रहे हैं। ये विधान सभा में पहली बार आये हैं। लेकिन इनके दूसरे बहुत सारे साथी जो काफी पुराने सदस्य हैं जो विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं चौधरी बंसी लाल जी व चौधरी भजन लाल जी तथा और कई ऐसे साथी हैं जो कई बार इस हाउस के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें सारी बातों की जानकारी है, वे अपने नए मैम्बरों को इस बारे में जानकारी दे सकते थे कि कौन सा काम किस ढंग से होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये अपने मैम्बरों को हाउस की कार्यवाही कैसे चले, उस बारे में एजुकेट कर सकते थे। चौधरी भजन लाल जी की यह बात ठीक है कि बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था कि क्वैश्चन लग सकते हैं और इसके लिए सरकार भी सहमत थी। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि शार्ट नोटिस पर क्वैश्चन लग सकते हैं, इसलिए मेरा मैम्बर्ज़ साहेबान से निवेदन है कि यदि वे शार्ट नोटिस पर क्वैश्चन देंगे तो वे अवश्य लगेंगे, ऐसा आपने पहले ही कहा है। क्वैश्चन आने पर सरकार उनका फ्राखदिली से जवाब भी देगी। यदि क्वैश्चन लगते हैं तो उसके बाद जीरो ऑवर भी हो जायेगा। ऐसा होने पर सभी को जीरो ऑवर में अर्जेन्ट मैटर पर बोलने की एपोरच्यूनीटि भी मिल पायेगी।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद माना है कि दो शार्ट नोटिस क्वैश्चन्ज आए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शार्ट नोटिस क्वैश्चन नहीं आए हैं। (विघ्न) आप अभी लिख कर दे दें। कमैंट्स के लिए सरकार को भिजवा देंगे। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। आप एक हैल्दी ट्रैडीशन डालें इससे सरकार को ताकत मिलेगी तथा सरकार को इससे कोई नुक्सान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, देश में फर्टिलाईज़र की बात है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अलाउ किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बहुत ज्यादा बोल चुके हैं इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) सारी बात कायदे कानून से चलेगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी दो कॉलिंग अटैंशन मोशन थीं उनके बारे में आपने क्या फैसला किया है, मेहरबानी करके बताने की कृपा करें। मैं आपसे इन कॉलिंग अटैंशन मोशन पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी की दो कालिंग अटैंशन मोशन्ज थीं एक तो टीचर्ज के बारे में है जो सरकार के पास कमैंट्स के लिए भेजी है और दूसरी मिक्सिंग ऑफ सीवरेज वाटर इन ड्रिंकिंग वॉटर की है वह कल लगेगी। (विघ्न) कल आएगा तभी लगेगी। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। पंचायत के चुनावों के बारे में दैनिक ट्रिब्यून में लिखा है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपकी बात मैंने सुन ली है, अब आप अपनी सीट पर बैठिए। (विघ्न एवं शोर) दलाल साहब, मैं आपका पूरा सम्मान कर रहा हूँ। आप अपनी सीट पर बैठिए। (विघ्न)

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी दो कालिंग अटैंशन मोशन्ज थीं उनका क्या हुआ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपकी एक कालिंग अटैंशन मोशन अबोलिशिंग ऑफ 29 म्यूनिसिपिल कमेटीज के बारे में थी वह डिसअलाउ कर दी है। दूसरी regarding suspension of disbursement of loan के बारे में थी वह अण्डर कंसिड्रेशन है। (विघ्न) एक कालिंग अटैंशन मोशन राव नरेन्द्र सिंह की regarding acquisition of land in Panchkula district थी वह डिसअलाउ कर दी है। (विघ्न)

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, ********

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) जो वह बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion on Governor's address will be resumed.

श्री भूपेन्द्र सिंह (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले नई शताब्दी में इस विधान सभा का गठन हुआ है सभी साथी इलैक्शन से चुन कर आए हैं मैं सभी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हरियाणा बने 34 वर्ष हो गए हैं। जब हरियाणा बना था उस समय हमारी परिस्थिति क्या थी और बाद में विभिन्न दलों की सरकारें यहां रहीं तो हरियाणा की स्थिति क्या है। आज 34 साल के बाद हम कहां पर खड़े हैं इस बात का हम सब को मिल कर विश्लेषण करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी कमी कहां पर रही है और उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हम किन कारणों से पिछड़ गए इस बारे में विचार किया जाना चाहिए जब हरियाणा राज्य बना था तो हरियाणा देश में प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से नम्बर दो पर था। आज 34 वर्ष के बाद इतनी प्रगति होने के बावजूद भी हम सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो आदरणीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है यह एक कांस्टीच्यूशनल ऑब्लीगेशन है। संविधान के अन्तर्गत जो उनकी जिम्मेदारी है वह

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह]

उन्होंने पूरी की है। वे यहां पर आए और उन्होंने यहां पर अभिभाषण पढ़ा। उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मुझे अभिभाषण पढ़ने का भी मौका मिला है, खास तौर पर जैसा कि सम्पत सिंह जी ने कहा है मेरा यहां पर पहला मौका है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कई राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़े और उन पर चर्चा सुनी। यह अभिभाषण पढ़कर कम से कम मुझे ऐसा लगा है कि यह अभिभाषण 34 साल का जो तजर्बा है उन सालों में हरियाणा ने जो उन्नति की उस बारे में कोई चर्चा नहीं है। किसी नीति के बारे में कोई दिशा नहीं है। यह डायरैक्शनलैस अभिभाषण है। यह अभिभाषण केवल डायरैक्टर पब्लिक रिलेशन का भाषण है। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ। इसमें बहुत से मुद्दे कहे गए हैं। हरियाणा के निर्माण में चौधरी देवी लाल जी की चर्चा की है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के निर्माण में उनका हाथ रहा है। लेकिन जिस व्यक्तित्व की वजह से हरियाणा बना, हरियाणा ने प्रगति की उनका भी इसमें नाम लिखते तो अच्छा होता, वे थीं श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हरियाणा अपनी कलम से बनाया था। जो प्रगति कांग्रेस की सरकार के वक्त हुई है वह सारे देश के सामने उदाहरण है। आज अगर हम उस व्यक्ति को भुलाएं जिस व्यक्ति के कारण हरियाणा प्रगति पर है तो ठीक नहीं है उनका नाम सर छोटू राम है, इसमें उनका उल्लेख भी न करें तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आज पंडित जवाहर लाल नेहरू का उल्लेख न करें जिन्होंने भाखड़ा डैम बनवाया यह भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आज से पहले पानी कितना था अब एस.वाई.एल. का कितना योगदान है इसका उल्लेख न करें यह भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें 34 वर्षों का विश्लेषण करने की जरूरत है, राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की जरूरत है। हम एक शताब्दी पूरी करके दूसरी शताब्दी में जा रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों का, हरियाणा के बुजुर्गों का योगदान रहा है उसकी चर्चा हम इसमें न करें, उनके मान सम्मान की बात न करें यह बात भी हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। 34 वर्षों में हमने राजनीति का व्यापारीकरण होते देखा है, अपराधीकरण होते देखा है। हमारे सदन के नेता भी स्वतन्त्रता सेनानी परिवार से हैं इन्हें मालूम है कि कितना योगदान हमारे बुजुर्गों का हरियाणा में रहा है। किस प्रकार की राजनीति हमारे देश में थी और कहां आज हरियाणा खड़ा है इसका संकेत राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में नहीं दिया है।

सबसे पहले मैं कृषि के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। आज हरियाणा और पंजाब कृषि में हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर हैं। आज हमें बाहर से अनाज नहीं मंगवाना पड़ रहा है। अभिभाषण में कई चीजों की चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में यह चर्चा है कि सूखे की वजह से बिजली की कमी हुई और बिजली की कमी से सूखा था लेकिन इस बात का इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है कि इस सूखे की वजह से कोई राहत हरियाणा सरकार ने या केन्द्र सरकार ने उन किसानों को दी हो, उन इलाकों को दी हो जो सूखे की चपेट में आये थे। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में जिस दूसरी बात का बहुत बड़ा ढोल पीटा गया और कहा गया वह यह कि हरियाणा में गन्ने की कीमत हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस अभिभाषण में जो दस सहकारी मिल्ज़ हैं उनके घाटे का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अगर सहकारी मिल्ज़ के गन्ने की कीमत का हिसाब लगाये तो महाराष्ट्र में ऐसी भी सहकारी मिलें हैं जो 150 रुपये का भाव गन्ने का किसानों को दे रही हैं। लेकिन अभिभाषण में इस बात की ऐसे चर्चा की गयी है जैसे चुनावी घोषणा पत्र में चर्चा की जाती है। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में 110 रुपये गन्ने का भाव देने की तो चर्चा की गयी लेकिन यह चर्चा नहीं की गयी कि 110 रुपये का भाव गन्ने की कौन सी किस्म का दिया जायेगा। अगर सी-64 के लिए दिया जाएगा तो इस किस्म का उत्पादन तो हमारा किसान केवल 10 प्रतिशत ही करता है और यदि 106 रुपये का

रेट सी-77 के लिए दिया जाएगा तो इस किस्म का उत्पादन तो केवल 20 प्रतिशत ही है। इसी तरह से गन्ने की किस्म 48 और 67 का उत्पादन तो हमारे यहां पर 70 से 75 परसैंट के बीच है लेकिन उसका भाव 104 रुपये रखा गया है।

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय हुड्डा साहब ने दक्षिण के गन्ने के रेट की चर्चा की। ठीक है कि हुड्डा साहब देश की पार्लियामैंट के सदस्य भी रहे हैं लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपके माध्यम से उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि देश में गन्ने की दो ज़ोन हैं एक हाई रिकवरी ज़ोन और दूसरी लोअर रिकवरी ज़ोन। उत्तरी भारत तो लोअर रिकवरी ज़ोन में आता है तथा दक्षिणी भारत जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं वे इलाके जहां पर चीनी की प्रति क्विंटल जो रिकवरी है वह उत्तरी भारत की तुलना में ज्यादा होती है, आते हैं इसलिए ये इस बात को तो भूल गये कि हमारा ज़ोन कौन सा है। अध्यक्ष महोदय, लोअर रिकवरी ज़ोन में जितने भी प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों से हमारे माननीय मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभिभाषण में यह चर्चा की गयी है कि पूरे देश में गन्ने का भाव सबसे ज्यादा हरियाणा में दिया गया है और मैं इसी रैफरैन्स में यहां पर बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैं पहली दफा विधानसभा में सुनकर आया हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इनको हर बात का बीच में जवाब नहीं देना चाहिए। इनको भी जवाब देने का मौका मिलेगा। यहां के रीति रिवाज क्या हैं उनका तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन लोकसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको पहले हमारी बात सुननी चाहिए। मंत्री जी को और सरकार को जब मौका मिलेगा तो ये जवाब दे सकते हैं। मैंने तथ्य से परे तो कोई बात नहीं कही है। अध्यक्ष महोदय, दस रुपये क्विंटल के हिसाब से जो किसान की जेब से गन्ने का किराया भाड़ा काटा जाता है उसकी तो इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। कहने को ही 104 रुपये हैं लेकिन किसान को असल में मिलता कितना भाव है ? लेकिन इन्होंने इस बात की कोई चर्चा नहीं की। असल बात यह है कि किसान को कितना भाव दे रहे हैं। इस बात की भी इसमें चर्चा नहीं है कि यदि किसान को गन्ने की 14 दिन से ज्यादा डिलेड पैमेंट मिलेगी तो क्या उसे उस पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं ? दस सहकारी शूगर मिल्ज़ में से किसानों को तीस चालीस करोड़ रुपये की डिलेड पैमेंट हुई है लेकिन उसका कोई ब्याज किसान को नहीं मिला है इसलिए इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गन्ना एक ऐसी खेती है जो किसान को जीवित रखती है। पहले जितना गन्ना किसान देता था उसकी ऐवज में कुछ चीनी भी उसको मिलती थी। आज सवाल महाराष्ट्र या किसी ज़ोन का नहीं है सवाल इस बात का है कि जितनी भी सहकारी चीनी मिल है। सरकारी मिलों का किस प्रकार से सरकारीकरण किया हुआ है यह कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं होगी और इस बात का दोष मैं आपकी सरकारी को नहीं दे रहा हूँ यह मैं पिछले 34 वर्षों की चर्चा कर रहा हूं जो कमीपेशी है उसको दूर करना चाहिये। सरकार जब तक इनका सरकारीकरण बन्द नहीं करेगी तब तक किसान को इसके उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आज शूगर मिल का चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर आई.ए.एस. है, जी.एम. ब्यूरोक्रेट है तो जब तक सरकारीकरण खत्म नहीं होगा तब तक लाभ नहीं मिल सकता है। महाराष्ट्र में 150 रुपये केवल रिकवरी के हिसाब से मिलता हो केवल यह बात नहीं कह सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को फिर से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि देश में दो ज़ोन हैं एक हाई रिकवरी ज़ोन है दूसरा लो रिकवरी ज़ोन जहां लो रिकवरी

[श्री धीरपाल सिंह]

ज़ोन की तुलना में हाई रिकवरी ज़ोन में प्रति क्विंटल 3-4 किलो चीनी की रिकवरी ज्यादा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी उदाहरण है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी उस समय पिछली सरकार द्वारा छोड़ा गया गन्ने का बकाया 21 करोड़ रुपये था और इस सरकार ने गन्ने की बकाया रकम की पेमेन्ट की है। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीगण को समझाएं कि जब जवाब देने का समय आएगा तब सारी बात का जवाब दे दें अगर एक-एक बात का बीच में ये जवाब देंगे तो डिबेट के क्या मायने रह जाएंगे और जो वक्ता है वह अपनी बात जो कह रहा है उसे भूल भी सकता है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठ जाइए।

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय व चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय हम उधर बैठते थे। बंसी लाल जी की सरकार के समय में श्री कर्ण सिंह दलाल बार-बार बीच में इन्टरवीन करके जवाब देते थे। यह तो यहां की परम्परा रही है। हमने तो इस परम्परा को तोड़ा है और समय मांगकर बोले हैं।

वित्त मंत्री (श्री संपत सिंह) : भजन लाल जी, आप बहुत बड़ी बात कह गए । आपने कहा है कि बीच में इन्टरवीन करने से हुड्डा साहब भूल जाएंगे और अपनी बात नहीं कह सकेंगे। ये इतने सीनियर लीडर हैं आपकी पार्टी के प्रैजिडैंट हैं तीन बार पार्लियामैंट के मैम्बर रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये भूल जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : गन्ने के बारे में स्पष्टीकरण चौधरी भजन लाल जी दे दें कि इनके समय में गन्ने का बकाया कितना था ? पानीपत शुगर मिल ने किसानों की तीन साल तक पेमेन्ट नहीं की थी।

श्री भजन लाल : ऐसा कभी नहीं हुआ। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए बैठ गए होंगे। न तो किसी ने असैम्बली में यह बात उठाई न पार्लियामैंट में उठाई न कभी हमें कहा।

श्री अध्यक्ष : यह बात हुड्डा साहब कह दें तो हम मान लेंगे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल की सरकार गन्ने का 50 करोड़ रुपये बकाया छोड़कर गई थी।

श्री संपत सिंह : बकाया इधर से भी था, बकाया उधर से भी था। हमने वह बकाया दिया है आपको तो गवर्नमैंट का वैलकम करना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा में मेरा नाम लिया गया है मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपके बारे में कुछ नहीं कहा है नाम लेकर कहा है वह तो जवाब चौधरी बंसी लाल जी ने दिया है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी धीरपाल सिंह ने यह कहा है कि कर्ण सिंह दलाल बार-बार दखल देते थे हमने तो परम्परा को तोड़ा है जबकि धीरपाल जी को यह कहना चाहिए था कि हमने तो परम्परा को कायम रखा है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा-

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि चौधरी धीरपाल जी ने मेरा नाम लिया है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब पिछली सरकार में मैं मंत्री था उस समय जब इस सदन में कोई चर्चा होती थी उसके बारे में जवाब देने के लिए मुझे बीच में खड़ा होकर स्पष्टीकरण देना होता था। लेकिन मैं आज की सरकार की तरह जवाब नहीं देता था।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप बैठिए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी धीरपाल सिंह जी को और चौधरी सम्पत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने थोड़ा हमारा समर्थन किया। जैसा कि चौधरी धीरपाल जी ने यह कहा कि मुझे कृषि के बारे में ज्ञान नहीं है तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं केन्द्र की एग्रीकल्चर कमेटी का मैम्बर रहा हूं और मैंने सारे देश का दौरा किया है और मुझे यह सब मालूम है कि कौन सा जोन हाई रिकवरी का है और कौन सा जोन लोअर रिकवरी का है। यह जो सहकारिता का सरकारीकरण किया गया है इस वास्ते किसानों को लाभ नहीं पहुंचा है। परन्तु महाराष्ट्र में किसानों को लाभ इसलिए पहुंचा है क्योंकि वहां पर सहकारिता को सहकारिता तक ही रखा है इसलिए जो भी घाटा या मुनाफा होता है वह सहकारिता का ही होता है। इसलिए हमें भी जो हमारी 10 शुगर मिल्ज हैं, जो घाटे में चल रही हैं उनका सरकारीकरण खत्म करना चाहिये। क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठा रही है या नहीं?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सारी शुगर मिल्ज घाटे में नहीं चल रही हैं। हुड्डा साहब यह आधारहीन बात कह रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो शुगर मिल्ज ज्यादा घाटे में चल रही हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब, अपने विपक्ष के नेता से ज्ञान लेकर सही बात कहें ऐसे आधारहीन बात इन्हें सदन में नहीं कहनी चाहिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्ञान तो मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से ले लूंगा। मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता। अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूँ। आज हमारे प्रदेश में कृषि नीति बनाने की जरूरत है। कृषि नीति को बनाकर उसे आगे बढ़ाया जाये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि यह सरकार किसानों का ख्याल रखेगी। जब धान की फसल का मौसम था तब मैं दस मंडियों में खुद जाकर आया था। जितनी सरकारी धान की खरीद हुई उसका किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला। मैंने सोचा कि अगर किसानों को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिला तो कम

[श्री भूपेन्द्र सिंह]

से कम गरीब आदमी को तो सस्ते दाम पर चावल मिलता होगा परन्तु जिस धान का भाव किसानों को 520 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिये उसका भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल था यह बात सभी की नॉलिज में है किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके बाद यूरिया और डीज़ल के भाव बढ़ गये हैं। यूरिया और डीज़ल के दाम बढ़ने के बावजूद भी इस अभिभाषण में इस के बारे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चर्चा अवश्य की गई है कि दस रुपये कम कर दिये गये हैं। परन्तु इसके बाद भी भाव बढ़ा है। यूरिया और पी.डी.एस. का भाव दुगुना हो गया है। किसान और गरीब आदमी पर इसकी मार पड़ने जा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसानों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं इस बात का उल्लेख इस अभिभाषण में कहीं नहीं किया गया है। जहां तक बिजली और पानी का सवाल है। बिजली के बारे में काफी उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है। बिजली की जितनी परियोजनाओं का उल्लेख किया है। लेकिन इस सरकार के आने के बाद से इन परियोजनाओं पर कोई काम नहीं किया गया है। ये परियोजनाएं या तो कांग्रेस सरकार के समय की हैं या फिर देवी लाल जी की सरकार के समय की हैं और यह अच्छी बात है। बिजली के बारे में अभिभाषण में नहीं बताया गया कि यह सरकार बिजली के बारे में क्या स्पष्ट नीति अपनाने जा रही है। यह सरकार बिजली बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या कर रही है और किसानों के लिए बिजली का क्या रेट रखेगी। फ्री बिजली पानी का नारा तो खत्म हो गया है इस बारे में मैं दोष नहीं देता कि मुख्य मंत्री महोदय अपने चुनाव के दौरान किए गए वायदे से पीछे हट गए हैं। जब ये कहते हैं कि हम फ्री बिजली पानी नहीं दे सकते। मैं तो कहता हूं कि यह ठीक बात है इनको साफ बात कहनी चाहिए, इनकी बात में ट्रांसपैरेंसी होनी चाहिए इन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं की है कि ये किसानों को किस रेट पर बिजली देंगे और क्या ये बिजली के रेट बढ़ायेंगे और क्या कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने रिइम्बर्समैंट सस्पैंड कर दी है। अध्यक्ष महोदय, यहां एस.वाई.एल. का जिक्र किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एस.वाई.एल. हरियाणा प्रदेश के किसानों की ही नहीं बल्कि सभी लोगों की जीवन रेखा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह मामला इतने लम्बे समय से लटका हुआ है और विधान सभा के हर सत्र में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, मैं तो कहता हूं कि यह हरियाणा प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा से हटकर राजनेताओं की जीवन रेखा बन गया है। वोट लेने के लिए कई तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं लेकिन सरकार बनने के बाद उन मुद्दों को सीरियसली नहीं लिया जाता। आज मौका है श्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और हमारे सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के उनके साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। आज केन्द्र में भी बी०जे०पी० की सरकार है इसलिए ये एस०वाई०एल के मुद्दे को सुलझा सकते हैं। ये बताएं कि राजीव-लौंगोवाल समझौते के बारे में इनका क्या रुख है ? इस सरकार को बने हुए 7 महीने हो गए हैं लेकिन आज तक इस एस०वाई०एल० के मुद्दे को सुलझाने के लिए न कोई बात आई है और न ही कोई ऐसा प्रयास किया गया है। आज हम सब यहां बैठे हैं, हम कोई समय निर्धारित करें, सदन के नेता 3,4,5 या 6 महीने समय निर्धारित करें कि हम इतने समय में एस०वाई०एल० के मुद्दे को सुलझा देंगे। आज पूरा सदन इनके पीछे खड़ा है, ये कोई भी फैसला करें हम हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वार्ता के नाम पर हमें हरियाणा की जनता को धोखा देने का काम नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे को राजनेताओं की जीवन रेखा न बनाकर किसान और मजदूर की जीवन रेखा बनाकर चलेंगे तो इस समस्या का अवश्य ही समाधान हो जाएगा। आज तीन मुद्दे हैं जिनका राज्यपाल महोदय ने यहां पर उल्लेख किया। पहला मुद्दा पंजाब से हमारा हिन्दी भाषा क्षेत्र का है, दूसरा मुद्दा पानी का है और तीसरा मुद्दा राजधानी का है। आज पूरे सदन को एक बात लेकर चलना चाहिए कि हमारी

प्राथमिकता पानी की है। पंजाब हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। इन तीनों मामलों को इकट्ठा उलझा कर के और लम्बा नहीं करना चाहिए। हमें समय निर्धारित करके पानी का फैसला करना चाहिए, राजधानी का फैसला करना चाहिए, हिन्दी भाषी क्षेत्र का फैसला करना चाहिए। जब तक ये तीनों मामले इंटरलिंक्ड रहेंगे तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में कहना चाहूंगा। इस बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में वास्तविक सफलता केवल एस०वाई०एल० नहर से स्टेट के हिस्से का रावी व्यास का पानी मिलने पर ही प्राप्त होगी। इसके इलावा ये कहते हैं कि एस०वाई०एल० कैनाल द्वारा रावी व्यास का हमारे हिस्से का पानी मिलने पर ही दक्षिणी हरियाणा के लोगों को पूरा पानी मिलेगा। वे ऐसी बातें कहकर दक्षिणी हरियाणा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा में जो पानी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम है इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय जवाब देते समय बताएं। इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहीं भी नहीं बताया गया कि आज कहां कितना वाटर अलॉउस है। आज नहरी पानी में दक्षिणी हरियाणा का जो हक है, वह पानी दक्षिणी हरियाणा को देने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज वाटर अलॉउस में बहुत फर्क है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ये पिछले 20 दिन की ही बात कर रहे हैं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 20 दिन की बात नहीं कर रहा। मैं तो जब से हरियाणा बना है तब की बात कर रहा हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने हिन्दुस्तान टाईम्स में मुख्य मंत्री महोदय का इंटरव्यू पढ़ा। उसमें मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि इनसे जो गलतियां पहले हुई वे दोबारा नहीं करेंगे। उनसे सबक लेंगे। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो भी गलतियां पिछले 34 साल में हुई उनसे हमें सबक लेना चाहिए और उन्हें ठीक करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में जितना पानी है उसका न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। हरियाणा के अंदर पानी का न्यायोचित बंटवारा नहीं हो रहा है। कहीं पर तो 23-23 दिन पानी महीने में चलता रहता है और कहीं-कहीं पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। पानी के बंटवारे में क्षेत्रीय असमानता नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भेदभाव की नीति को प्रदेश की जनता ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार आज इस स्थिति में है कि उस पर दबाव डाले तथा हरियाणा प्रदेश में नये आटोमिक थर्मल प्लांट लगवाये ताकि हमारी बिजली की समस्या दूर हो। अध्यक्ष महोदय, हाईडल प्रोजैक्ट से जो बिजली मिलती है वह सस्ती मिलती है। इसलिए यह बिजली कृषि क्षेत्र को देनी चाहिए। हमें किसानों की समस्याओं के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो पांच औद्योगिक टाउन हैं वहां पर एक नीति बनाकर कैपटिव पावर स्टेशन लगाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यमुना के पानी के बारे में हमारा दिल्ली सरकार से एग्रीमेंट हुआ था लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहीं नहीं लिखा कि मौजदा सरकार यमुना के पानी के बारे में दिल्ली सरकार से बात करेगी। क्योंकि मौजूदा सरकार ने वह पानी न मिलने पर बहुत शोर मचाया था। इस बारे में सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा के इलाके में राजस्थान से साबी, धोम, कृष्णावती आदि नदियों का पानी आता था। जिससे वहां की जमीन चार्ज होती रहती थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने काफी समय से इन नदियों का पानी बंद कर रखा है, इस बारे में भी अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई। अब हरियाणा की तरफ इन नदियों का पानी नहीं आता। इसलिए

[श्री भूपेन्द्र सिंह]

मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे राजस्थान सरकार से बात करके इन नदियों का पानी हरियाणा में लायें ताकि दक्षिणी हरियाणा के किसानों के ट्यूबवैल्ज का पानी का लैवल ऊपर आये। अध्यक्ष महोदय, आज से पांच साल बाद हरियाणा प्रदेश को 34 एम०ए०एफ० पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी पूर्ति सरकार कैसे करेगी। इस बारे में भी अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया और आज हमारे पास सिर्फ 18 एम०ए०एफ० पानी उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने रेणुका डैम के बारे में क्या सोचा है ? किस प्रकार से पानी के साधन बढ़ायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे महम के भाई ने जे०एल०एन० और दूसरी नहरों से सेम की जो समस्या आती है उसके बारे में बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया था। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जे०एल०एन० और दूसरी नहरों के साथ लगती कई एकड़ जमीन खराब पड़ी है। उसको ठीक करना चाहिए। चाहे सरकार इसके लिए डिच ड्रेन बनाये, चाहे कुछ और करे। किसानों को इस समस्या से निजात दिलानी चाहिए। दूसरा जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसका हम मैनेजमैंट कैसे करें इस बारे में भी सोचना चाहिए। इस बारे में ईजराइल हमारे सामने उदाहरण है कि पानी की एक-एक बूंद कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। जो पानी फालतू होता है वह सब-स्वायल कैनाल्स से बचेगा या ड्रीप ईरीगेशन से बचेगा। इस बारे में हमें सोचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी यूटीलाईज करना चाहिए तथा रिजनल इंबैलेंस भी तभी खत्म हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मौजूदा सरकार ने समाज कल्याण और विकास की बात बहुत जोर-शोर से उठाई है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। इस बारे में बहुत ज्यादा उपलब्धियां पढ़ी गई हैं। जबकि ये सब उपलब्धियां थोथी और खोखली नजर आती हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गई है। उसके अनुसार वर्ष 2000-2001 में एक साल के दौरान सिर्फ 12 हजार व्यक्तियों को आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। जबकि हरिजनों की संख्या इस प्रदेश के अन्दर 19 या 20 प्रतिशत के करीब है। हरिजन भाई बहुत सालों से पिछड़े हुये हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग केवल 12000 हरिजन भाइयों को आर्थिक मदद देकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज़ के 2100 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिये जाने की बात कही गई है जबकि हरियाणा प्रदेश में इनकी जनसंख्या 17 प्रतिशत या 18 प्रतिशत जरूर है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में बुढ़ापा पेन्शन 100 रुपये से 200 रुपये करने की बात कही गई है। इसके लिये मैं भी सत्ता पक्ष के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि यह एक अच्छा कदम है। हमारा भी प्रयास था कि कई सालों से बुढ़ापा पेन्शन 100 रुपये चल रही है इसलिए इसे बढ़ा कर 200 रुपये किया जाना चाहिए। हम कहना चाहते है कि इसको आगे भविष्य के लिए मंहगाई के डियरनैस अलाउंस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर बार यह चुनावी मुद्दा होता है। चुनावों से पहले तो 200-200 रुपये या 300-300 रुपये पेंशन के बंटवा दिये जाते हैं लेकिन चुनावों के बाद में समय पर सरकार के पास बुढ़ापा पेंशन देने के लिये पैसा ही नहीं मिला। बुढ़ापा पेंशन हर महीने समय पर देनी चाहिये और इसके लिये बाकायदा एक तारीख निर्धारित होनी चाहिये। हर साल इसके लिये चाहे 2 या 5 प्रतिशत या 7 प्रतिशत फण्डस अलग से रखने चाहिएं। इससे भी बढ़ा इज़ाफा होगा। कोई भी दल वोट लेने से पहले इस तरह की घोषणाएं करता है कि हम 200 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे और अब की बार तो तीन उंगलियां भी दिखाई गई हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को बताना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और मतभेद होंगे भी क्योंकि हम अलग-अलग दलों के सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, ये भी फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं और मैं भी फ्रीडम फाइटर परिवार से हूं। पिछली शताब्दी में हमारे कई हजारों-

लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी हैं लेकिन इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। केन्द्र सरकार ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन में मंहगाई भत्ता साथ जोड़ा है। मैं सदन के नेता को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे भी इस ओर ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात पीले राशन कार्डों को जारी करने की है जिनके लिये बार-बार गरीब लोग मांग कर रहे हैं। किसी भी गांव में जाएं या किसी भी शहर में जाएं, वहां पर शिकायतें मिल रही हैं कि गरीबी रेखा का सर्वे ठीक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आप जरा अपनी बात शार्ट करिए क्योंकि बाकी सदस्यों ने भी बोलना है। आपको प्रोपोशनिट टाइम तो जरूर मिलेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे गरीब लोग इस गरीबी रेखा के सर्वे में कवर होने से वंचित रह गये हैं। जो लोग वंचित रह गये हैं उनका नाम भी गरीबी रेखा के सर्वे में आना चाहिए। लेकिन इस बात की भी अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं शहीदों के बारे में कहना चाहूंगा। कारगिल में तथा देश की दूसरी जगहों पर जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 5 लाख रुपये देने की घोषणा चौधरी बंसी लाल सरकार ने की थी और वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है। यह एक अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन यह तथ्य से परे की बात है क्योंकि शहीदों को जो 10 लाख रुपये की राशि दी जा रही है वह जनता के सहयोग से दी गई है। 10 लाख रुपये में से 8 लाख रुपये लोगों ने डुनेट किये। केवल 2 लाख रुपये ही सरकार की ओर से दिये गये हैं। अच्छा होता अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन लोगों का भी धन्यवाद किया गया होता जिन्होंने यह राशि शहीदों के लिये डुनेट की है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उन शहीदों के परिवारों को नौकरी देने की बात कही है जो कारगिल में "विजय आप्रेशन" के दौरान शहीद हुये। अध्यक्ष महोदय, नौजवान कारगिल में शहीद हों, या असम में बोर्डर की रक्षा करते हुये अथवा देश की रक्षा करते हुये शहीद हों उन सबके परिवारों को नौकरी देने की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने केवल "विजय आप्रेशन" में जो नौजवान शहीद हुए उनके आश्रितों को नौकरी देने की बात कही है। देश की रक्षा करके जो नौजवान घर में वापिस आते हैं उन एक्स सर्विसमैनों को भी इस तरह की कोई सुविधा देने के सम्बन्ध में इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय बड़े भाई श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से यह जानना चाहूंगा कि पहले जब 1965 और 1971 में देश की रक्षा करते हुये जो नौजवान शहीद हुए थे, उस टाइम की सरकार ने उन शहीदों के लिए क्या किया था ?

श्री भूपेन्द्र सिंह : भाई बलबीर जी की अच्छी भावना है। अच्छी भावना पर हमें एतराज भी नहीं होना चाहिए लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहने से काम नहीं चलता कि पिछली सरकार ने ऐसा किया था। आज सवाल यह है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। पहले कोई काम ठीक नहीं हुआ तभी तो आप यहां पर बैठे हैं। हरियाणा बने हुए आज 34 वर्ष हो चुके हैं। हमने पिछले 34 सालों का अवलोकन करके काम करना चाहिए ताकि पीछे जो कमी हमसे रह गई है वह आगे न हो।

अध्यक्ष महोदय, अगली बात मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों के बलबूते पर ही कोई सरकार अपनी नीतियों को इम्पलीमेंट करवाती है। सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी उनका इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया। न ही इस बात

[श्री भूपेन्द्र सिंह]

का जिक्र किया गया है कि जो फिफथ पे-कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाने पर एनोम्लीज रह गई थी वे दूर की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, उसका भी जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। इसी प्रकार से दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वे सुविधाएं हरियाणा में दी जाएंगी या नहीं, उनका भी इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे माननीय हुड्डा साहब लोक सभा के मैम्बर रहे हैं। ये शहीदों को सुविधाएं देने के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं। हम इनकी बातों से सहमत भी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये बताएं कि इनके दिल में शहीदों के प्रति कितनी हमदर्दी है ? मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लोक सभा के मैम्बर्ज को लोक सभा की तरफ से कुछ ग्रांट मिलती है। ये बताएं कि उस ग्रांट में से इन्होंने कितना पैसा शहीदों के नाम किसी गांव में या शहर में किसी सामूहिक नाम से कोई संस्था आदि बनाकर लाईब्रेरी खोलने के लिए या दूसरे काम के लिए कितनी ग्रांट दी ? चौधरी देवी लाल जी ने सामूहिक तौर पर शहीदों के नाम से लाईब्रेरी आदि खोलने के नाम पर 2-2 लाख रुपये दिये हैं। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप भी ऐसा करते तो बहुत ही अच्छा रहता।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय साथी को ज्ञान जरूर होगा कि जब यह कारगिल का इशु हुआ था, तब लोक सभा के चुनाव भी साथ ही साथ आ गये थे जिस कारण लोक सभा का मैम्बर ऐसी ग्रांट किसी डिवैल्पमैंट के काम के लिए नहीं दे सकता था। राज्य सभा का मैम्बर ऐसी ग्रांट दे सकता था। मैं उस वक्त लोक सभा का मैम्बर था और चौधरी देवी लाल जी राज्यसभा के मैम्बर थे। वे इस तरह की ग्रांट दे सकते थे, मैं नहीं दे सकता था। ग्रांट देने के बाकायदा नियम बने होते हैं, उन्हीं के हिसाब से कोई ग्रांट आदि दी जानी होती है।

श्री गोपी चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से जानना चाहता हूं कि जब सौंध गांव में शहीदों के बारे में एक स्टेज पर मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग के बाद हुड्डा साहब दो किलोमीटर के फासले पर जा कर उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जा नहीं सके थे। ये वहां से लड्डू तो खा कर आ गए लेकिन उस शहीद के घर तक दो शब्द कहने के लिए नहीं गए।

श्री भूपेन्द्र सिंह : जो बात आप कह रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप जो दिल में आये आप कहें।

श्री गोपी चन्द : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने गलत बात कही हो तो हुड्डा साहब बता दें। ये तो बड़े लीडर थे। हम तो इनके मुकाबले कुछ नहीं थे। हम लोग वहां पर गए थे लेकिन हुड्डा साहब नहीं गए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप बताएं कि वहां पर आप गए थे या नहीं गए थे?

श्री भूपेन्द्र सिंह : अवतार सिंह भडाना जी भी गए थे। मैं भी गया था। मुझ से जहां तक संभव हो सका हर जगह आने का प्रयास किया है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, गोपीचन्द जी ने जिस सौन्ध गांव में मीटिंग का जिक्र किया उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वह गांव मेरे हल्के हथीन में पड़ता है। वहां पर गोपी चन्द जी भी थे, मैं भी था, हुड्डा साहब भी थे और दूसरे कई और लोग थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हुड्डा साहब मीटिंग से वापिस आ गए लेकिन उस शहीद के घर तक नहीं गए।

श्री गोपी चन्द : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त उस कांस्टीच्यूंसी को श्री हर्षकुमार जी रिपरजेंट करते थे, वे भी गए थे, लेकिन हुड्डा साहब नहीं गए।

श्री अध्यक्ष : गोपी चन्द जी आप बैठिये। यह तो किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन क्या करता है। आप बैठिये।

श्री गोपी चन्द : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है इसलिए मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे रहा हूं। आप स्वयं इस बात को वैरीफाई करवा लें कि कितने शहीदों के यहां पर मैं गया हूं और ये कितने शहीदों के यहां गए हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह बात तो ये खुद ही मान रहे हैं। वैसे भी यह तो मर्ज़ी की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह : यह गए हैं तो यह अच्छी बात है ऐसे मामलों में तो सब को जाना चाहिए कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से उनके यहां गए हैं और कुछ लोग नहीं भी गए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस कर्मचारियों के बारे में चर्चा कर रहा था। एस०सीज़० और वी०सीज़० का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन उनकी सर्विसिज़ में परमोशन में जो बैकलॉग है और जो भर्ती में उनका बैकलॉग रह गया है उनकी यहां पर कोई चर्चा नहीं करता है। इसी तरह से ट्रांसफर पॉलिसी की भी कोई चर्चा नहीं है तथा एड-हॉक टीचर्ज की भी कोई चर्चा नहीं है। चौधरी बंसी लाल जी यहां पर बैठे हुए हैं। जब चुनाव की बात चल रही थी तो कोई 50 हज़ार, कोई 70 हज़ार कोई, चालीस हज़ार ट्रांसफर के बोलता था, इसको वे बेहतर ढंग से जानते होंगे मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। वे बेहतर बताने की स्थिति में हो सकते हैं, न जाने कितने लोगों का उसमें सहयोग था। कितने ही ऐसे बेरोज़गार थे जिनको रोज़गार मिल सकता था। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि सरकार बताए कि वे स्थान रिक्त क्यों हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन रिक्त स्थानों के बारे में सरकार क्या करने जा रही है, वे रिक्त स्थान कब भरे जाएंगे, कितनी नौकरियां उपलब्ध की जाएंगी। जो एडहॉक टीचर्ज हैं उनका क्या होगा, जो पटवारी सिलैक्ट हो गए थे, उनका क्या होगा, सैक्रेटरीज़ के लिये जिनका सिलैक्शन हो गया था उनका क्या होगा इस बारे में सरकार अपना स्पष्टीकरण सदन में दे। मैंने सुना है कि टीचर्ज के लिए पहले कंडीशन थी कि डोमिसाईल हरियाणा का होगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपको बोलते हुये पौन घंटा हो गया है इसलिए अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं मैं केवल कुछ मिनट का समय और लूंगा। बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है और सरकारी नौकरियों में प्रवेश की उम्र 35 साल से बढ़ा कर 40 साल करके इस सरकार ने एक बड़ी अच्छी बात की है। जब मैं यह अभिभाषण पढ़ रहा था या कोई बाहर का आदमी इसको पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे 35 साल तक की उम्र के सभी लोगों को रोज़गार मिल गया है इसलिए यह उम्र की सीमा 40 साल तक बढ़ा दी गई है। अब तीन या चार साल के बाद चुनावों के लिए जाएंगे तो यह उम्र की सीमा 40 साल से बढ़ा कर 45 साल करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए देखने वाली बात तो यह है कि रोज़गार के कितने साधन बढ़े हैं इसके बारे में चर्चा करें, कितनी नौकरियां लगेगी। अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं कर्नाटक या आंध्र प्रदेश की तरह इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग

[श्री भूपेन्द्र सिंह]

एजुकेशन पर हम जोर नहीं देते, क्यों आज यहां पर इण्डस्ट्रीज़ नहीं आ रही है। इण्डस्ट्रियल ग्रोथ 7.2 प्रतिशत से घट कर 5.2 प्रतिशत पिछले कुछ समय में आया है। इस सरकार के द्वारा ऐसी कोई नीति बनाई जानी चाहिए जिससे इण्डस्ट्रीज़ यहां पर आए और रोज़गार के नये-नये अवसर पैदा हों। कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब अखबार में डाका, कत्ल या अपहरण की घटनाएं न छपती हों। हो सकता है गुड़गांव में अपराधों में कुछ कमी हो। गुड़गांव में भी एक अजीब बात देखी है कि किसान को कम्पनसेशन दे कर वापिस लिया गया है। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। (विघ्न) क्या कानून व्यवस्था इतनी सुधर गई है कि आनन्द सिंह डांगी की सिक्योरिटी वापस ले ली, बीरेन्द्र सिंह की सिक्योरिटी वापस ले ली, हरपाल सिंह की सिक्योरिटी वापिस ले ली। लेकिन अखबारों में छपता है कि कहां पर डकैती, अपहरण या कत्ल की घटनाएं हुई हैं। (विघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। हुड्डा साहब पार्लियामैंट के एक वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा क्यों कि उन्होंने कानून-व्यवस्था की बात कहीं है। पिछली सरकार में भरत सिंह अध्यापक का बेटा जो कि गन्ना बेच कर आ रहा था उसका दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था और वहां पर तत्कालीन मंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगर कातिलों को अरैस्ट नहीं कर पाए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। शायद उनको संरक्षण था। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई और सात दिन के अन्दर-अन्दर वे अपराधी जेल के अन्दर बन्द हैं। अध्यक्ष महोदय, मदनपुर का एक गडरिया था वह भेड़ें चरा रहा था दिन दिहाड़े उसको मार दिया गया लेकिन इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की दृष्टि से आज स्टेट की स्थिति काफी संतोषजनक है। (विघ्न)

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। कनीना रोड पर 15 लोगों के गिरोह ने सरिये लगा कर रोड पर ट्रकों को रोका और कमरों में बन्द करके लोगों को पीटा। ट्यूबवैल पर जो मीटर की कोठियां होती है उनमें ले जा कर लोगों को बन्द किया गया और पीटा गया। (विघ्न एवं शोर)

12.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** बहन जी आप बैठिए। आप गैर-जिम्मेदाराना बात न करें। यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की पोजीशन अच्छी नहीं है। इन्होंने लोकल सैल्फ गवर्नमैंट की बात कही है। एक तरफ इन्होंने 29 कमेटियां खत्म कर दी हैं और एक तरफ ऐसी बात करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इनको दोबारा से बहाल करें। हमें मिलजुल कर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल रंगा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री हुड्डा जी ने आरक्षण की बात कही है। बैकलॉग की बात कही है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए चौटाला जी की पार्टी ने रिजर्व कैटेगरी के 17 विधान सभा के सदस्यों को यहां पर भेजा है। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा बैकलॉग को पूरा करने के लिए हम नोटिफाई कर चुके हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे लोकसभा में प्वायंट ऑफ आर्डर के लिए कानून डिसाइड करना पड़ता है क्या यहां पर भी उसी तरह से है।

श्री अध्यक्ष : यहां पर पुरानी कन्वेशन है और वही चली आ रही है, मैंने भी उसी कन्वेशन को माना है।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलते हुये सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने और मेरे जैसे मध्यमार्गी सदस्यों ने कई बातें की। पानी की बात की लेकिन किसी ने राजधानी की बात नहीं की। नई राजधानी के बारे में राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में भी कोई जिक्र नहीं है। राजधानी का जिक्र इसमें आना चाहिए था। यह बहुत ही जरूरी मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं एम०एल०एज० की ग्रांट के बारे में कहना चाहता हूं कि ग्रांट पार्लियामैंट में दोगुनी हो गई है तो इसको दुगना करना चाहिए और इसको दोबारा से चालू करवाने की अध्यक्ष जी आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह बात दिल में सबके है कि यह दुगनी हो जाए और लागू हो। ठीक है कि सत्ता पक्ष वाले इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि कहीं मुख्य मंत्री जी नाराज न हो जाएं इसलिए कहो मत। लेकिन दिल में सबके हैं कि एम०एल०एज० की ग्रांट दोबारा शुरू हो जाए। अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता पक्ष विपक्ष में था तो गुरनाम सिंह आयोग के बारे में काफी लम्बी चौड़ी बातें उन्होंने उठायी थीं। अब वे सत्ता में है तो उनको इस बारे में भी अपनी नीति बनानी चाहिए कि इस आयोग की जगह कोई नया आयोग बनाया जाएगा या नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का भी जिक्र था कि दस रुपये डी०ए०पी० या यूरिया खाद पर घटा दिये गये हैं लेकिन इन्होंने जो केन्द्र सरकार से मिलकर इस पर दाम बढ़वाए थे उसका जिक्र भी इनको अभिभाषण में करना चाहिए था। सारी बातें इसमें होनी चाहिए थीं। अभिभाषण में बिजली के आंकड़े भी पेश किए गए तथा नयी स्कीम्ज के बारे में भी कहा गया जिनके बारे में सबको मालूम ही है लेकिन मैं आपके द्वारा एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि न तो पिछली सरकार ने और न ही इस सरकार ने नये ट्यूबवैल्ल के कोई कनैक्शंज जारी किए हैं। थोड़े बहुत कनैक्शंज जारी भी किए तो वह एक्स सर्विसमैन के नाम से, हरिजन के नाम से या फिर हैण्डीकैप्ट परसन के नाम से ही जारी किए जबकि अभी तक किसानों के काफी कनैक्शंज बकाया हैं सरकार बताए कि वह कब तक बकाया कनैक्शंज भी जारी कर देगी ? एकीकृत विकास स्कीम के तहत चरखी दादरी एवं एक दो अन्य शहरों को दो करोड़ रुपये देने की बात कही गयी है लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर शहरों का विकास करना है तो विकास एक करोड़ या दो करोड़ देने से नहीं होगा। मेरा कहना है कि चरखी दादरी को ज़िला बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह सबसे पुराना एक बड़ा उप-मंडल है और कभी वह जींद रियासत के समय में ज़िला होता था और वहां सैशन जज की कचहरी भी लगती थी। अध्यक्ष महोदय, जब एक भूतपूर्व सी०एम० के लड़के को लोगों ने एम०एल०ए० बना दिया तो उन्होंने उस हल्के को ज़िला बना दिया इसी तरह से जो दूसरे मुख्य मंत्री हैं जब उनके लड़के ने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने भी कुछ ऐसे वायदे किये थे मेरा कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक आधार पर जिले बना दिये गये जबकि चरखी दादरी सबसे पुराना सब-डिवीज़न है इसलिए उसका तो ज़िला बनने का सबसे ज्यादा हक बनता है उसको ज़िला बनाया जाना चाहिए। एक करोड़ या दो करोड़ रुपये देने से शहरों का विकास नहीं होगा। अभिभाषण में रोज़गार की बात भी आयी कि नये कारखाने, नयी फैक्ट्री लगायी जाएंगी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दादरी में भारत सरकार का एक सीमेंट का कारखाना सी०सी०आई० है वह बन्द पड़ा है। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी उसके चलवाने के बारे में बात करती है इस बार

[श्री जगजीत सिंह सांगवान]

भी मुख्य मंत्री जी ने और उस जिले के पुराने मुख्य मंत्री ने कहा था कि उसको चालू करवाएंगे। लेकिन आज भी वह वैसे का वैसा पड़ा है वह बहुत बड़ी फैक्ट्री है बहुत ज्यादा उसमें प्रोपर्टी है और उसके चालू होने से बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि कब तक इस कारखाने को चालू करवाया जाएगा। अगर वह चालू हो गया तो इससे दादरी इलाके के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसको चालू करवाया जाए। इसी तरह से अभिभाषण में शिक्षा का जिक्र आया है इस बारे में बहुत दावे किए गए लेकिन दादरी के अंदर न तो कोई लड़कियों का या लड़कों का गवर्नमैंट कालेज है, न आई०टी०आई० है, न कोई पोलिटैक्नीक कालेज है और न ही वहां पर कोई इंजीनियरिंग कालेज है, यानी वहां पर कोई भी इस तरह की गवर्नमैंट की संस्था नहीं है जबकि वह सबसे पुराना उपमंडल है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वहां पर आई०टी०आई०, इंजीनियरिंग कालेज, पोलिटैक्निक कालेज या गवर्नमैंट कालेज कोई न कोई तो खोला ही जाना चाहिए। जबकि कहा यह जा रहा है कि सरकार सारी स्टेट में एक सी-ही नीति अपनाए हुए हैं। इसी तरह से सड़कों के बारे में मुख्य मंत्री जी ने बता ही दिया कि मई के अंत तक सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी इसलिए मैं इस बारे में जिक्र नहीं करूंगा। मैंने पिछली सरकार के बारे में कहना था कि शराबबंदी के नाम उसने सारे प्रदेश को बुरी तरह से लूटा है। सरकार में चंद कुछ लोग ऐसे थे जो बुरी तरह से सरकार को लूट रहे थे। उन्होंने दो हजार करोड़ रुपया लूटा होगा, या कितना लूटा होगा और उस पैसे से दिल्ली में पता नहीं कितनी कोठियां बनीं। (विघ्न) उन दिनों में यही देखा करता था कि कहां-कहां लूट हो रही है कहां-कहां कोठियां बन रही हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस सारे मामले की जांच कराई जाए। पिछली सरकार के वक्त में यह काम हुये हैं। जो लोग इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उनको पकड़ो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो। मेरा निवेदन है कि जांच अधिकारी इसमें ठीक बनाओ। यह मैं बता दूंगा कि यह प्रॉपर्टी कब बनी है।

श्री अध्यक्ष : आप टौपिक पर बोलें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : सर, इस सारे मामले में जो नुकसान सरकार को व प्रदेश को हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें की गई हैं कि 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। मेरे चरखी दादरी हल्के में गांवों के जोहड़ों में पशुओं के लिए पानी नहीं है, पीने के पानी की तो बात अलग है चरखी दादरी में 20 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के लिए पानी नहीं है जोहड़ों में जो पानी है वह भी काफी समय पहले का भरा हुआ है और सड़ रहा है। एक रामनगर विलेज है, भौंडल विलेज है, आप किसी एजेन्सी को वहां भेजो वह पता लगा ले कि वहां पर पानी की क्या स्थिति है। वहां पानी भरे हुये ही सालों हो गए होंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भिवानी में बस स्टैंड के लिए जगह एक्वायर की थी वह इस प्रकार से की थी कि एक टुकड़ा एक एकड़ का हो उसमें सौ गज छोड़ दिया ताकि मार्किट बन जाए, कमर्शियल साइट बना ली। इसमें भी बड़ी भारी धांधली हुई हैं। एक तरफ कमर्शियल साइट छोड़ दी और टेढ़ी-मेढ़ी जगह बस स्टैंड के लिए एक्वायर कर ली। सरकार को अपने फायदे के लिए चंद लोगों ने यूज किया है। इस मामले की भी जांच कराई जाए। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि 6 महीने के लिए मंदिर बना दिया। कुछ दिन मंदिर बना पड़ा रहा बाद में वहां दुकानें बना दी जाएंगी इस तरह की धांधली का पर्दाफाश किया जाए। अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि 11 हजार किलोवाट की बिजली की तारें गांव के ऊपर हैं और कई जगह यह तारें घरों के ऊपर से भी गुजर रही हैं और ढीली पड़ गई हैं उससे वहां के नागरिकों को जान माल का

काफी खतरा है गांव के लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि ऐस्टीमेट बनेगा और बहुत लम्बा चौड़ा खर्च इसमें इन्वौल्व है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की तारें सरकार अपने खर्च पर वहां से हटवाए और यह सर्वे करवाया जाए कि इतनी ज्यादा पॉवर की तारें वहां से कैसे गई हुई हैं ? अभी श्री भूपेन्द्र हुड्डा जी ने शुगर मिलों के क्षेत्र में सरकारीकरण की जो बात कही वह बिल्कुल ठीक है। आज तक कॉपरेटिव शुगर मिलों के चेयरमैन का चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐक्ट में प्रौविजन है कि चेयरमैन सरकार लगाएगी और यदि राज्यपाल का शासन होता है तो चेयरमैन आई०ए०एस० लगा दिया जाता है और जब सरकार होती है तो चेयरमैन अपने चहेतों को लगा देती है। नये प्लांट्स लगाने की बात आई है। चीनी मिल नयी लगा रहे हैं जबकि भिवानी के अंदर बहुत बढ़िया मिल्क प्लांट है जो बंद पड़ा है। सरकार उसको चालू करवाये। क्योंकि जो पहले प्लांट लगे हुये थे वे सिर्फ प्रशासनिक तौर पर अनदेखी करने की वजह से बन्द पड़े हैं उनको दोबारा चालू करने का प्रोग्राम बनाया जाये। यह काम राजनीति से ऊपर उठकर करवाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले भिवानी जिले के चरखी गांव में एक ए०एस०आई० ने गोली मार कर एक लड़के की हत्या कर दी थी उस समय काफी आन्दोलन हुआ तब भिवानी जिले के लोकसभा सदस्य श्री अजय सिंह चौटाला ने उस लड़के के आश्रितों को पांच लाख रुपये तथा एक सदस्य को नौकरी देने की बात की थी। नौकरी तो डेली-वेजिज के तौर पर एक सदस्य को दे दी गई है लेकिन पांच लाख रुपये की राशि अभी तक नहीं दी गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि उस परिवार को पांच लाख की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाये। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री रमेश राणा (घरौंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश के हर हल्के में खुला दरबार लगाया था। उस वक्त विपक्षी पार्टियों के नेता लोगों को यह कहा करते थे कि श्री ओम प्रकाश चौटाला खुले दरबार के द्वारा लोगों को झुठा आश्वासन दे रहा है और जो वायदे इस खुले दरबार में किये गये हैं वे कभी पूरे नहीं किये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खुले दरबार में जो भी जनता से वायदे किये थे उन वायदों के अनुसार एक हफ्ते के अन्दर ही काम शुरू हो गया था और आज वे सभी वायदे पूरे होने जा रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवी लाल जी के स्वपन को पूरा करते हुये बुढ़ापा पैंशन को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक कर दिया है इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के तीन साल के शासनकाल में सड़कों की मरम्मत पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया था। वर्तमान सरकार बनने के बाद किसी भी गांव की सड़क नहीं बची होगी जिस पर मरम्मत का काम पूरा नहीं किया गया हो या जिस पर काम नहीं चल रहा हो इसके लिए भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है। चुनाव के पहले पिछली सरकार में जो साथी शामिल थे या जो साथी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वे इस बात का ढिंढोरा पीटा करते थे कि हरियाणा के मुख्य मंत्री की कुर्सी से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हटाया जाए ताकि प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो सकें। अध्यक्ष महोदय, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष ढंग से करवाये। 90 विधान सभा क्षेत्रों में से एक भी विधान सभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे थे किसी सदस्य की शिकायत नहीं मिली कि हरियाणा में चुनावों में कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही है या धांधली हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला

[श्री रमेश राणा]

जी को इस बात पर बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ताऊ देवी लाल जी के स्वपन को पूरा करते हुये हमारी हरिजन बाल्मीकि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और बहनों को 500 रुपये देने का काम किया था। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने देवी लाल जी के स्वपन को पूरा करते हुये हमारी हरिजन बहनों की शादी में 5100 रुपये कन्यादन के रूप में देने का काम किया। पिछली बंसी लाल जी की सरकार में मैं दर्शक दीर्घा में बैठा था क्योंकि 1996 का चुनाव जब मैंने लड़ा था तो मुझे इन्हीं बंसी लाल के कुकर्मों की वजह से ही यहां बैठने की बजाय दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ा, मुझे जीते हुये भी हरा दिया गया। मैं यहां पर बैठकर देखा करता था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी विपक्ष में हुआ करते थे वे बार-बार कहा करते थे कि हमारे जो नौजवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए आपने 1 लाख 2 लाख रुपये की राशी रखी है उसको बढ़ाकर 10 लाख किया जाए लेकिन उनके आग्रह के बावजूद, उनके शोर शराबे के बावजूद बंसी लाल जी ने उस धन राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया था। मैं आज मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही वह धनराशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी। अभी हमारे माननीय कांग्रेस के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गन्ने का भाव हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हरियाणा के अन्दर नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय, को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि चाहे हिन्दुस्तान के अन्दर गन्ने का भाव सबसे ज्यादा है या नहीं लेकिन हरियाणा के किसान गन्ने का भाव बढ़ने पर उनका जगह-जगह स्वागत कर रहे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस सदन के अन्दर हरियाणा की नई राजधानी बनाने की बात उठी थी, आज से पहले जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने नई राजधानी बनाने का ढिंढोरा पीटा। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजधानी तो बनती रहेगी लेकिन आज सबसे पहली जरूरत रोजी रोटी की है उसको यह हरियाणा सरकार पूरा करे। नई राजधानी बनाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछली बंसी लाल जी की सरकार ने एक वायदा किया था कि मैं हरियाणा के अन्दर शराबबन्दी लागू करूंगा, शराबबंदी लागू हुई थी और उन्होंने इसके साथ-साथ एक और वायदा किया था कि जो शराब बेचेगा मैं उसको जेल के अन्दर बन्द करूंगा और उसको देखने के लिए टिकट लगाऊंगा जिससे हरियाणा की आमदनी बढ़े। बंसी लाल जी ने उन नौजवानों को जेल के अन्दर बन्द कर दिया जिन्होंने आधा या पव्वा शराब बेची थी या थोड़ी बहुत शराब पी ली थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बंसी लाल जी उस बात को तो पूरा करें कि 'मैं उस आदमी को जेल के अंदर बंद कर दूंगा जो हरियाणा में शराब बेचेगा-पीयेगा'। अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी तो अपना यह वायदा पूरा नहीं कर पाये लेकिन मैं चौटाला साहब से निवेदन करूंगा कि उनके इस वायदे को ये पूरा करें। जो हरियाणा का शराब माफिया था, जिसकी शराब हरियाणा में बिका करती थी उसको जेल में बंद किया जाये और उसके ऊपर टिकट लगा दी जाये। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के अन्दर इण्डस्ट्रीज लगनी चाहिएं लेकिन हरियाणा का जो मेन बेस है वह खेती-बाड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज या फैक्ट्रियां लगने से पहले हमारे यहां के किसानों की और मजदूरों की आर्थिक दशा ठीक की जाये। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आपने मुझे इस महान सदन के व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय बोलने के लिए दिया।

श्री रणबीर सिंह (बाढ़डा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्य मंत्री महोदय भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री महोदय का मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में शपथ समारोह रखा। अध्यक्ष महोदय, 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे "अन्याय पर सत्य की विजय" का। वहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शपथ लेकर एक नया इतिहास और आयाम कायम किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने 9 तारीख को सदन में जो अभिभाषण पढ़ा, जिसमें मौजूदा सरकार की उपलब्धियां हैं इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले 7 महीनों में जो उपलब्धियां पाई हैं उन्हें जितना गिनाया जाये उतनी ही वे कम हैं। जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री कहते थे कि उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है वह उन्होंने अपने पिछले 7 महीने के शासन काल में करके भी दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से चौटाला साहब ने किसानों को गन्ने का मूल्य 110 रुपये देकर एक सराहनीय काम किया है उसके लिए सरकार की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। इसके अतिरिक्त 10 रुपये यूरिया और 5 रुपये डीएपी पर कम कराये यह भी बहुत ही सराहनीय काम है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से चौटाला साहब ने बुजुर्गों की पैंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। वृद्धावस्था पैंशन की शुरुआत चौधरी देवी लाल जी ने ही की थी और चौटाला साहब ने इसे दुगना करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पिछली सरकार ने जिनकी पैंशन बंद कर दी थी उनको भी पैंशन दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विडो पैंशन और विकलांगों की पैंशन को भी 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये चौटाला साहब ने कर दिया है। इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने जिस तरह से पिछले 7 महीने में हरिजनों की चौपालों का निर्माण व स्कूलों और विद्यालयों का पुनर्निर्माण किया है। ये सरकार की बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं। पिछली सरकारा ने अपनी बेटी अपना धन की जो स्कीम चलाई थी उसको मौजूदा सरकार ने बरकरार रखा इसके लिए भी मौजूदा सरकार बधाई की पात्र है। हरिजन के घर बच्चा पैदा होने पर चौधरी देवी लाल जी ने 500 और 300 रुपये की जो रकम शुरू की थी उसे मौजूदा सरकार ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में आधी संख्या महिलाओं की है। इनके उत्थान के लिये जो महिला आयोग गठन किया गया है उससे महिलाओं का जीवन स्तर सुधारा जा सकेगा। इसके लिये भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, सीमाओं की रक्षा के लिये जो कारगिल युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध में जो नौजवान शहीद हो गये थे उन शहीदों के सम्मान के लिये पिछली सरकार ने बड़ा री-री करके 50,000 रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये उनके परिवारों को देने की बात कही थी और वह भी हमारे जैसे कई सदस्यों के बार-बार कहने पर बढ़ाये गये थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता संभालते ही एक कलम से इस पांच लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ-साथ जख्मी हुये शहीदों के लिये भी तीन लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर छः लाख रुपये कर दिया। इसके लिये भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, गलियों के विकास के सम्बन्ध में भी मैं सदन को बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी खुले दरबारों में विकास के लिये जो घोषणाएं किया करते थे उसे देख कर हमारे प्रति पक्ष के सदस्य कहा करते थे कि यह तो केवल घोषणा मुख्य मंत्री है और खाली घोषणाएं ही करते रहते हैं, कोई विकास नहीं कर सकते।

[श्री रणबीर सिंह]

यही मेरे साथी जब विधानसभा के चुनावों में वोट मांगने गये थे तो गांव-गांव में जिस प्रकार से गलियों के काम चल रहे थे या और विकास के काम चल रहे थे उनको देखकर उंगली दबा कर रह गये। इन साथियों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो-जो घोषणाएं की उन सभी विकास कार्यों को जोर-शोर से चलाया जा रहा था। इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकार ने व्यापारियों की चिरपरिचित मांग चुंगी को समाप्त किया, वह एक सराहनीय कार्य है। इसके अलावा चुंगी समाप्त करने पर नगरपालिकाओं के चुंगी कर्मचारियों को दूसरे महकमों में समयोजित करके सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावा मार्किट शुल्क 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। मंडियों में आढ़तियों के लिये जगह का प्रावधान भी सरकार ने किया है जोकि सराहनीय काम है। अध्यक्ष महोदय, किसान या कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिये लड़ते थे तो उनके ऊपर पिछली सरकारों ने मुकदमें बना दिये। सरकार ने इन मुकदमों को वापिस लेकर भी सराहनीय कार्य किया है। सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके साथ-साथ अग्रोहा मैडिकल कालेज की जो ग्रांट बन्द पड़ी थी उसे खोलकर और 7 करोड़ तक करके सरकार ने सराहनीय काम किया है। सरकार ने यह एक अनूठा कार्य करके प्रदेश में अच्छा संदेश दिया है। इसके साथ-साथ अध्यापकों के लिये राज्य पुरस्कार योजना को दुगुना करके सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। युवाओं के लिये भी कई अच्छे काम किये गये हैं जैसे कि पिछली सरकार ने जिस प्रकार से नशाबन्दी के दौरान युवाओं पर मुकदमें बनाये थे उन मुकदमों को सरकार ने वापिस लिया है। इसके लिये मैं सरकार का बड़ा कृतज्ञ हूं। इसी तरह से युवाओं के लिये नौकरियों में आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई है और पहले भी 30 वर्ष से 35 वर्ष की आयु सीमा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही की थी। यह युवाओं के लिये बड़ा अच्छा और शुभ संकेत है। मैं सरकार को इसलिये भी बधाई देना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल की पिछली सरकार ने नौकरियों पर जो प्रतिबन्ध लगा रखा था उसे भी इस सरकार ने हटा दिया है। अध्यक्ष महोदय, स्कूल और कालेजों में कहीं भी दाखिला लेने के लिये डोमीसाइल की जरूरत पड़ी है और डामीसाइल की अवधि 6 माह है जबकि दूसरे प्रदेशों में कहीं एक साल और कहीं 3 साल की है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में भी डोमीसाइल की अवधि छः माह से बढ़ाकर तीन साल कर दी जाए ताकि युवाओं को बार-बार डोमीसाइल बनवाने के लिये धक्के न खाने पड़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० नहर पर भी कई साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। एस०वाई०एल० नहर का मसला काफी सालों से लम्बित चला आ रहा है। समय-समय की सरकारें अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करती रही हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1977 में जितना काम चौधरी देवी लाल जी ने करवाया था, उतना काम आज तक किसी सरकार ने नहीं करवाया। 1991 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी इस पर काफी काम हुआ था। बाद में इस में काफी रूकावटें आई जिस कारण यह काम पूरा नहीं हो सका था। जब 1991 में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त इस नहर पर काम चल रहा था और पंजाब में आतंकवाद का बढ़ावा था। उस आतंकवाद के चलते इस नहर पर काम करने वाले 36 इन्जीनियर्ज भी आतंकवादियों ने मार दिये थे जिसके कारण उस वक्त काम रुक गया था। चौटाला साहब के वक्त में 95 फीसदी काम हो चुका था उस वक्त तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर से मिलकर हमारे मुख्यमंत्री चौटाला साहब ने इस नहर का काम करवाने के लिए बी०आर०ओ० को सौंप देने के लिए कहा लेकिन बाद में 1991 में हमारी सरकार चली गई जिस कारण काम बीच में रुक गया। इसके बाद इस तरफ किसी सरकार ने ध्यान

नहीं दिया। तब से लेकर आज तक यह मामला यूं का यूं लटका हुआ है। बाद की सरकारों ने भी इसे बी०आर०ओ० से करवाने की बजाये सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को उलझा दिया। तब से लेकर अब तक यह मामला लम्बित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला हल हो जाये ताकि इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। जो प्रयास हमारी सरकार इस काम के लिए कर रही है, उसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आर्थिक औद्योगिक विकास की तरफ भी काफी ध्यान दिया है। सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं वे वाकई ही बहुत सराहनीय और उल्लेखनीय हैं। किसी प्रदेश का विकास तभी संभव हो सकता है जब उस प्रदेश का आर्थिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का विकास हो सके। हमारी सरकार इस दिशा में गम्भीरता से इन दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है और इनके विकास के लिये हमारी सरकार अच्छी नीतियां बना कर काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने 7 महीने के कार्यक्रम में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। बिजली की आपूर्ति में भी हमारी सरकार का रवैया बहुत ही रचनात्मक रहा है। हम सब को बड़ी खुशी है कि गए साल बारिश न होने के कारण जो सूखा पड़ा था उसका मुकाबला करते हुये सरकार ने किसानों को लगातार बिजली की सप्लाई की जिस कारण किसान सूखे का मुकाबला करने में कामयाब रहे। बिजली की सप्लाई लगातार होने के कारण ही हमारी उबड़-खाबड़ जगहों पर अच्छी अच्छी फसलें नजर आ रही हैं। जो फसल हमें आज नजर आ रही है उतनी अच्छी फसल आज तक कभी भी हमारे प्रदेश की नहीं थी। यह सब सरकार द्वारा किसानों को लगातार बिजली की सप्लाई करने के कारण संभव हो सका था और इसीलिए हमें चारों तरफ आज हरी-भरी खेती नजर आ रही है। इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है और इसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्थानीय स्वशासन के तहत जो सुविधाएं लोगों को दी हैं, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के तहत जो दो चीनी मिलें लगाने का फैसला लिया है उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसी संबंध में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एरिया में सरसों की पैदावार अधिक होती है इसलिए वहां पर एक तेल मिल लगायी जाये ताकि किसानों को और अधिक फायदा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जनस्वास्थ्य की तरफ भी काफी ध्यान दिया है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन क्षेत्रों में पिछली सरकारों के दौरान पीने के पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था उन पर सरकार ज्यादा ध्यान दे ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पशुधन की तरफ भी काफी ध्यान दिया है ताकि हमारी यहां की जो दुधारू नस्ल की गाय और भैंसे अच्छी नस्ल की हैं उनको और सुधारा जा सके। सरकार ने इस स्कीम के तहत 373.5 लाख रुपये रखे हैं। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भी सरकार उचित कदम उठा रही है। आज के दिन प्राईवेट स्कूल अधिक खुल रहे हैं। इस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर कुछ रोक लगायी जानी चाहिए। हमारी शिक्षा का स्तर कुछ गिरा है लेकिन सरकार इस स्तर को ऊपर उठाने के लिए कदम उठा रही है।

[श्री रणबीर सिंह]

अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। चरखी दादरी हमारा नया डिपू है। वहां पर बसों का काफी अभाव है। सभी डिपूओं के जो आंकड़े आए हैं, उनमें चरखी दादरी के आंकड़े काफी सराहनीय रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन सरकार से करना चाहूंगा कि इसके लिए ज्यादा पैसा दिया जाए। अब नया डिपो बनने के बाद नई बसों की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं इसलिए हमारे डिपो के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध करवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यहां पर कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार की उपलब्धियां काफी सराहनीय रही हैं। इस अभिभाषण में अपराधों के जो आंकड़े बताए हैं वह पिछली सरकारों के मुकाबले कम हैं। यह ठीक है कि शराब माफिया के कारण अपराध ज्यादा हो रहे हैं लेकिन पिछली सरकारों की बजाए अब जो आंकड़े बता रहे हैं वे यह दर्शाते हैं कि इस बार अपराधों में कमी आई है। अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए कुछ समय लगेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के सरकार की उपलब्धियों को अभिभाषण में पढ़ा उसके लिये मैं माननीय राज्यपाल महोदय का अत्यन्त आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपनी सरकार के इतने थोड़े समय में जो उपलब्धियां गिनाई हैं वे बड़ी ही उल्लेखनीय हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री जी ने इतने थोड़े समय में इतने विकास के कार्य नहीं करवाए इसलिए इन विकास कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जितने विकास कार्य किये हैं किसी भी अन्य मुख्यमन्त्री ने इतने थोड़े समय में नहीं किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूँ तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

डॉ० जय प्रकाश शर्मा (यमुनानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से इस विधान सभा में चुन कर आए सभी साथियों को मुबारिकबाद देता हूँ। मैं यमुनानगर को रिप्रैजेंट करता हूँ वहां पर थर्मल प्लांट का प्लान बहुत देर पहले ही आयोजित किया गया था। थर्मल प्लांट के लिए चौधरी भजन लाल जी के टाईम में जमीन ऐक्वायर की गई थी और उस समय के ग्राईम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने इसका नींव पत्थर रखा था। अध्यक्ष जी, उसके बाद जो भी सरकारें आई उन्होंने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की और यह प्रोजैक्ट खुड्डे लाईन लगा हुआ है। हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है जिस पर काश्त हो सकती है। इससे बेहतर तो यह होता कि उस जमीन को ठेके पर दे देते जिस से सरकार को भी कुछ आमदनी होती और वहीं पर जमींदारों को भी कुछ राहत मिलती। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक बिजली का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक हरियाणा का विकास नहीं हो सकता है। थर्मल प्लांट बनने से बिजली के उत्पादन में वृद्धि होगी और नये-नये प्रोजैक्ट और नई-नई इण्डस्ट्रीज हरियाणा में आएंगी और इससे हरियाणा की इन्कम बढ़ेगी। पिछले 5-7 साल से हरियाणा में कोई भी इण्डस्ट्री आने के लिए तैयार नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की सबसे बड़ी मण्डी है और सबसे ज्यादा रैवेन्यू सरकार को यमुनानगर से आता है लेकिन यमुनानगर के डिवैल्पमैंट में सरकार का कोई योगदान नहीं है। वहां पर लड़कों या लड़कियों के लिए कोई भी गवर्नमैंट कॉलेज या मैडिकल कॉलेज नहीं है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सत्तिंग पार्टी की तरफ से कहा गया है कि शूगरकेन के रेट्स बढ़ा दिये गये हैं। शूगरमिल से शूगरकेन की जो पर्ची कटती है उस पर रेट नहीं लिखा हुआ होता है। नीचे टोटल तो लिखा होता है लेकिन रेट वाले कॉलम पर रेट नहीं लिखा होता वहां पर पर्ची खाली होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ महीने बाद यह चेंज हो जाएगा। यह रेट जब अनाउंस हुआ था तो दो महीने तक किसी भी फारमर को पेमैंट नहीं हुई, उन दो महीनों का इन्ट्रस्ट कहां

गया ? वह इन्टरेस्ट फार्मर को दिलाइये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, मेरे से पहले भी इस बारे में मेरे साथी काफी कुछ कह चुके हैं। मैं यह कहूंगा कि सर्वे होना चाहिए। इस समय इसमें बहुत गलतियां हैं। काफी जगहों पर हमने इस बारे में देखा है इलैक्शनों में हम जगह-जगह गए हैं। जो राशन कार्ड बने हुए हैं या यलो कार्ड बने हुए हैं सर्वे दोबारा से करवा कर दोबारा कार्ड बनाए जाएं। (विघ्न) इसमें कोई दो राय नहीं कि आप भी गरीबों की सेवा करना चाहते हैं और हम भी गरीबों की ही बात कर रहे हैं। हम लोग भी सेवा ही करना चाहते हैं और यह आप ही के माध्यम से होगा। गवर्नर साहब, के एड्रैस में लिखा है कि फिशरी मार्किट यमुनानगर में बनाई गई है लेकिन उसकी प्रौडक्शन के लिए जो लोग आगे आएंगे, क्या उनको कोई सबसिडी या लोन देने का विचार सरकार ने बनाया है या नहीं बनाया है ? यमुनानगर में लेबर बहुत है। सर, एक ई०एस०आई० स्कीम है, लेबर आफिसर है जिसे 1600 रुपये की सैलरी तक के केसिज सुनने का अधिकार है अब वह बढ़ गई है। इसलिए यह लिमिट भी बढ़नी चाहिये और अधिक वेजिज के केस सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, आप इसके बारे में कुछ करें। इसके साथ ही सर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि एक ई०एस०आई० स्कीम है। यह स्कीम बहुत अच्छी है और यह फारेन में भी है। अगर यह स्कीम सारे देश में लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अन्दर यह प्रावधान है कि अढ़ाई प्रतिशत तो मजदूर देते हैं और साढ़े चार प्रतिशत पैसे का योगदान मालिक की तरफ से दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यमुनानगर में जाकर देख लें कि न तो वहां पर कोई डाक्टर है और न ही कोई दवाई है जिसकी वजह से वहां पर इस स्कीम का मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे मिल लूंगा और इस विषय में बात कर लेंगे कि वहां पर क्या होना चाहिये। पहले दिल्ली से एक सर्वे टीम आई थी और वह सर्वे करके चली गई। उसने जो रिपोर्ट दी थी वह आज तक लागू नहीं की गई है। मैं हैल्थ बजट के बारे में कहूंगा कि कोई भी सरकार लोगों की हैल्थ के प्रति इंट्रस्टेड नहीं है। अगर मजदूरों की सेहत ठीक नहीं होगी तो वे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की सेहत की तरफ ध्यान दें। प्रो० सम्पत सिंह जी यहां पर बैठे हुये हैं ये बजट लाने वाले हैं तो मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये बजट में हैल्थ के बजट में पिछले बजट से ज्यादा बढ़ौतरी करें। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ब्लड बैंक हैं। कुछ साल पहले ब्लड बैंक में से 265 रुपये देकर ब्लड की बोतल मिल जाती थी लेकिन अब इसका रेट बढ़ाकर 500 रुपये प्रति बोतल कर दिया गया है। गरीब आदमी कहां से इतने पैसे लाएगा क्योंकि किसी को चार बोतलों की जरूरत होती है किसी को पांच बोतलों की जरूरत होती है आप इस बारे में कुछ करें। अध्यक्ष महोदय, अब चण्डीगढ़ से दिल्ली तक चलें तो वहां पर कोई भी ट्रौमा यूनिट नहीं है। अगर कोई एक्सीडैंट हो जाए तो कोई भी वहां पर उसके इलाज की सुविधा नहीं है। आप इस बारे में कुछ करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। रूरल स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है बच्चे लॉन में बैठते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं और वहीं पर गाय भैंसे घूमती रहती हैं। यमुनानगर में तो सूअर घूमते है। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए गवर्नमैंट कालेज नहीं है। अटेली गांव की पंचायत ने 65 एकड़ जमीन डोनेट की थी और यह भजन लाल जी के टाईम में हुआ था । मेरी बहन कमला वर्मा ने इसके लिये क्रेडिट लिया लेकिन उनको शायद यह नहीं पता कि उस समय स्पोर्टस मिनिस्टर राजेश शर्मा और चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी थे जब यह शुरू हुई थी। (विघ्न) मैं यह कह रहा हूं कि क्रेडिट लेने कि कोशिश की मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। (विघ्न) जब सरकारी अस्पताल अच्छे न हो लोगों को उनमें सुविधाएं नहीं मिलती हैं। (विघ्न)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल रंगा) अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। इन्टैसिव केयर यूनिट की बात की। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि इस बारे में करनाल का हमारा प्रोजैक्ट आ गया है तथा हमारी इस संबंध में मीटिंग हो चुकी है। इसी तरह से इन्होंने शिक्षा के बारे में भी बात की है मैं आपके द्वारा इनको बताना चाहूंगा कि यमुनानगर में सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थाएं हैं चाहे वह एम०बी०ए० हो, चाहे वह बी०डी०एस० हो, चाहे वह माइक्रोबायॉलजी हो या चाहे डैंटल कोर्सिज हों यानी यमुनानगर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। इन संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस सरकार के आने के बाद ही मिला है। पिछले 6 महीने में हम चार कोर्सिस के प्रमाण-पत्र दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं सम्मानित सदस्य की सूचना के लिए बता रहा हूँ।

डॉ० जय प्रकाश शर्मा : लेकिन मैंने तो वहां पर शिक्षा सुविधाएं देने के लिए नहीं कहा। वहां पर लड़कों या लड़कियों के लिए कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है। जिन कोर्सिज़ की बात आप कर रहे हैं उनके बारे में भी मुझे पता है वह सब प्राईवेट संस्थाएं हैं। यमुनानगर में सरकार की तरफ से डिवैल्पमैंट मिनिमम ही है। अध्यक्ष महोदय, इलैक्शन के पहले सड़कों पर रोड़ी पड़ी, पत्थर पड़े लेकिन मैं अब सरकार से अनुरोध करूंगा क्योंकि अब चौटाला साहब भी आ गए हैं कि इलैक्शन खत्म हो गये हैं अब इन रोड़ी पत्थर को वहां से सड़कों से हटवा न लेना बल्कि सड़कें पूरी तरह से ठीक करवा देना। (विघ्न) यहां पर लॉ एंड आर्डर की बात भी कही गयी। मैं लॉ एंड आर्डर को अपने जिले के लिए क्रिटीसाइज नहीं करूंगा लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां पर यू०पी० का बोर्डर नजदीक है वहां से लोग आते हैं और चोरी वगैरह करके खिसक जाते हैं। खासकर प्रोहिबिशन के दौरान उनमें यह आदत पड़ गयी थी कि वे शराब की स्मगलिंग करते थे उनमें अब भी यह आदत पड़ी हुई है। इसलिए इस बारे में सरकार ध्यान दे ताकि लॉ एंड आर्डर की स्थिति पर कंट्रोल हो सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी पूछना चाहूंगा कि इन्होंने नवम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक कितने ओल्ड परसंज एवं विडोज को पैंशन डिस्ट्रीब्यूट की है और कितनी नेशनल हाई-वे और एक्सप्रेस हाई-वे बनाई हैं। लेकिन होता यह है कि एक सरकार स्कीम बनाती है तो दूसरी सरकार उसको सबसे पहले खत्म करती है। जबकि यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। अभी तो इस सरकार ने काम शुरू करना है। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि जितने भी काम आप करेंगे जनता उतना आपको ऐप्रीसिएट करेगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम तो क्रीटीसाइज करेंगे ही, जनता भी क्रीटीसाइज करेगी। एक प्रोजैक्ट तो अम्बाला से यमुनानगर नेशनल हाइ-वे सैंक्शन हुआ था इसके फंड्ज लैप्स हुये। इस बारे में आप जिम्मेदारी फिक्स करें और इसको दोबारा से रिवाइज करवाएं। दूसरी एक्सप्रेस हाइवे का था इसका भी पता नहीं क्या हुआ है इसकी तरफ भी आप ध्यान दें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ? इसके अलावा गवर्नर साहब के अभिभाषण में पौल्यूशन के बारे में मैंशन नहीं किया गया। यह देश की एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आज के युग में जीना मुश्किल है। मैं यह बात लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात अच्छी तरह से सुनी, रूलिंग पार्टी ने सुनी। बीच में नोंकझोंक भी की है इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

श्री भागे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अभी अभी हमारे पास कल के बिजनेस के बारे में पेपर आया है। कल आदरणीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे। आपने यह भी फरमाया था कि हमारी जो पिछली प्रथा है उस पर हम हाउस को चलाएंगे। आज यह लिस्ट ऑफ बिजनेस से पता चला है कि कल आप बजट पेश करेंगे उसके तुरन्त बाद सैकिण्ड सिटिंग में बजट पर चर्चा चालू की जाएगी। बजट को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए उसके बाद उस पर बहस होनी चाहिए। यदि आप पुरानी प्रथा पर हाउस को चलाना चाहते हैं तो अगले दिन हाउस में बजट पर चर्चा चलाएं।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी वित्त मंत्री रह चुके हैंऔर सीनियर मेम्बर हैं उनको बताना चाहूंगा कि हाउस के समक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई और लीडर ऑफ दि अपोजीशन भी बी०ए०सी० की मीटिंग में शामिल थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को हाउस ने एज इट इज असैप्ट कर लिया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्वायंट ऑफ आर्डर है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात नहीं आई थी कि उसी दिन सिटिंग हो जाएगी। कल आप बजट पेश करेंगे। एक बजे बजट खत्म होगा उसके बाद दो बजे दूसरी सिटिंग में चर्चा होगी तो बजट को पढ़ने का मौका हमें कल मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने क्लीयर किया था कि 11 बजे से 2 बजे तक का समय आप लोगों को बजट की स्टडी के लिए मिलेगा।

श्री भजन लाल : मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और लीडर ऑफ दि हाउस भी बैठे हैं। यदि बजट पर अगले दिन डिस्कशन हो जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय,बी०ए०सी की मीटिंग में लीडर ऑफ दि अपोजीशन भी शामिल थे उसके बाद वह रिपोर्ट आपने हाउस में रखी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में एज इट इज असैप्ट कर लिया तो आज यह बात कहां से आ गई। उस समय सारा हाउस यहीं था 89 के 89 मैम्बर यहां थे You were a part and parcel of that. That was not called as final. सूनानीमसली वह रिपोर्ट पास हुई, किसी ने सिंगल सैंटेंस भी उसके बारे में कहा हो तो आप रिकार्ड देख सकते हैं। It is only an after thought.

श्री भजन लाल : यह मैं मानता हूं कि हाउस में इस बात पर चर्चा नहीं हुई। किसी ने ऐतराज भी नहीं किया फिर भी आप सोच लें कि आपका बजट कल पेश हो और उस पर बहस परसों शुरू हो जाए। हमारे मैम्बर भी उसको देख लेंगे और यह अच्छी प्रथा रहेगी, गलत नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : कमेटी ने फैसला कर लिया और हाउस ने उसको रैक्टिफाई कर दिया। बजट सुबह 9.30 बजे से 11 बजे तक आएगा और उस पर बहस दो बजे शुरू होगी इतने में आप लोग तैयारी कर लेना।

13.00 बजे **श्री कंवर पाल** (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया। उसके बाद अपने सभी सहयोगी साथियों को बधाई देता हूं जो विधान सभा का चुनाव जीतकर इस सदन में आये हैं। छछरौली जो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की बैल्ट है वहां से चुनाव जीतकर आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गन्ने के भाव बढाये हैं इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले हरियाणा के किसान यह लड़ाई लड़ा करते थे कि हमें पंजाब के किसानों को जो गन्ने के भाव मिल रहे हैं वे भाव दिये जायें। लेकिन पंजाब के किसान यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें हरियाणा में जो गन्ने का भाव मिल रहा है वह भाव दिया जाये। अभी माननीय भाथी डाक्टर साहब कह रहे थे कि जो मिल में गन्ने की पर्ची काटी जाती है उस पर भी भाव लिखा जाये। इसमें पर्ची पर भाव लिखने की कौन सी जरूरत आन पड़ी जब पूरे गन्ने के भाव के हिसाब से पेमेंट ही कर दी जाती है। यह एक रिकार्ड की बात है कि इतनी जल्दी गन्ने की पेमेंट 15-16 साल में अब तक कभी नहीं हुई। कभी दो-दो महीने पेमेंट रोक दी जाती थी। पहली बार गन्ने के इतने अच्छे भाव दिये गये हैं। दूसरी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किये गये "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूंगा। यह

[श्री कंवर पाल]

कार्यक्रम हरियाणा में एक क्रान्तिकारी बनकर आया है। आज तक इतने जल्दी काम कभी नहीं हुये जितने जल्दी काम इस कार्यक्रम के तहत हो पाये हैं। आज तक यह प्रथा रही है कि घोषणाएं होती थी लेकिन काम नहीं होते थे। जब चौटाला साहब छछरौली में "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में गये तो लोगों ने यही बात कही थी कि झूठी घोषणाएं करने आये हैं काम तो कुछ नहीं होगा। परन्तु चौटाला साहब ने प्रत्येक गांव को 3-4 लाख रुपये दिये और जो झूठी घोषणाएं कहते थे उनको पता चल गया। अब वे पछता रहे हैं कि अगर हम भी उस कार्यक्रम में चले जाते तो हमें भी कुछ पैसा मिल जाता। "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में इतने बढ़िया काम हुये हैं जोकि स्वागत योग्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने प्रदेश में शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाये। चुनाव से पहले कुछ विपक्ष की पार्टियों के साथी कहते थे कि वर्तमान सरकार के रहते राज्य में चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। परन्तु चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से करवाये गये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। छछरौली हल्के पर भगवान की अथाह कृपा रही है परन्तु पिछली सरकार ने अपनी तरफ से उस हल्के की उपेक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे हल्के से सिर्फ दो बार दूसरी पार्टी के सदस्य निर्वाचित हुये हैं। एक तो मैं और दूसरे श्री रोशनलाल आर्य, नहीं तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही जीतकर आया है। श्री रोशनलाल आर्य चुनाव तो जीतकर आये थे विरोधी पक्ष की तरफ से लेकिन बाद में चौधरी भजनलाल जी के साथ मिल गये थे। जिन लोगों की सरकार आज तक रही हैं उन्होंने कभी मेरे हल्के के विकास का काम नहीं किया। पिछली सरकार में छछरौली के सिविल हौस्पिटल को प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बना दिया गया। आज उस गांव के लोग आंखें खोलकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब अपनी सरकार आई है और वह हमारे गांव में विकास का कार्य करेगी और उस प्राइमरी हैल्थ सैन्टर को दोबारा से सिविल होस्पिटल बनाएगी। छछरौली गांव में कोई कालेज नहीं है जबकि यमुनानगर में 5 हल्के पड़ते हैं और 5 हल्कों में से 4 हल्कों में कालेज हैं। छछरौली इतना बड़ा ब्लाक होने के बावजूद भी वहां पर कोई कालेज नहीं है। जैसा कि यमुनानगर में कालेज बनाने का सरकार का विचार है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यमुनानगर में कालेज बनाने की बजाय छछरौली में एक कालेज बनाया जाए। हमारे गांव में सड़कों की हालत बहुत खराब है। जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन कर आये हैं तब से वहां पर पैच वर्क हुये हैं। बूढ़ीया चौक से खदरी, देवधर खिजराबाद रोड की हालत बहुत ही खराब है तथा वह जगह-जगह से टूटी हुई है। पूर्व सरकार में बंसीलाल जी का वहां पर कोई कार्यक्रम था, उस समय उनको सलाह दी गई कि आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ कर न जाएं बल्कि अगली सीट पर बैठकर जाएं और वह सड़क ऐसी है कि उससे सरकार को 2 करोड़ रुपये की रॉयलटी मिलती है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस सड़क को डबल करवाने और बढ़िया करवाने का काम करें तो उस सड़क से सरकार को 4 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है और लोगों का भी भला हो जाएगा। शेरपुर से कोट रोड, खिजराबाद से बकरवाला रोड, सादेपुर रोड ये ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब हैं। सरकार को इन सड़कों के काम को प्राथमिकता देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पहाड़ी एरिया ज्यादा है जहां से नदी नाले निकलते हैं और जहां जगह-जगह पर पुलों की जरूरत है लेकिन आज तक इस ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बूढ़ो पिपली गांव हरियाणा में पड़ता है लेकिन इस गांव में कोई पुल न होने की वजह से यहां से हरियाणा में घुसने के लिए 30 किलोमीटर यू०पी० से घूमकर आना पड़ता है। इस बात से मुख्य मंत्री महोदय, भी परिचित हैं। वहां से कलानौर 5 किलोमीटर है लेकिन कोई पुल न होने की वजह से वहां से कलानौर 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए इस गांव में कोई छोटा सा पुल बनाया जाए। आज

तक जो सरकारें रही हैं, जो भी अफसर वहां गए हैं उन्होंने बड़े-बड़े पुल बनाने के ही अनुमान बनाए हैं, सरकार के पास इसके लिए पैसा भी होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर इस गांव में कोई पुल बना दिया जाए जिससे लोग इधर से उधर जा सकें तो आपकी मेहरबानी होगी। ऐसे ही टापू में मण्डोली, लाकड़, नवजपुर ऐसे गांव है जो अण्डमान निकोबार की तरह लगते हैं। ये सारे गांव बिल्कुल अलग पड़े हुये हैं अगर कोई व्यक्ति यमुनानगर से चण्डीगढ़ को चले तो कुछ ही देर में आ सकता है लेकिन अगर बुडो पीपली से यमुनानगर जाना हो तो ज्यादा समय लगता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे हल्के की समस्या को दूर करें। मेरे हल्के के विधायक सरकार में रहे हैं लेकिन सरकार में रहने के बावजूद भी इस गांव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ-साथ दूसरे साथियों ने जिन बातों का जिक्र किया उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय, का धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री शेर सिंह (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं इस वातावरण में पहली बार आया हूं। मैं अपने जुलाना हल्के का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन और उत्साह के साथ यहां भेजा है। यहां पर सैनिकों के विषय में बात की गई कि सैनिकों को सम्मान मिला है इसमें कोई शक नहीं है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा चेयर पर पदासीन हुये)** हरियाणा प्रदेश में सैनिकों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या सैनिक को उसी समय सम्मान मिलता है जब देश पर मुसीबत पड़ती है। सभापति महोदय, अब भारत वर्ष, का वातावरण इस तरह से बदलता जा रहा है कि इस देश को हमेशा ही सैनिक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने देखा है, सुना है या महसूस किया है कि सैनिक को सिर्फ उसी वक्त याद किया जाता है जब वह शहीद होता है और बाद में भूल जाते हैं। उस शहीद का परिवार दर-दर की ठोकरें खाता रहता है। उसके बच्चे अपना हक लेने के लिए पैसे देते हैं तब जाकर उनको उनका हक मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने उसे हक दिया है उसे हासिल करने के लिए पैसे देने क्यों पड़ते हैं ? सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के सिस्टम को सुधारा जाये और सभी को अपना हक आसानी से मिलना चाहिए। सभापति महोदय, जब सैनिक लड़ाई के लिए मैदान में जाता है तो उसे तरह-तरह के लाभ दिखाए जाते हैं लेकिन बाद में कुछ भी नहीं मिलता। बाद में लोग कहते हैं कि फौजी बेवकूफ होते हैं, पागल होते हैं। सभापति महोदय, यह कहना गलत है, हम लोगों को जनता में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और सरकार की प्रणाली को भी सुधारना पड़ेगा। सभापति महोदय, सैनिक को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए ताकि आने वाले नये सैनिकों को प्रेरणा मिले। सभापति महोदय, सैनिकों की सहायता के लिए एक सैनिक बोर्ड बना हुआ है, यह एक वैलफेयर एजैंसी है। उसमें जो भी नौकरी होती है वह फौजी के लिए ही होती है। उसमें भी बहुत ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इस बारे में मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन पदों को जल्दी से भरा जाये, ताकि सैनिकों को और भी सम्मान मिले। इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, एक बात और देखने में आई है कि हरियाणा प्रदेश में कोटा बिजनैस बनाया गया है। सैनिकों का भी अलग से कोटा है यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सैनिकों के कोटे में भी सब-कोटा बनाया गया है। डिफैंस में ही जब कोई कोटा नहीं है तो यहां पर भी सैनिकों के कोटे में सब-कोटा नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, जहां पर ऐसा होता है कि जिस जाति का सैनिक नहीं है वह पद जनरल कैटेगरी को दे दिया जाता है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर जिस जाति का पद है उस जाति का सैनिक नहीं है तो भी वह पद सैनिक को ही दिया जाना चाहिए और यदि यह सब-कोटे का

[श्री शेर सिंह]

सिस्टम ही खत्म कर दिया जाये तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि डिफैंस में इस तरह का कोई कोटा नहीं होता। जो दूसरी जाति के कोटे हैं वे तो ठीक हैं लेकिन सैनिक में जो सब-कोटा रखा गया है वह खत्म कर दिया जाये। सभापति महोदय, जो हमारी पुलिस फोर्स है वह भी सेना की तरह ही कार्य करती है। पुलिस वालों को भी गोली का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहां पर वातावरण ही कुछ इस तरह का बना हुआ है। उनके सीने पर भी गोली लगती है उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह के माहौल में चाहे वह किसी भी पुलिस फोर्स का सिपाही है, वह शहीद होता है तो उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जैसा भारत सरकार के सैनिकों को मिलता है। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा की बात पर आता हूं। शिक्षा के बारे में हमारी सरकारें बहुत कम पैसा अपने बजट में रखती हैं। अभी बजट नहीं आया है लेकिन कल आ जायेगा। मेरे से पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने भी शिक्षा पर काफी चर्चा की है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी शिक्षा के स्तर के बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया। अब इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और इसके स्तर को सुधारना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं जिस हल्के से आया हूं वहां पर एक भी कालेज नहीं है। सभापति महोदय, रोहतक और जींद के बीच जुलाना मेरा हल्का है। वहां पर न तो गवर्नमैंट कालेज है और न ही प्राईवेट कालेज है। हमारे वहां पर छात्राएं कालेज में पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से रोहतक या जींद जाती हैं। (विघ्न) सभापति महोदय, मैं तो अपने हल्के की समास्याएं बता रहा हूं कि वहां पर छात्राएं किस परेशानी का सामना कर रही हैं। इसलिये सरकार जुलाना हल्के में कालेज खोलने के मुद्दे पर जरूर विचार करे और शीघ्र अति शीघ्र वहां पर एक कालेज खोला जाए। इसके लिये हम सरकार के आभारी होंगे और वहां के लोगों का भी कल्याण होगा। अध्यक्ष महोदय, अब रोजगार की बात आती है। सरकार ने नौकरियों में आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी है लेकिन यह कहीं नहीं दर्शाया कि किस तरीके से और कितने रोजगार के साधन जुटाये जाएंगे। जिन युवकों की उम्र 35 साल हो चुकी है उनको नौकरियों में पात्रता देने की बजाय उनके लिये आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रावधान करना चाहिए था ताकि वे नौकरियों के लिए और इन्तजार न करके अपना कोई काम करें और जो युवा पीढ़ी बी०ए० या एम०ए० पढ़कर बाहर आ रही है उनके हिस्से के नौकरियों में भी कमी न आये। आज कालेज छोड़ते ही युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत होती है। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी शिक्षा के स्तर की बात आती है। आज किस तरह से कम्पीटीशन एग्जाम होते हैं। सरकार को यह सोचना चाहिये कि युवाओं को किस तरह से कम्पीटीशन एग्जाम में बैठने के काबिल बनाया जाए। इसके लिये सरकार की पंजाब की तरह हरियाणा में भी कई कोचिंग सैन्टर खोलने चाहिएं। इन कोचिंग सैन्टरों को सरकार की ओर से ही ग्रांट मिलनी चाहिए तथा सरकार के संरक्षण में ही इनको चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि युवकों में जागृति पैदा हो और उनकी नौलिज बढ़ सके। यदि सरकार द्वारा ऐसे प्रबन्ध किये जाएं तो हमारी युवा पीढ़ी अपनी नौलिज बढ़ाकर कम्पीटीशन एग्जाम में बैठ सकती है।

श्री मुनि लाल रंगा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भारत सरकार द्वारा कोचिंग सैन्टर खोल दिया गया है जिसके लिये 10 लाख रुपये की ग्रांट भी दी गई है। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी में हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से 6 लाख रुपये की ग्रांट प्राप्त करके रैमिडियल कोर्सेज भी शुरू किये हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी लाभान्वित होगी तथा रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।

श्री शेर सिंह : सभापति महोदय, इस बात से तो हम वाकिफ हैं लेकिन हरियाणा प्रदेश बहुत लम्बा-चौड़ा है और कम से कम दो तीन जगह तो कोचिंग सैन्टर जरूर खोले जाएं। सरकार के लिये ऐसा

करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं अब अध्यापकों के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि अगर अध्यापक अच्छे न हो तो शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जो 6000 अध्यापक एडहोक पर लगे हुए हैं और 3200 रुपये पर-मन्थ कन्टैक्ट पर लगे हुए हैं तो सरकार इनको पक्का क्यों नहीं करती ? क्या वे निकम्मे हैं ? जहां तक मेरा ख्याल है सरकार द्वारा इनका चयन निर्धारित योग्यता के आधार पर ही किया गया था और ये पक्का होने की सभी कंडीशनज़ फुलफिल करते हैं। कब तक इनको लटकाया जाएगा और कन्टैक्ट वाले 3500 रुपये में क्या ठीक पढ़ायेंगे इसलिये इनको पक्का करने का कोई न कोई प्रावधान होना चाहिये। अगर किसी में कैपेबलिटी नहीं है तो उसे निकाला जाए। अगर जल्दी ही इनको पक्का करने का कोई प्रावधान नहीं किया जाता तो शिक्षा के स्तर पर विपरीत असर पड़ेगा। सभापति महोदय, अब मैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। पिछली सरकारों ने इस तरफ काफी ध्यान दिया है लेकिन फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उससे हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। आज के दिन हम बीसवीं सदी में हैं लेकिन इस दिशा में हम बहुत पीछे हैं। मेरे हल्के जुलाना में एक प्राईमरी हैल्थ सैंटर है। वहां पर नार्म्ज के हिसाब से जितने डाक्टर्ज होने चाहिएं उतने आज तक नहीं हुए। मेरे ख्याल में वहां पर आज तक कोई लेडी डाक्टर तो गई ही नहीं। जींद डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारा जुलाना हल्का भी उसी पिछड़े इलाके के अन्दर आता है। हमारे वहां पर बड़े-बड़े नेता जाकर वायदे तो कर आते हैं लेकिन उनको इम्लीमैंट आज तक किसी ने नहीं किया है। जुलाना तो अच्छी जगह पर स्थापित है। वहां से डाक्टर अपनी ड्यूटी देकर रोहतक भी जा सकते हैं और जींद भी जा सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि नार्म्ज के हिसाब से जो संख्या डाक्टर्ज की वहां पर होनी चाहिए वह पूरी की जाये ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े।

सभापति महोदय, अब मैं जन स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे हल्के के बहुत से गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जुलाना रेलवे लाईन से दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनको पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। वहां पर लोग अपने ट्यूबवैल्ज या नल्के तो लगा सकते हैं लेकिन पानी खराब होने के कारण लगा नहीं पाते। मेरे हल्के में एक ब्राह्मणवास गांव है। उसमें पीने के पानी की बहुत समस्या है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवाये।

सभापति महोदय, अब मैं रोडज़ के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यह बात ठीक है कि रोडज़ पर पैच वर्क हुआ है लेकिन अभी भी रोडज़ को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कई रोडज़ ऐसी हैं जो बहुत दिनों से बन रही हैं लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन रोडज़ को शीघ्र पूरा किया जाये। ये रोडज़ हैं इगराना से बुआना, रामकली से करसोला, खान्ती से बुआना और बुरथार से बुआना। सरकार ने वायदा किया है कि जून तक सभी सड़कों की मुरम्मत का काम पूरा कर दिया जायेगा। यदि सरकार जून तक मेजर वर्क करवा देती है तो अच्छी बात होगी। जुलाना से लजबाना जो सड़क है उसकी बहुत ही खस्ता हालत है। मेरा सरकार से अनुरोध है इस सड़क को भी तुरन्त ठीक करवाया जाये ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न आये। यदि रोडज़ ठीक होंगे तो किसान अपनी फसल आसानी से मंडी ले जा सकता है और मजदूर अपने काम पर समय पर पहुंच सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि जितनी भी मेरे हल्के की रोडज़ खराब हैं उनको सरकार तुरन्त ठीक करवाने की कृपा करे।

[श्री शेर सिंह]

सभापति महोदय, अब मैं सहकारिता के बारे में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात में आनन्द डेरी काम कर रही है, उसी तरह से हमारे यहां पर भी सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। मेरा तो इस बारे में यह कहना है कि हमने बहुत सारी चीजें सहकारी क्षेत्र में एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस काम में सरकारी नियंत्रण जितना कम से कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। सिंचाई प्रणाली के बारे में मैंने पहले जिक्र किया था कि जुलाना हल्के में नहर जाती है लेकिन अभी भी सिंचाई के लिहाज से यह बहुत ही पिछड़ा हुआ है तथा वहां पर पानी पूरा नहीं मिलता है। कैनाल के बारे में कुछ निर्णय लिया गया है लेकिन वह निर्णय अभी तक जमीन पर नहीं हुआ है केवल कागजों में ही निर्णय लिया गया है। रामकली से शादीपुर में 4-5 माईनरज़ ऐसी हैं जिनका काम तो शुरू हुआ लेकिन शुरू होने के बाद आगे नहीं बढ़ा (विघ्न) इस अभिभाषण में आर्थिक औद्योगीकरण और उसके विकास के विषय में जिक्र किया गया है लेकिन इस बारे में मैं अपने हल्के की बात बताता हूं। किला ज़फगढ़ के पास एक फैक्टरी बन्द पड़ी है। यह फैक्टरी प्राईवेट है और इसके बन्द होने में सरकार का कोई कसूर नहीं है। क्या उस जमीन को हासिल करके क्या उसका औद्योगिकरण करने जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस विषय में सोचे। जुलाना हल्के में कोई भी इण्डस्ट्रीज़ नहीं है। मैंने सुना है कि एक सब-सैंटर खोलना था लेकिन वह सब-सैंटर भी वहां से शिफ्ट हो गया है। यह कैसे शिफ्ट किया गया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। जुलाना हल्के में कोई न कोई ऐसा स्टैप जरूर उठाना चाहिए जिससे वहां के लोगों को भी कुछ सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जाकिर हुसैन (तावडू) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह अभिभाषण इस सदन में दिया तो हमें बड़ी उम्मीद थी और अब भी उनसे यह उम्मीद है कि मेवात को अलग नया जिला बनाने की घोषणा होगी और उसका हैडक्वार्टर नूंह होगा। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी को भी मेवात से बहुत प्यार था और जब कभी भी वे मेवात एरिया में गए चाहे वह इलैक्शन से पहले गये या चुनाव के बाद गए तभी मेवात में यह बात आई और लोगों को उम्मीद थी कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मेवात जिला घोषित किया जाएगा। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जितने भी छोटे-छोटे प्रदेश बने हैं उनसे उन प्रदेशों की बहुत तरक्की हुई है। चाहें आप हरियाणा को ही ले लें चाहे और प्रदेशों को ले लें। इसी प्रकार से जब छोटे-छोटे जिले बनते हैं तो वहां पर पूरा पैसा लगने की बात होती है लेकिन आज भी जो पैसा गुड़गांव के नाम से जाता है और उसमें से जो पैसा हमारे मेवात एरिया में लगना चाहिए उतना नहीं लगता है! इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि मेवात को जिला बनाया जाए और उसका हैडक्वार्टर नूंह में हो। दूसरे सर, मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का जिक्र इसमें रह गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बना है तब से वहां पर कुछ तरक्की के काम किये गए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि कल जब वे अपना बजट पेश करें तो मेवात का ध्यान रखते हुए मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के लिए ज्यादा धनराशि का प्रावधान करने की कृपा करें। इस बोर्ड के चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं इसलिए मैं इनसे भी यह निवेदन करूंगा कि एक महीने में कम से कम बोर्ड की एक मीटिंग जरूर करें। वह मीटिंग चाहे चण्डीगढ़ में हो

या गुड़गांव में हो लेकिन मीटिंग जरूर हो। मैंने खुद इस बात को देखा है कि जो पैसा यहां से भेजा जाता है वह पूरा इस्तेमाल नहीं होता इसलिए मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को देखें कि जो पैसा यहां से भेजा जाए वह पैसा ठीक ढंग से लग सके और लोगों के काम आए। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में बिजली के बारे में कहा गया है। इस बारे में मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो भी हमारा शेयर बिजली का बनता है वह मेवात को पूरा मिले। बिजली के कनैक्शन्ज और ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन्ज जो बहुत समय से नहीं दिये गये हैं वे जल्दी से जल्दी दिये जाएं। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में सिंचाई के बारे में विशेषतौर पर जिक्र किया गया है तो इस में सबसे पहले बाढ़ की बात आती है। सन् 1978 से चौधरी देवी लाल जी ने उझीना ड्रेन बनाई है उसके बाद से मेवात एरिया में बाढ़ नहीं आती है या आती है तो न के बराबर है लेकिन आज भी कुछ गांव मेरे हल्के तावडू में इस उझीना के आस-पास बीबीपुर मोड़, मण्डरा और हसनपुर के आस-पास के इलाकों में पानी खड़ा रहता है और किसानों को अपनी पूरी फसल नहीं मिलती। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बाढ़ का पानी निकलवाने के लिए कोई स्कीम बनाई जाए। पहले कई सरकारे रहीं हैं। चौधरी देवी लाल जी के वक्त में चाहे कोई विपदा आई थी उसका वहां के लोगों को मुआवजा मिला है। उसके बाद 1996 में सरकार आई उस वक्त मेवात की बदकिस्मती रही कि मेवात में बड़ा भारी फ्लड आया और मुख्यमंत्री जी वहां पर गए लेकिन वहां के लोगों को फूटी-कोड़ी भी नहीं मिली। सभापति जी मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप वैसा कुछ न करें जिससे वहां के लोगों को नुक्सान हो।

अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा कि ज्यादातर विपक्ष में एम०एल०एज० दक्षिणी हरियाणा के हैं। गवर्नर साहब के एड्रैस में कहा गया है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि एस०वाई०एल को पूरा करने के बारे में कोशिश की जाएगी। हमारे यहां पर जो भी पानी मिलता है चाहे एस०वाई०एल० का मुद्दा सुलझाने की बात हो, हथनी कुंड बैराज पूरा होने की बात हो और औटू की बात हो। दक्षिणी हरियाणा को इसमें से कुछ हिस्सा बढ़ाकर देना चाहिए। मेरा आपसे यह निवेदन है। जब ज्वायंट पंजाब था तब से हरियाणा को उसके हक देने की बात कही जा रही है। जब हरियाणा बना तब से हमारे इलाके से पक्षपात की बात रही है। वायदे बहुत से किए गए मगर पूरे नहीं किए गए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा यह बहुत ही पुरानी बात है। प्रताप सिंह कैरो गोहाना गए थे उस वक्त मेरे दादा यासीन खां एम०एल०ए० थे। प्रताप सिंह जी ने वहां पर बहुत कुछ कहा कि हम यह करेंगे और वह करेंगे तो मेरे दादा ने बीच में माईक लेकर लोगों से कहा कि भाई बाद में मेरे कपड़े मत फाड़ना क्योंकि ये गरजेंगे तो यहां, पर बरसेंगे राजपुरा से आगे जाकर। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा कि वे कृपा करके हमारे एरिए मेवात में जरूर बरसें। मेवात में सड़कों की मरम्मत हुई है लेकिन अभी भी वहां पर और मरम्मत की जरूरत है। जो सड़कें इन्कम्पलीट हैं जहां पर मरम्मत की जरूरत है उनको पूरा किया जाए। जहां तक एम०एल०ए० ग्रांट की बात है तो पिछली सरकार ने यह ग्रांट खत्म कर दी थी। मेरा यह निवेदन है कि यह ग्रांट दोबारा से शुरू कि जाए। अब बात नगरपालिकाओं की आती है तो इनकी बहुत जरूरत है। तावडू कस्बे में बस स्टैण्ड की और सीवरेज की बहुत जरूरत है। इसके लिए भी आप कुछ करें। इसके साथ ही आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम कुमार कटवाल (राजौंद) : चेयरमैन महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। गवर्नर साहब ने जो यहां पर आकर अपना अभिभाषण पढ़ा इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, मेरे से पहले गुलाना हल्के के एम०एल०ए० जो भूतपूर्व डी०आई०जी० रह चुके हैं, बोल रहे थे। उन्होंने इलैक्शन के समय 9 हज़ार लड़कों को रोज़गार देने का वायदा किया है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वे 9 हज़ार लड़कों को लगाने का

[श्री राम कुमार कटवाल]

कष्ट करेंगे। चेयरमैन महोदय, मेरे बोलने से पहले हुड्डा साहब ने भी बड़े लच्छेदार तरीके से अपना भाषण दिया था और उन्होंने पिछले 34 साल के इतिहास की बात उठायी थी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन 34 सालों में से पांच साल तो चौधरी भजनलाल ने खा लिये। ये अपने साथ चालीस एम०एम०एल० ले गये थे और काफी समय दारूबंदी में चौधरी बंसी लाल ने ले लिया। चेयरमैन महोदय, 9 साल का तो हमारा तुजर्बा है। हम तो जिम्मेदार हैं इसलिए हमने तो लोगों को रोज़गार देना ही देना है। चौधरी भजन लाल जी जब सी०एम० थे तो ये राजौंद गए थे उस समय ये एक लाख रुपये की माला डलवाकर रफु चक्कर हो गये थे इन्होंने वहां के लोगों को कुछ नहीं दिया था। उस समय ये मुझे भी गाली गलौच देकर चले गये थे लेकिन मैं चौटाला साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही राजौंद को उप-तहसील का दर्जा दिया और उसके एक हफ्ते बाद ही वहां तहसीलदार बैठने लगा। एक हफ्ते बाद ही वहां ट्रैजरी भी आ गयी। इसी तरह से उन्होंने अलेवा को भी तहसील का दर्जा दिया वहां पर तहसीलदार आ गया और ट्रैजरी भी आ गयी है। भजनलाल जी तो वहां केवल रसगुल्ले खाकर ही आये थे इन्होंने वहां के लोगों को कुछ नहीं दिया। चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से कहना चाहूंगा कि राजौंद में एक अस्पताल है वहां पर केवल एक ही छोटा डाक्टर बैठता है इसलिए वहां पर डाक्टर्ज की पूरी टीम भेजी जानी चाहिए। भजन लाल जी ने तो वहां पर कोई डाक्टर लगाया ही नहीं। इसी तरह से वहां पर जो बस स्टैंड है उसका थोड़ा काम रूका पड़ा है उसको पूरा करवाकर चालू करवाया जाए। इसी तरह से मेरे इलाके में जो पानी की समस्या है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। चेयरमैन महोदय, मुझे अपने नेता पर पूरा विश्वास है कि वे हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। इसके साथ ही मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।

श्री दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : परम आदरणीय चेयरमैन महोदय, प्रथा और परमपराओं के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने आलोचनात्मक विश्लेषण और रचनात्मक सहयोग के साथ अपने-अपने विचार रखे। मुझे भी आपने सदन में पहली बार अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही मैं सभी सदस्यगणों से यह अपेक्षा भी रखता हूं कि वे मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने में सहयोग देंगे। चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं सदन में निर्वाचित होकर आए हुये सभी सदस्यगणों को हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देता हूं जिन्हें इस प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर के भेजा है। चेयरमैन सर, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है यहां की मुख्य आजीविका कृषि पर निर्भर है दक्षिणी हरियाणा के उस छोर से मेरा संबंध है जिसकी सीमा राजस्थान से सटी है। हमारे यहां पर किसान बड़े परिश्रमी और मेहनती हैं और उस सूखी धरती के सीने को चीरकर अपने पसीने से सींचकर अनाज पैदा करना तो जानते हैं लेकिन उनके भाग्य में हरियाली देखपाना उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। हमारे यहां नहरी योजना नहीं है जमीन से नीचे का पानी लिया जाता है और वह पानी भी दिन प्रति-दिन नीचे जा रहा है इसका कारण है, राजस्थान की तरफ से आने वाली तीन नदियां दोहान, कृष्णावती और साहिबी। इन पर राजस्थान ने अब बैराज बना दिया है इन नदियों से जो रीचार्जिंग हमारे यहां होती थी वह होनी बंद हो गई है। नारनौल के सब-डिवीजन में 25 गांवों के द्वारा गत विधान सभा चुनावों में चुनाव का बायकाट से आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार की तरफ से उन गांवों में कोई यह पता लगाने नहीं गया कि आखिर प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का बहिष्कार क्यों किया गया। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन गांवों के लोगों को यह कदम उठाना पड़ा? चेयरमैन सर, मैं आपकी मार्फत मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे यहां जमीन

के नीचे से पानी लाने के लिए डीप बोरिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है वह मशीन हमारे यहां सस्ती दरों पर मुहैया करवाई जाए ताकि इस समस्या का निदान हो सके। चेयरमैन सर, जब भी चुनाव होते हैं, हर पार्टी, हर राजनेता रावी ब्यास के पानी को लाने की बात करते हैं। चुनाव घोषणा पत्रों में घोषित करते हैं लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों रहता है महज चुनावी वायदा बनकर रह जाता है मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ढुलमुल नीति चल रही है उससे ऐसा लगता है कि पानी तो आएगा परन्तु हमारे खेतों में नहीं बल्कि हमारी आंखों में आएगा। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सक्षम हैं उनकी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी व भाजपा गठबंधन की सरकार है व केन्द्र में भी भाजपा और इनके गठबंधन की सरकार है। तीनों का इस तरह से सामंजस्य है कि यदि सच्ची नीयत से चाहें तो इस काम को करा सकते हैं यदि वे यह काम कराते हैं तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश उनका ऋणी रहेगा और हम इनके आभारी रहेंगे और अगर यह काम नहीं कर पाते हैं तो हम समझेंगे कि ये चुनावी घोषणाओं के ऊपर लाभ लेने की बात करते हैं। चेयरमैन सर, बिजली हमारी दूसरी समस्या है। दक्षिणी हरियाणा के लिए बिजली को यदि रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। नहरी पानी तो है नहीं इसलिए ट्यूबवैल से पानी निकालने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहां ट्रांसफार्मर्ज की तबदीली की अत्यंत आवश्यकता है और इसी वजह से मंडियाली जैसे कांड हुए हैं। ट्रांसफार्मर बदले जाने और बिजली की आपूर्ति करने के बारे में अभिभाषण में कहीं अभिलेख नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही चाहूंगा कि समय पर अपने अधिकारियों को निर्देश दें ताकि आने वाले समय में इस तरह के कांडों की पुनरावृति न हो। चेयरमैन महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है अभिभाषण से स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में असंतुलन और असमानता बरकरार है जहां एक तरफ हिसार में 2-2 विश्वविद्यालय हैं, मैडीकल कालेज है रोहतक में एक विश्वविद्यालय व एक मेडीकिल कालेज है, कुरुक्षेत्र में भी मैडीकल कालेज और विश्वविद्यालय है। चौथी तरफ मुरथल में इंजीनियरिंग कालेज है मैंने कल ही अखबारों में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने हिन्दु इंजीनियरिंग कालेज का उद्घाटन किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा ने ऐसा क्या किया है, न तो वहां पर विश्वविद्यालय है न मैडीकल कालेज है न कोई कृषि महाविद्यालय है, न विधि महाविद्यालय है न इंजीनियरिंग कालेज है, इस तरह की असमानता क्यों है ? मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में आप कोई विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा का संस्थान खोलें ताकि दक्षिणी हरियाणा में जो औद्योगिक बिकास हो रहा है वहां के लोगों को रोजगार देते समय कहीं यह न कह दिया जाए कि आप शिक्षित नहीं है या आप तकनीकी रूप से शिक्षित नहीं हैं। वहां पर नौकरी फिर यू०पी० और बिहार के लोगों को शिक्षा के नाम पर दे दी जायें इस असमानता को खत्म किया जाये। बेरोजगारी हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। एक हाथ के लिए काम पैदा होता है तो 99 हाथ बेरोजगार हो जाते हैं। जब तक रोजगार को शिक्षा से जोड़ने का काम नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का प्रावधान कहीं देखने को नहीं मिला। जहां तक शहरी बिकास का संबंध है। चेयरमैन महोदय, हर आदमी की कामना होती हैं कि वह अच्छी जगह पर रहे, वहां का वातावरण अच्छा हो और रोजमर्रा की कोई समस्या न हो। बिजली-पानी उपलब्ध होते हों, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा हो। मैं जिस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं वहां की समस्या तो कह सकता हूं। शायद हिन्दुस्तान में इतनी दुर्भाग्यशाली जगह दूसरी नहीं है जितनी महेन्द्रगढ़ है। ज़िला तो महेन्द्रगढ़ है और उसका हेडक्वार्टर नारनौल में है, ऐसा क्यों है ? क्योंकि महेन्द्रगढ़ में न तो बिजली की व्यवस्था है, न कोई सीवरेज की व्यवस्था है, न कोई मिनी सचिवालय है, न चिकित्सा की कोई सुविधा है। अगर वहां पर कोई अधिकारी जाता है तो पिछड़ा शहर देखकर उससे दूर भागने का प्रयास करता है।

[श्री दान सिंह]

हरियाणा प्रदेश को बने हुए 35 साल हो गये हैं। लेकिन महेन्द्रगढ़ आज तक पिछड़ा शहर ही है। सरकार की भी यह मानसिकता बनी हुई है कि अगर किसी अधिकारी को सजा देनी हो तो उसकी पोस्टिंग महेन्द्रगढ़ कर दी जाती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि महेन्द्रगढ़ शहर को विकसित करने के लिए वहां का विकास किया जाये और जो महेन्द्रगढ़ जिले के दफ्तर नारनौल में हैं उनको वापस महेन्द्रगढ़ में शिफ्ट किया जाये। ताकि वहां पर जाने वाला हर अधिकारी अपना हक समझकर वहां जाये और वहां के विकास कार्य करे। ऐसा न हो कि अधिकारी अपनी सजा समझ कर वहां रहे और यह दिन गिनता रहे कि कब यह सरकार बदलेगी और कब मैं अपने पैतृक स्थान पर जाऊंगा। इस समस्या का निदान करने की आवश्यकता है। चेयरमैन महोदय, अब मैं खेल-कूद के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक खेल-कूद का सवाल है। हमारे देश की 100 करोड़ आबादी है परन्तु कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं है। जब हम अपने देश की अंक तालिका देखते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें शून्य अंक देखकर हमारा सिर शर्म से नीचा हो जाता है। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार हमारे खिलाड़ियों को वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मिलतीं हैं। जो खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करते हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें राव बीरेन्द्र सिंह का नाम और जोड़ना चाहता हूं जिनके पुत्र राव इंद्रजीत सिंह जी इस महान सदन के सदस्य हैं। राव इन्द्रजीत सिंह निशानेबाजी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने कॉमनवैल्थ खेलों में जो सैफ में हुए थे भारतीय निशानेबाजी के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी किया था। आज राव इन्द्रजीत सिंह की लड़की वर्ल्ड शुटिंग चैम्पियनशिप में ब्रोन्ज मैडल जीतकर लाई है। 1999 में फिनलैंड में भी उसने ब्रोन्ज मैडल जीता था। वह दिल्ली की तरफ से खेलती है और रहने वाली हरियाणा की है। इसका कारण यह है कि हरियाणा में कोई अच्छा शूटिंग सैन्टर नहीं है दिल्ली में उसे वे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए सरकार को अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की तरफ ध्यान देना चाहिये। चेयरमैन महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। किसी भी प्रदेश की समृद्धि का पता उस प्रदेश की सड़कों को देखकर लग सकता है कि वह प्रदेश कितना खुशहाल है। गांवों में तो एक कहावत है कि गांव का पता तो गतवाड़ों से ही चल जाता है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि नारनौल से हिसार तक जो रोड़ है उसे नेशनल-हाई-वे करने के लिए अखबारों में तो कई बार पढ़ने को मिला लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस नेशनल हाई-वे का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये ताकि यहां के लोग जो अपने आप को बैकवर्ड महसूस करते हैं उस बात से उनको छुटकारा मिल सके। चेयरमैन महोदय, जहां तक शहीदों की बात है। मैं इस सरकार को और खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये किया। यह राशि भी उन रण बांकुरों के बलिदान के लिए कम है। हमारे देश के अन्दर कभी भी किसी दुश्मन ने बुरी नजर डालने की कोशिश की तो हमारे नौजवानों ने बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुये अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की एकता और अखण्डता को बरकरार रखा। उन शहीदों का सम्मान करना अनिवार्य है, यह हमारे लिए इज्जत की बात है। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 15 दिन पहले एक शहीद भाई ओम प्रकाश जो कि खांडसा का रहने वाला था कि मणिपुर में पोस्टिंग थी जब उसके पार्थिव शरीर को लाया जाने वाला था तो उसको रिसीव करने के लिए न तो जिले के एस०पी० साहब वहां मौजूद थे, न ही डी०सी० महोदय और न ही कोई मंत्री महोदय ही उपस्थित था। सबसे बुरी बात तो यह है कि हमारी सांसद जो स्वयं एक शहीद की पत्नी है जिन्हें शहादत के नाम पर वोट मिले हैं, वह भी उपस्थित नहीं थी। सबसे अफसोस की

बात तो यह है कि जब उस के पार्थिव शरीर का अन्तिम संस्कार किया जाना था तो गांव के किसी आदमी ने उसके लिए 2 गज जमीन तक नहीं दी और न ही सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था की और सार्वजनिक श्मशानघाट में उसका दाह संस्कार किया गया जो कि एक निन्दनीय बात है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब सरकार शहीदों के परिवार वालों को लाखों रुपये देती है तो उनकी समाधि के लिए थोड़ी सी जमीन का भी इंतजाम करवाए ताकि आने वाले बच्चों के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत बने। अन्त में सभापति महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी को 36 वर्ग, जाति के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है परन्तु दक्षिणी हरियाणा से इनको कम सीटें मिली हैं इसलिए इनके मन में बदले की भावना न हो और ये सबको एक समान दृष्टि से देखें और हरियाणा प्रदेश के विकास के सभी काम करने का प्रयास करें। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री गोपी चन्द : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो ओम प्रकाश शहीद की बात की है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि खांडसा मेरे क्षेत्र में नहीं लगता है, परन्तु मेरे हल्के के साथ लगता है, वह गांव सोहना से लगता है। जब तक ओम प्रकाश का शव नहीं आया था उससे एक रात पहले हम वहां पहुंच चुके थे और जहां तक ये जमीन की बात कर रहे हैं तो हमारे यहां तो पंचायतों के पास या किसी और के पास जमीने है ही नहीं। हमारे 40 गांव के एरिया में कोई श्मशान घाट ही नहीं है। खांडसा गांव में कम से कम श्मशान घाट तो है। जहां ओम प्रकाश के शव का दाह संस्कार किया गया। मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम इस पर रहम करके हमारे श्मशानों, जोड़ों, मन्दिरों और धर्मशालाओं को तो बक्श दें। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये)**

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप कांग्रेस को यानि अपोजीशन को खाने के टाईम पर ही बुला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आज की प्रोसीडिंग से पहले अपोजीशन को 301 मिनट मिले हैं और ट्रेजरी बैन्चिज को 197 मिनट मिले थे।

श्री इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधानसभा में तीसरी बार आया हूं। गवर्नर साहब ने अपना अभिभाषण दिया और हमने पार्टी की तरफ से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुना मैं समझता हूं कि अपोजीशन लहजीब से इस वक्त अपना काम कर रहा है। हमारी पार्टी के सदन के नेता ने कहा कि यह सरकार अभी-अभी बनी है इसलिए हम इसकी ज्यादा आलोचना नहीं करेंगें। मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि जनता ने जो फैसला किया है वह हमको मान्य है। अध्यक्ष महोदय, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हरियाणा की जनता का पूरा सहयोग मिला और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं चौटाला साहब को सपनों का सौदागर कहूं तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि इन्होंने चुनावों के समय में जनता को बड़े ही रंग-बिरंगें सपने दिखाये, जनता बहक गई और चौटाला साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। अध्यक्ष महोदय, आज से पहले भी चौधरी देवी लाल जी के समय में इसी तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी, सन् 1987 में 90 में से 85 सीटों पर लोक दल के सदस्य विजयी रहे थे। लेकिन 85 सीटें होने के बावजूद इनकी सरकार पूरे पांच साल नहीं चली और पहले ही टूट गई। अध्यक्ष महोदय, अब चौटाला साहब को 85 तो नहीं लेकिन 47 सीटें इनको पार्टी को मिली हैं और मेरी कामना है, मंशा है कि इनकी सरकार पूरे पांच साल चले। अध्यक्ष महोदय, अगर चौटाला साहब अपनी सरकार पूरे पांच साल चला लेते हैं और इन्होंने जो वायदे जनता से किये हैं, उन्हें

[श्री इन्द्रजीत सिंह]

पूरे करते हैं तो जनता तो इनकी वल्ले-वल्ले करेगी ही, हम भी इनकी वल्ले-वल्ले करेंगे। अगर इनकी सरकार बीच में ही टूटती है और जो वायदे इन्होंने जनता से किये हैं, वे पूरे नहीं कर पाते हैं, जैसा इनका पिछला इतिहास रहा है तो फिर सरकार बनाने का अवसर हमें मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हम मौजूदा सरकार में डिफैक्शन करके अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते, अगर मौजूदा सरकार अच्छे काम करेगी तो हम इनका साथ देंगे। अध्यक्ष महोदय, भगवान की दया से और जनता के स्नेह की वजह से 15 साल मैंने इस सदन के अंदर काटे हैं और मैंने यह महसूस किया है कि जब सरकारें बनकर आती हैं उस टाईम जो चुनावों के अंदर जनता से जो वायदे किये जाते हैं, धीरे-धीरे उनको ओट दिया जाता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। अध्यक्ष महोदय, अब मैं उम्मीद करता हूं कि सत्तापक्ष में जो सदस्य बैठे हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं या मंत्री हैं वे आने वाले समय में जनता की राय के अनुसार, निर्णय के अनुसार अच्छे कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब 1977 में मैं पहली बार विधायक बनकर यहां आया था उस समय बड़े जोर शोर से यहां पर रावी-व्यास के पानी की चर्चा होती थी कि एक साल के दौरान रावी-व्यास का चैनल हम बना देंगे और आज उस जमाने को 20 साल बीत गये हैं, उतने जोर-खरोश के साथ कोई सरकार उस मुद्दे को नहीं लेती क्योंकि बीच में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पंजाब की तरफ से हमें एक बूंद पानी न देने की घोषणा की गई। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि चौटाला साहब रावी-व्यास के मामले को नहीं सुलझा सकते हैं क्योंकि इनकी नीयत में फर्क है। यानी की परिस्थिति इस तरह की है कि पिछले 20 साल में जो कार्य नहीं हो पाया वह आने वाले पांच सालों में भी नहीं हो पायेगा क्योंकि मौजूदा सरकार ने इस मामले को सरसरी तौर पर ही जिक्र किया, जोर देकर नहीं किया। अगर जोर देकर कहते हैं और इसे पूरा नहीं कर पायेंगे तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बात पर मुझे बहुत एतराज है, मौजूदा सरकार से ही नहीं बल्कि जितनी भी सरकारें हरियाणा में आई उन सबसे है। किसी भी सरकार ने हरियाणा की जनता को यह जाहिर नहीं होने दिया कि रावी-व्यास के 3.5 एम०ए०एफ० पानी में से कुछ हिस्सा हरियाणा को मिलता है। अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा जिसमें गुडगांव, मेवात, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, नारनौल और झज्जर का कुछ हिस्सा पड़ता है, आज तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इन इलाकों से चुने हुये प्रतिनिधियों को कभी भी इरीगेशन का महकमा नहीं दिया क्योंकि उन्हें इस बात का भय होता था कि कहीं यह बात खुल न जाए कि जो रावी व्यास का पानी का दक्षिणी हरियाणा का हिस्सा है वह हिस्सा दक्षिणी हरियाणा के लोगों को न मिल कर दूसरे लोगों को मिल रहा है और दक्षिणी हरियाणा के लोगों को इस पानी से वंचित रखा जा रहा है। उन लोगों को यह पानी मिल रहा है जहां पर सेम आ रही है। आज हरियाणा के अन्दर कई ऐसे हल्के हैं जहां कीकर सूख गई है और वह कीकर इस लिये सूख गई है क्योंकि उनकी जड़ों में पानी खड़ा रहता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सेम की वजह से पेड़ के पेड़ खत्म हो गये हैं और समतल धरती हो गई है। जबकि आज ये लोग बात करते हैं कि पानी का समान बितरण करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये समान पानी का वितरण करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह उम्मीद जरूर करूंगा कि कम से कम 1.8 मिलियन एकड़ फुट पानी तो हमारे को दिलाएं जो कि हमारा वाजिब हिस्सा बनता है। उसके लिये कैरियर वाटर चैनल बनाएं। बार-बार यह बात आती है कि रावी व्यास के पानी को हम दक्षिणी हरियाणा तक कैसे पहुंचाए। आप बात करते है कि कैरियर लिंक चैनल बनायेंगे तो रावी व्यास का साढ़े तीन मिलियन एकड़ फुट पानी दक्षिण हरियाणा में आ जाएगा। सरकार को ये कैरियर चैनल खुद बनाने है और इन कैरियर चैनलों को बनाने के अधिकार भी सरकार के पास हैं लेकिन आज तक यह साढ़े तीन मिलियन एकड़ फुट पानी दक्षिणी हरियाणा को नहीं मिला। केवल बकाया 2

मिलियन एकड़ फुट पानी दक्षिणी हरियाणा को मिलना है, कम से कम उसके लिये दक्षिणी हरियाणा तक कैरियर चैनल बनायें और ये कैरियर चैनल बनाने के बाद जितना पानी का हक हमारा है वह पानी का हिस्सा हमारे को दें। अगर आप दे देते हैं तो आपकी वाह-वाह। अगर आप नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हम लेकर दिखायेंगे। यह हमारा दावा है। अध्यक्ष महोदय, वाटर पोलिसी के ऊपर बात हो रही थी। आज से कुछ दिन पहले जब आप गांव के अन्दर जाया करते थे तो आपने वहां देखा होगा कि जगह-जगह पर ढहर बने हुआ करते थे जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा होता था और आस-पास के पांच-सात गांवों में कुओं का पानी रिचार्ज होता रहता था। गांवों के कुंओं के अन्दर पानी का स्तर 20-30 फुट पर सीमित रहता था जबकि आज वहां पानी 200 से 300 फुट नीचे तक चला गया है। आज वो ढहर देखने को नहीं मिलते। अध्यक्ष महोदय, चौ० धीरपाल जी रोहतक जिले से हैं इन्होंने भी देखा होगा कि गांवों में ढहर हुआ करते थे लेकिन आज वहां कोई ढहर नजर नहीं आता। अब किसान उन ढहरों के ऊपर खेती करने लग गये हैं। वे खेती करके अपने लिये थोड़ा-बहुत अनाज जरूर पैदा कर लेते हैं लेकिन आस-पास के बीसियों गांवों का अनाज पैदा करने का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। पहले जहां एक कीले में 50-60 मन अनाज की पैदावार होती थी वहां आज एक कीले में केवल 30 मन गेहूं की पैदावार रह गई है। यह समस्या इसलिये पैदा हो गई है क्योंकि उन खेतों में पूरा पानी नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे यहां जो ढहर हुआ करते थे उन ढहरों को दोबारा से अडन्टीफाई किया जाए और अडन्टीफाई करके उन ढहरों को ढहरों के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए। जो किसान इन ढहरों पर खेती करते हैं उनसे ये ढहर पानी खड़ा करने के लिये ले लिए जाएं और जितना अनाज इन ढहरों पर वे पैदा करते थे उसके बराबर की आमदनी उन्हें बिना खेती किये हुये सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में दी जाए। ऐसा करने से कम से कम उन ढहरों के समीप लगने वाले गांवों के खेतों को पूरा पानी तो उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ-साथ मैं पीने के पानी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। आज सरकार की तरफ से गवर्नर साहब ने 70 लीटर प्रति व्यक्ति को पीने का पानी देने की घोषणा की है और यह लक्ष्य आज से पहले शायद 45 लीटर से 50 लिटर का था लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाया है। आज के दिन मुझे नहीं लगता कि 70 लिटर प्रति व्यक्ति पानी देने का लक्ष्य ग्राउन्ड वाटर से पूरा हो पाएगा। जिन गांवों के मार्फत दूसरे लोगों को पीने का मीठा पानी मुहैया कराया जाता है वहां पानी का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वे गांव 300 फुट नीचे से पानी ले रहे हैं और दूसरे गांवों को पानी देने के लिये बहुत एतराज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भगवान ने हमारे दक्षिण हरियाणा के अन्दर जमीन का खारा पानी दिया है। हमारे एरिया में बहुत कम जगहों पर मीठा पानी है। जहां पर पहले मीठा पानी था वहां से दूसरे लोग ले लिया करते थे लेकिन अब उन लोगों ने पानी देना बन्द कर दिया है। सरकार कह रही है कि हम प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लिटर पानी मुहैय्या करवाएंगे। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 70 लिटर पानी प्रति व्यक्ति तब मुहैय्या करवा पायेगी जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर, कैनाल बेस्ड पानी वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मुहैय्या करवायेगी। सरकार ने इरीगेशन चैनल के खर्चे का भी जिकर किया है। इरीगेशन चैनल वहां पर ही होता है जहां पर आलरेडी पानी पहले ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम तो अपने एरियाज में पीने के पानी की ही मांग कर रहे हैं, खेती के लिए तो पानी की मांग कर ही नहीं रहे। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि यदि आने वाले 5-7 सालों में हमारे वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवाई गई तो लोग वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर वाटर वेस्ड स्कीमें बनाएं ताकि लोगों को कम से कम पीने का पानी तो मिल सके।

[श्री इन्द्रजीत सिंह]

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में बहुत चर्चा हुई है। आपकी सरकार किसान सहयोगी सरकार होने के नाते ही चुनाव जीत कर आई है। यहां पर बताया गया कि शुगर केन की प्राईस 110 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। यह अच्छी बात है। मैं इस बारे में दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब एक फसल की कीमत अधिक बढ़ा दी जाती है तो दूसरी तरफ इन्बैलेंस आ जाता है। हमारे एरियाज में सरसों की अधिक पैदावार होती है। पिछले एक साल पहले तक 2000 रुपये प्रति क्विंटल सरसों का दाम था लेकिन अब वह गिर कर 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया है जो किसानों के लिए ठीक नहीं है। इसका मेन कारण यह है कि सेन्टर की सरकार जिनको आप केन्द्र में सहयोग दे रहे हैं और यहां पर उस सरकार का सहयोग ले रहे हैं वह पामोलीन आयल बहुत अधिक मात्रा में बाहर से मंगवा रही है जिस कारण सरसों के दाम एकदम नीचे गिर गए हैं। इस पार्टी ने जो सेन्टर में राज कर रही है सरसों के बीज में कटेहली का बीज मिला दिया था। आपको याद होगा कि कटेहली की बीजाई अलग समय में होती है और सरसों की बिजाई अलग समय में होती है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हमारे एरियाज में जो फसल होती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुये उचित पग उठाये ताकि वहां के किसानों को भी अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं दक्षिण हरियाणा से सम्बन्ध रखता हूं। पूरे हरियाणा में तो लोकदल की सरकार को बहुमत मिल पाया है लेकिन हमारे अहिरवाल क्षेत्र के 10 हल्कों में से केवल 2 सीटें ही लोकदल की सरकार को मिल पाई हैं। अब तक जो भी सरकारें आई हैं वे तरह तरह के वायदे करके आती रही हैं कि हम अहिरवाल क्षेत्र में यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन कोई भी सरकार सत्ता में आने के बाद उस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देती। चुनावों के दौरान और चुनावों से पहले ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे एरियाज में कई बार गए। 4-5 जगह पर तो कुछ छोटा-मोटा काम हुआ था बाकि हमारे एरियाज में सड़कों के निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे एरियाज की 10 सीटों में से 4-5 जिलों में तो सड़कों की मुरम्मत बिल्कुल नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इंडस्ट्रियल पालिसी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर जिक्र आया है कि यह सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान के सहयोग से सरकार बन कर आई है। पिछले कुछ समय से हमारे हरियाणा के अन्दर कई फैक्टरीज स्थापित हुई हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली से मथुरा, जयपुर से दिल्ली, सोनीपत से दिल्ली और बहादुरगढ़ साईड में काफी फैक्टरीज लगी हैं। जहां पर पहले लोग खेती करते थे अब वहां पर फैक्टरीज लग गई हैं। ऐसी जगहों पर जो लोग फैक्टरीज लगाने के नाम पर जमीन लेते हैं बाद में मुनाफा कमा कर चले जाते हैं जबकि किसान को जमीन का बहुत ही कम भाव देते हैं। लेकिन जिन लोगों की जमीन गई है उनको राहत मिलनी चाहिए। हम कहते तो रहे हैं और हमने प्रयास भी किए हैं लेकिन हम असफल रहे हैं शायद यह सरकार ही इस मामले में कामयाब हो जाए। जिन लोगों की जमीनें हासिल करके रियायती दरों पर दी गई हैं उन गांवों के और उन लोगों के बच्चों को वहां पर नौकरी देने का कानूनी तौर पर लाजमी होना चाहिए। कह तो देते हैं कि जिनकी जमीनें गई हैं उनके बच्चों को नौकरी देंगे लेकिन वहां पर स्टील के गेट के भीतर किसी गांव वाले को कोई घुसने नहीं देता। बाहर गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कम से कम जिनकी जमीनें गई हैं उनके बच्चों को वहां पर नौकरी मिल जाए। हमारी पुश्तें उन जमीनों को काश्त करती रही हैं अगर उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी तो उससे उनको कुछ राहत तो मिलेगी। श्री गोपी चन्द गहलौत जी ने जिक्र किया गुड़गांव क्षेत्र के आस-पास

ऐसा एरिया है जहां पर अगर कोई बहन जंगल जाना चाहे तो जंगल नहीं जा सकती है। कहीं दो गज़ जमीन ऐसी खाली नहीं है जिसके अन्दर वह अपना नैचुरल काम कर सके। स्पीकर सर, इस तरह की स्थिति को दूर करने के लिए अगर सरकार प्रयास करे तो हमारी पार्टी इस सरकार को पूरा सहयोग देगी। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि इलैक्शन अनाउंस होने के बाद कुछ नगरपालिकाएं कैंसल कर दी गई। 29 नगरपालिकाएं ऐसी हैं जो कि भंग कर दी गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी हमें कोई कारण बताएं कि ये नगरपालिकाएं क्यों भंग की गई हैं इसके लिए हम उनके आभारी होंगे। कोई कहता है कि नगरपालिकाएं इसलिए भंग कर दी गई क्योंकि उनकी माली हालत दरुस्त नहीं थी लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है कोई ऐसी नगरपालिका नहीं है जिसकी माली हालत ठीक नहीं थी क्यों उसको तोड़ा गया ? किस वजह से यह निर्णय लिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को या कार्यकर्त्ताओं को निराश करने की मन्शा से तो ऐसा नहीं किया गया ? हम तो यही समझ सकते हैं कि नगरपालिकाओं को भंग करके भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश कर दिया गया है पता नहीं कृष्ण पाल गुर्जर इनकी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आपका समय हो गया है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री इन्द्रजीत सिंह : ठीक है जी, अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, महामहिम गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सर्वप्रथम माननीय श्री गोपी चन्द जी ने मेरे महकमे से सम्बन्धित कुछ प्वांयट्स को आधार मान कर चर्चा की। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को और पूरे हाउस को जानकारी देना चाहता हूँ। माननीय बिधायक ने झाड़सा गांव की शमशान भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में समस्या का जिक्र किया। स्पीकर सर, वर्तमान सरकार बनने से पहले पिछली सरकार के समय इस शमशान भूमि को अधिग्रहण किया गया था। वर्तमान सरकार बनने के बाद झाड़सा गांव के निवासी आदरणीय मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से गुड़गांव में मिले थे और मुख्य मंत्री जी ने उनकी भावनाओं को देखते हुए यह आदेश पारित किये कि उस शमशान भूमि के बदले में उतनी जमीन अलग से अलॉट की जाएगी और जो जमीन अलॉट की जाएगी उसकी चारदीवारी का खर्चा टाउन एण्ड कण्ट्री विभाग द्वारा किया जाएगा। वहां पर ट्यूबवैल लगवाने के लिए, अन्तिम संस्कार करने के वास्ते शैड बनाने के लिए और वहां पर पौधारोपण के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा, मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए उतनी राशि स्वीकृत कर दी है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कार्टरपुरी गांव में जब पिछली सरकार के समय शमशान भूमि का अधिग्रहण किया गया था तो लोगों में निराशा और नाराजगी आना स्वाभाविक बात थी। लेकिन वर्तमान सरकार बनने के बाद करीब एक एकड़ जमीन गांव की पंचायत ने गांव के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर जहां वाजिब बनती थी, उस जगह को अंकित कर दिया है। उस बात पर आज गांव कार्टरपुरी के निवासी, प्रधान और जमींदार सहमत हो गए हैं। वहां पर ट्यूबवैल लगाने के लिए पौधारोपण के लिए एवं शैड आदि को बनाने के लिए ऐस्टीमेट्स तैयार करके खर्चा किया जाएगा। शायद वहां पर काम शुरु हो गया है। माननीय विधायक जी ने अन्य कई बातों पर हमारा ध्यान केन्द्रित किया है। उनकी कुछ आशंकाएं वाजिब थीं। पीछे क्या हुआ उस पर वही लोग प्रकाश डाल सकते हैं जो उस वक्त थे। लेकिन वर्तमान सरकार के गठन के बाद विधायक जी इस बात के गवाह है कि जो भी काम इस सरकार ने कहे हैं वे करे हैं। अध्यक्ष महोदय, गलियों को बनवाना, पानी की निकासी करवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करवाना और सीवरेज की देखभाल वही संस्था करती है जो भूमि अधिग्रहण करती है। धनुआपुर गांव माननीय विधायक जी के हल्के में पड़ता है। उस गांव में पीने के पानी का अभाव था, पानी की निकासी

[श्री धीरपाल सिंह]

की समस्या थी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक करोड़ रुपया उस गांव के पानी की निकासी के लिए, गली के निर्माण के लिए स्वीकृत किया है शायद वहां पर काम भी शुरू हो गया होगा। कुछ प्राईवेट कलोनाईजर हैं। उन्होंने वहां पर भूमि का अधिग्रहण किया हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद उनको अहसास करवाया जा रहा है कि जहां पर प्राईवेट कलोनाईजर्ज ने भूमि का अधिग्रहण किया हुआ है वहां गलियों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी व्यवस्था करना उनकी जिम्मेवारी बनती है और वे सैद्धान्तिक रूप से तैयार भी हो गए हैं। जिन गांवों को वर्तमान सरकार ने गठन के बाद अडाप्ट किया है उनमें झाड़सा, खांडसा, सुखराती, सीरहोल डुंडाहेड़ा, मंडेहड़ा, काटरपुरी, गुड़गांव, काजीपुर, कन्हीं और सात गांव दूसरे थे। इसमें सात गांव ऐसे हैं जहां भूमि का अधिग्रहण तो हो चुका है लेकिन उस पर किसी का कब्जा न होने की वजह से उन गांवों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। माननीय विधायक जी ने एक प्वायंट और रेज किया था। आठ-नौं गांव ऐसे हैं जिनमें 137 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि की रिक्वरी की बात माननीय हाईकोर्ट के आदेश के कारण आई है। ये गांव झांडसा, सीलाखेड़ा, इस्मायलपुर, सुखराली, कन्हीं, बजीराबाद, घाटा, समस्तपुर और हेदरपुर हैं। जिन गांवों का जिक्र मैंने अभी किया है उनके बारे में माननीय हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिया कि इनमें ज्यादा मुआवजा वितरित किया गया है इसलिए इनसे रिक्वरी की जाए और यह जो आदेश पारित हुए वह पिछली सरकार के समय में ही पारित हुये। उसके बाद कुछ किसान भाई डबल बैंच में गए तथा कुछ किसान भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप भी स्वयं वकील हैं और कई दूसरे विधायक भी वकील हैं इसलिए आप सबको यह पता ही है कि जो विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लम्बित हो उस पर हाउस में चर्चा करना वाजिब नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में यह केस किस स्टेज में है और हरियाणा सरकार का इस बारे में क्या स्टैंड है ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो विषय कोर्ट के आधीन विचाराधीन हो उस पर हाउस में चर्चा करने की परम्परा नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : लेकिन सरकार का इस बारे में क्या स्टैण्ड है ?

श्री धीरपाल सिंह : हुड्डा साहब, मैंने इस बारे में हर चीज देखी है। फिर भी अगर विधायक जी को किसी बात की जानकारी की कमी रह जाएगी तो जानकारी देने का तो मेरा दायित्व बनता है।

श्री गोपी चन्द : स्पीकर साहब, मेरा नाम यहां पर आया है और मेरे क्षेत्र से संबंधित चर्चा चल रही है। इस विषय में मैंने जो कहना था वह कह दिया था। अब मैं इतना ही कहूंगा कि हर क्षेत्र में ये किसानों के मुआवजे में इंक्रीज की बात कर रहे थे। यह मामला पिछली सरकार से विरासत में मिला हुआ है। जो कम्पनसैशन कलैक्टर रेट फिक्स किए जाते हैं उनके बारे में मुझे पता है चूंकि यह कोर्ट का मामला है और मैं वकील भी हूं इसलिए मैं इस विषय में ज्यादा यहां पर नहीं कहूंगा। लेकिन इस बारे में गवर्नमैंट का लिबरल ऐटीच्यूट होनी चाहिए । जो कलैक्टर रेट फिक्स किए जाते हैं उसके अंदर पब्लिक रिप्रेजेनटेटिव रखने का भी प्रावधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर आज भी आप कमपैरेटिव रेट देखेंगे तो हुडा के जो मार्किट रेट हैं और किसानों को जो मुआवजा दिया जाता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाहूंगा कि इस बारे में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें कमिश्नर, जिस जिले की जमीन का अधिग्रहण होता है उससे संबंधित जिले का उपायुक्त, तहसीलदार साहब, एल०ए०ओ० तथा दूसरे अधिकारी होते हैं। जहां-जहां पर भी किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती की उनमें से कई जगह ऐसी हैं जहां जमीन छोड़ने का काम किया गया है। माननीय विधायक साथी के क्षेत्र में सुखराली गांव में इस तरह की कोई दिक्कत थी। उन गांवों से जैसा कहा वैसा ही हुआ। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से हाउस को एक और इंस्टांस बताना चाहता हूं कि 15 मार्च, 1991 की यह घटना है उस समय चौधरी ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे और मैं इसी महकमें से संबंधित मंत्री था। आपके अपने गांव में कुछ किसानों के बने हुये मकानों के बारे में दफा चार और 6 के नोटिस जारी हो चुके थे। हमने उस समय मुख्यमंत्री जी के आदेश की पालना करते हुए सारे गांव को इकट्ठा किया और सारे गांव वालों के बीच में बैठकर एक लाईन नक्शे में खींच दी कि 15 मार्च, 1991 तक जो निर्माण हो गया वह तो छूट जाता है और इससे आगे से ही जमीन का अधिग्रहण होगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ऐसे भी उदाहरण हमारी सरकार के समय में हुए हैं और हमने गांव के लोगों से पूछकर निर्णय लिए हैं। इस तरह से यह सरकार किसानों के हिमायत की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा । इसके अलावा इन्होंने सरकार के गठन के बारे में भी कहा। चौटाला साहब ने किसानों के लिए, 36 बिरादरियों के लिए अपने सात महीने के शासनकाल में बहुत कुछ करके दिखाया है। लेकिन दिल्ली की सरकार तो केवल प्याज के नाम पर बनी हुई है। यहां पर चर्चा की जा रही है कि यह हुआ वह हुआ। यह तो वही बात हुई 'कि औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत'। दिल्ली की सरकार तो केवल प्याज के नाम पर ही लोगों ने बना दी।

पिछले 5-6 महीने में 310 करोड़ रुपये के विकास के कार्य शुरू हुए। पांच सौ करोड़ रुपये के सड़कों के पैच वर्क का कार्य शुरू हुआ और उस पर अगला काम भी शुरू होने जा रहा है उसके बावजूद भी हमारा काम इनको दिखाई नहीं देता है। कर्ण सिंह जी वरिष्ठ विधायक हैं इन्होंने अवैध कालोनियों के निर्माण के बारे में मुद्दा उठाया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी एन०सी०आर की मीटिंग में यह बात उठाई थी कि एन०सी०आर० का दबाव हम पर है क्योंकि दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां आती हैं चाहे वह बिहार से आएं, उड़ीसा से आएं या दक्षिणी भारत से आएं, उनमें कोई न कोई हमारा हिन्दुस्तानी भाई वहां से आता है और इसका सारा दबाव फरीदाबाद और गुड़गांव पर पड़ता है। एन०सी०आर की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया था कि जो असंतुलन बिजली का, रिहाइश का, पानी का, गंदगी का और जो अन्य दबाव हरियाणा पर बढ़ रहा है उसकी तुलना में हरियाणा को एन०सी०आर० से मिलने वाला पैसा नाम मात्र का है। मैंने भी यह प्वायंट उठाया था कि हमारे यहां बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा है। यदि बाहर से कोई आदमी आता है तो वह फरीदाबाद में या गुड़गांव में आता है जिससे दिन प्रति दिन हरियाणा पर दबाव बढ़ रहा है। मैं अपने साथी कर्ण सिंह जी को एक जानकारी देना चाहता हूँ।

श्री बलबीर पाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें पानीपत को भी इंक्लूड कर लिया जाए।

श्री धीरपाल सिंह : कर्ण सिंह जी, आप ऐसी सरकार में मंत्री रहे जिसके समय में फरीदाबाद के सैक्टर -48 का हुड्डा ने अधिग्रहण किया। उसके बाद मुआवजा सरकार ने दिया, कब्जा लिया, सड़कों का निर्माण किया, खंभे लगाए लेकिन उस पूरे सैक्टर को प्रॉपर्टी डीलर बेचकर खा गए। अध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारी, कब्जा हमारा, जमीन हुड्डा की और मुनाफा प्रॉपर्टी डीलर खा गए। वर्तमान सरकार के गठन के बाद जब यह जानकारी हमें मिली तो इनके खिलाफ कार्यवाही हुई और मैं विधायक जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जहां-जहां भी हुड्डा के अनडिवैलपड सैक्टर रह गए हैं वहां वर्तमान सरकार

[श्री धीरपाल सिंह]

के गठन के बाद कांटेदार तार लगाए गए हैं और 4 सैक्टर, 48 सैक्टर व अन्य सैक्टर्ज में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राइवेट सुरक्षा एजैंसियों को दी गई है। इसके अलावा एक आयोग का गठन हुआ भी है। उसके चेयरमैन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज़ कपूर साहब हैं। सैक्शन 75 और 63 में अवैध कालोनियों का निर्माण होता है उनकी अपील सुनने का उस आयोग को अधिकार है उसमें कुछ के खिलाफ चालान भी हुए हैं, कार्यवाही की जा रही है हमने कपूर साहब से विनती की है कि आप कुछ थोड़ी सी जल्दी करके ऐसे केसों का निपटारा करें जिससे दूसरों को सबक मिल सके। हम आपकी कही हुई बात पर कार्य करेंगे। कोशिश होगी कि अवैध कालोनियों का निर्माण न हो। कैप्टन साहब ने धारूहेड़ा के बारे में कहा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, मंत्री जी ने आप को सैटिस्फाई कर दिया है। जब आप बोले तब आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया इसलिए अब आप बैठ जाइए। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने धारूहेड़ा के बारे में हाउस में चर्चा की। धारूहेड़ा के पास छोटे-छोटे गांव जैसे बाटल, महेश्वरी, केहड़ा, कापड़ीवास, ये ऐसे गांव जो कंट्रोल्ड एरिया से बाहर हैं। ये सब गांव राजस्थान से लगते हैं। हरियाणा के बार्डर पर भिवाड़ी राजस्थान का एक औद्योगिक शहर है इस कारण इन गांवों में छोटे-छोटे मकान बन रहे हैं। इसलिए इसके बारे में मैं हाउस को जानकारी देना अच्छी बात समझता हूं। सबसे पहले धारूहेड़ा के सैक्टर 4-ए में फ्लैट बनाने की स्कीम तैयार की गई थी लेकिन बाद में उस स्कीम को मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से रोक दिया गया था। उसके बाद वहां पर 100-100 गज़ या 80-80 गज के निम्न वर्ग के लोगों को प्लाट मुहैया कराने के लिए दोबारा से स्कीम तैयार की गई है। अब उस सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को प्लाट देने की व्यवस्था की जायेगी। इस सरकार की एक नीति और है कि जो प्राइवेट कोलोनाइजर हैं वे जहां पर भी जमीन को डिवैलप करते हैं वहां पर उनको 25 प्रतिशत निम्न वर्ग को निम्न लागत पर प्लाट देने होते हैं। वे 20 प्रतिशत प्लाट नो-प्रोफिट नो-लौस पर देते हैं। वर्तमान सरकार आने के बाद हमारी कोशिश यह होगी कि गांव के लोगों को अच्छे ढंग के प्लाट मिलें और सुविधा मिले। मैं हाउस की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि पिछली सरकार के समय में 14 मरले और 10 मरले के प्लाटों की कीमत 1296- रुपये प्रति वर्ग गज थी परन्तु वे प्लाट बिक नहीं सके थे। वर्तमान सरकार आने के बाद उस भाव को बदलकर 1000/- रुपये प्रति गज किया है यानि जहां पहले कीमत ज्यादा थी उसको कम किया है और दोबारा से रोहतक, हांसी, नरवाना आदि के जो प्लाट बिक नहीं सके थे उनको कमेटी बनाकर कीमत कम की गयी है और उन प्लाट्स को दोबारा बेचने का काम शुरू किया है। स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, कुछ माननीय सदस्यों ने सबसे पहले कानून और व्यवस्था का जिक्र किया कि आज कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, असुरक्षा का माहौल है, आदि-आदि। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सारा हाउस भी जानता है कि ला एण्ड ऑर्डर का प्रोसैस कितना लम्बा है कितना कंटीनुअस प्रोसैस है। जब तक कोई सरकार मेहनत का काम नहीं करती तब तक लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थित ठीक नहीं हो सकती। ज्यों-ज्यों सोशल चेंजिज आ रहे हैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहले समाज इकट्ठा रहता था, पंचायतें होती थी आज वह टूटती जा रही हैं, समाज के रिलेशन टूटते जा रहे हैं। पुलिस बल जो कि सारे इंतजाम को देखता है उसमें और

पब्लिक में जब तक कोर्डीनेशन नाम की चीज नहीं होगी तब तक लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति कैसे ठीक रह सकती है ? पिछले साल 24 जुलाई, 1999 को ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी, उस समय प्रदेश की क्या हालत थी इस बात को आप सभी सदस्यगण और हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। अभी मेरे आदरणीय साथी जय प्रकाश जी प्रोहिबिशन का जिक्र करके बात को टाल गये। बार-बार प्रोहिबिशन का नाम लेने से बात नहीं बनेगी। लेकिन जहां तक अपराधिक मामलों के बढ़ने का सवाल है चाहे डकैती हों, किडनैपिंग विद रैन्सम हों, प्रोहिबिशन के बाद ये सब नई शक्ल के रूप में आए हैं। प्रोहिबिशन के दौरान सारी पुलिस, पोलीटीकल हाई अप्स ने मिलकर ला एण्ड आर्डर को इफैक्टिव तरीके से चलाने की बजाय सारे ऐसे काम किए जिससे क्राइम को बढ़ावा मिला। शराब की हजारों-हजारों बोतलें भरकर ले जाई जाती थी। दादरी से जो सदस्य यहां चुनकर आए हैं उन्होंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि किस तरह से चिटें दी जाती थी कि इन ट्रकों को नहीं पकड़ना हैं। यही पिछली सरकार की मैरिट और डी-मैरिट थी। जो इस तरह से शराब बेचने का काम करवाते थे। उनकी उसी प्रकार से पोस्टिंग होती थी। जब इस प्रकार के काम होंगे तो पुलिस बल को शह मिलेगी और ला एण्ड आर्डर की स्थिति में गिरावट आएगी। इसी तरह थोक के व्यापारी समाज के अन्दर सरकार के संरक्षण में काम करते थे। उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों और औरतों को इस प्रकार शराब बेचने के काम में इन्वाल्व कर दिया था। उनसे 2 बोलत, 4 बोलत, पव्वा शराब बेचने के काम करवाए जाते थे। इन्टरनैशनल बोर्डर नेपाल और हिन्दुस्तान के एरियाज में औरतें और बच्चों से इसी प्रकार शराब बेचने के काम करवाए जाते थे। हरियाणा के स्कूलों के बच्चों के बस्तों में शराब के ये पाउच देखे गए। इसी तरह से शराब बन्दी के समय 16-17, 18-20 साल के बच्चों पर सरकार द्वारा केस बनाए गए जबकि शराबबन्दी के समय सोशल रैजोल्यूशन की जरूरत थी, लोगों को विश्वास में लेने की जरूरत थी। आनन-फानन तरीके से प्रोहिबिशन करके प्रदेश में क्राइम को बढ़ावा दिया गया। क्राइम को बढ़ाने में प्रोहिबिशन एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बने अभी जुम्मे-जुम्मे 8 महीने हुए हैं और इसी दौरान 2 चुनाव भी आ गये पहले पार्लियामैंट के और फिर विधान सभा के। अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयुक्त ने माना है कि हरियाणा प्रदेश में ये दोनों ही चुनाव सबसे शांतिमय और निष्पक्षता से हुये हैं। स्पीकर सर, आप भी जानते हैं कि इन दोनों चुनावों में प्रशासन को भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ी है। बूथों की सुरक्षा के लिए, कंडीडेट की सुरक्षा के लिए और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को चुनावों के समय में कायम रखने के लिए चुनाव आयुक्त के आर्डरों के मुताबिक पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, जो छोटे-छोटे बच्चे थे, कच्ची उम्र के लोग थे उन्होंने प्रोहिबिशन के बाद डकैती, किड-नैपिंग आदि क्राईम अपना लिये। स्पीकर सर, इस क्राईम में शामिल युवकों को केवल पुलिस फोर्स से ही नहीं दबाया जा सकता बल्कि सोसाइटी में भी जागरुकता पैदा करनी पड़ेगी। इंसैंटिव और डिसइंसैंटिव करना पड़ता है। स्पीकर सर, हम आंकड़ों की बात नहीं करते और न ही आंकड़ों से संतुष्ट होते हैं। उस समय जो नजारा पैदा हुआ था उस पर हमारी सरकार अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई है। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि उस क्राईम पर पूरी तरह से काबू पाया जाये। स्पीकर सर, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को और सभी सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हम सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। स्पीकर सर, जहां तक आंकड़ों की बात है हमारी सरकार बनने से पहले आई०पी०सी० के 24460 केस दर्ज हुए थे और अब 23463 केस दर्ज हुये हैं। इस तरह से 997 केसिज की कमी हुई है और मर्डर के केसों में 30 की कमी आई है। लेकिन हमारी सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। स्पीकर सर, हम पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने इनसैंटिव और डिसइनसैंटिव की बात कही है। स्पीकर सर, पिछली सरकारों ने लॉ एण्ड आर्डर पर कम ध्यान दिया और

[श्री सम्पत सिंह]

दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान दिया तथा पुलिस को किसी भी सरकार ने इनसैंटिव नहीं दिया। स्पीकर सर, 1987 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी उसी वक्त इनसैंटिव पुलिस को दिया गया था। उसके बाद किसी भी सरकार ने पुलिस को इनसैंटिव नहीं दिया है। स्पीकर सर, 1987 से 1991 में जब हमारी सरकार थी। चौधरी देवी लाल जी और ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी उसी समय पुलिस को इनसैंटिव दिया गया। उसके बाद 8 साल हो गये हैं पुलिस को किसी भी सरकार ने इनसैंटिव नहीं दिया। स्पीकर सर, अगर पुलिस फोर्स को इनसैंटिव नहीं दिया जायेगा तो वे ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। उनके काम में कार्यकुशलता नहीं होगी। अभी एक सदस्य जो आई०जी० भी रहे चुके हैं, ने भी कहा था कि पुलिस वालों को ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिएं। हुडा साहब ने भी इस बारे में कुछ कहा था। स्पीकर सर, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में पुलिस को किसी भी तरह का इंसैंटिव न देकर उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अगर कोई एस०पी० लगा हुआ है और वह सरकार के लोगों का काम नहीं करता था तो उसकी रिपोर्ट्स में क्या-क्या लिखा जाता था इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, केवल सैडैस्टीक करैक्टर मात्र लिखने से काम नहीं चलेगा। उसका काम देखना चाहिए। एक तो कोई काम करे, फिर उसको सजा मिले। ऐसा होने से काम नहीं चलेगा और न ही उसे किसी तरह का इनसैंटिव दिया जाये। स्पीकर सर, अगर पुलिस वालों पर ऐसी ज्यादती होगी तो कैसे काम चलेगा ? उनको इनसैंटिव भी देने पड़ते हैं। हमने 1987 से 1991 के दौरान पुलिस को सिपाही लैवल से इन्सपैक्टर लैवल तक पंजाब और हिमाचल के बराबर ग्रेड दिये। उस समय पंजाब और हिमाचल के हाईएस्ट ग्रेड हुआ करते थे। इसी प्रकार से डिप्टी एस० पीज़ को एच०सी०एस० के बराबर ग्रेड दिये। ये इन्सैंटिव हमारी सरकार ने उस टाइम दिये । इसी तरह से जो बी०-I कोर्सिज़ हुआ करते थे जिससे छोटी उम्र के सिपाहियों के दिमाग में यह नक्शा होता था कि वे जल्दी ही इन कोर्सिज़ की सहायता से हैड कांसटेबल बनेंगे फिर ए०एस०आई० बनेंगे और फिर इन्सपैक्टर बनेंगे। वह सारे कोर्सिज़ बन्द कर दिये गये थे, मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सैंटर को बेकार करके छोड़ दिया था। टोटल प्रोमोशनल कोर्सिज़ बन्द कर दिये थे। प्रोमोशन के चांसिज़ नहीं रहेंगे तो उनको क्या चार्म रह जाएगा ? वह सिपाही दिन में ड्यूटी करके शाम को लाठी फैंक कर मारेंगे और सरकार को गाली देंगे। इसके सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। जब उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी तो वे ऐसा ही करेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने उनकी भी सुध ली है। अध्यक्ष महोदय, अब आती है ए-लैवल की पुलिस कॉफ्रैंस बुलाने की बात। चाहे चौधरी बंसी लाल की सरकार रही, चाहे चौधरी भजन लाल की सरकार रही हो। इनकी सरकारों में ए-लैवल की कोई कॉफ्रैंस नहीं की गई। हां ये लोग यूनियन की बातें करते रहे हैं और यूनियन के जो प्रधान थे उन लोगों ने कोठियां बना ली और भी सब कुछ किया लेकिन आम पुलिस कांस्टेबल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद अब जो पुलिस के लिये काम किये गये हैं उनके बारे में मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा। हमारी सरकार ने पुलिस फोर्स में जान डालने के लिए सिपाही, हवलदार और ए०एस०आई० को पंजाब के बराबर वेतनमान दे दिया है जो कि दिल्ली से भी ज्यादा कर दिया है। इसी तरह से राशन मनी ढाई गुणा, एच०आर०ए० भी डेढ़ सौ से साढ़े तीन सौ कर दिया है और ज़िला स्तर पर एच०आर०ए० 100/- रुपये से 250/- रुपये कर दिया है। यह सब चौटाला साहब की मौजूदा सरकार ने किया है। इसी तरह से वाहन भत्ता बाबा-आदम के पुराने जमाने से चला आ रहा था उसको भी तीन गुणा कर दिया गया है। कमांडोज़ जो इतना मेहनत करते हैं उनको भी डाइट मनी नोमिनल सी मिलती थी उसको भी दुगुना कर दिया है। वर्दी के रख-रखाव का जो भत्ता मिलता था वह काफी पुराने समय से कम मिल रहा था। उनकी मांग को कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार

में वर्दी भत्ता भी दुगुना कर दिया है। सिपाहियों की पदोन्नति की जहां तक बात है जैसे कि सिपाही से हवलदार बनना है तो सिपाही को 25-25, 30-39 साल हो जाते थे, रिटायरमैंट के नजदीक पहुंच जाते थे लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं हो पाती थी। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि सिपाही की 16 साल की सेवा पूरी होने पर वह आटोमैटिक हवलदार बन जाएगा। इस तरह से अगर उसके लिये यह इन्सैंटिव रहेगा तो उसमें काम करने की जान रहेगी। बी-1 कोर्सिज को हमारी सरकार ने दोबारा चालू कर दिया है ताकि जो पढ़े-लिखे और छोटी उम्र के सिपाही हैं वे आगे आएं और भर्ती होने के पश्चात् जल्दी प्रोमोशन कोर्सिज में जाकर प्रोमोशन ले सकें। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य शेर सिंह जी बोल रहे थे कि जिस तरह से जो मिलट्री है, पैरा मिलट्री है, बी०एस०एफ० है या सी०आर०पी०एफ० है उन में शहीद होने वाले नौजवानों को कम्पनशेसन मिलता है उसी तरह से अगर सिपाही प्रदेश के लिये या देश के लिए कुर्बान हो जाएं तो उनको भी कम्पनशेसन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मिलट्री में, बी०एस०एफ० में या सी०आर०पी० एफ० में किस हिसाब से कम्पनशेसन मिलता है यह तो मुझे मालूम नहीं है। इस बारे में आई०जी० साहब को ही ज्यादा पता होगा। लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो सिपाही किसी बदमाश या क्रिमिनल टाइप लोगों के साथ लड़ते हुये शहीद हो जाएंगे उनके परिवारों को 5 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी। इस तरह से प्रदेश के लिए कुर्बान होने वाले सिपाही को यह राशि मिलेगी। हमारी सरकार आने से पहले यह अनुदान राशि नहीं दी जाती थी। हमने सिपाहियों के लिये यह इन्सैंटिव किया है। इसके अलावा जो सिपाही प्रदेश के लिए शहीद हो जाएंगे उनकी विधवाओं को उस सिपाही की 58 साल की उम्र पूरी होने तक तनख्वाह के बराबर पैन्शन मिलती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, पहले पुलिस वैल्फेयर के लिए जो वैल्फेयर फण्ड होता था उसमें पुलिस कर्मचारियों से फण्ड काटा जाता था लेकिन पिछली सरकारों ने यह जमा नहीं कराया । यह मैचिंग ग्रांट स्कीम हमारी सरकार ने ही पहले शुरू की थी लेकिन बीच में बन्द हो गई थी। वर्तमान सरकार ने पुलिस कर्मचारियों के 45 लाख रुपये फिक्स में जमा कराये हैं। इसके अलावा रिजर्व में तैनात पुलिस कर्मचारियों को पहले मकान भत्ता नहीं दिया जाता था जबकि उनकी डयूटी ज्यादा हाई होती थी। उनसे मकान भी खाली करा लेते थे और मकान भत्ता भी नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार ने रिजर्व में तैनात कर्मचारियों का मकान भत्ता चालू किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पुलिस लाइन और एच०ए०पी० कैम्पस के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मियों के बिजली के रेट डोमैस्टिक आधार पर किये जो कि पहले नहीं थे। हिसार की पुलिस लाइन जो एशिया की नं० 1 पुलिस लाइन है जिसमें 700 से ज्यादा क्वार्टर हैं। इसके लिये जमीन हमारी सरकार के टाईम में एक्वायर हुई थी और बाद में निर्माण होते-होते पूरी हो गई थी। चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल दोनों की सरकारों ने कोई सुनवाई नहीं की थी और इस पुलिस लाइन में रहने वाले कर्मियों से बिजली के इंडस्ट्रीयल चार्ज लिये जाते थे और 4 रुपये कुछ पैसे प्रति वल्ब चार्ज किये जाते थे। हमारी सरकार के आने पर मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने कांफ्रेंस में जब यह जिक्र आया तो तुरन्त उनकी बिजली के डोमैस्टिक रेट कर दिये गये। कहां तो 4 रुपये कुछ पैसे चार्ज किये जाते थे और कहां आज सिर्फ 2 रुपये कुछ पैसे चार्ज होते हैं। इस तरह पुलिस कर्मियों का मोरल हाई-अप करने के लिये यह सब कुछ करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जो कोताही करता है, उसके खिलाफ सरकार पूरी कार्यवाही करती है। जिसका जैसा कसूर होता है उस हिसाब से कार्यवाही करते हैं। अगर किसी को ट्रांस्फर करने की आवश्यकता होती है तो उसका ट्रांस्फर किया जाता है, किसी को सस्पेंड करना होता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है, किसी के खिलाफ डिपार्टमैंटल इंक्वायरी करनी होती है तो उसके खिलाफ डिपार्टमैंटल इंक्वायरी करते हैं। किसी के खिलाफ यदि पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज करवानी होती है तो उसके खिलाफ एफ०आई०आर० भी दर्ज करवाते हैं।

[श्री सम्पत सिंह]
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नोटिस में लाना चाहूंगा कि शराब बन्दी के दौरान तकरीबन एक लाख के करीब केस हुए थे। उनमें से हमने 48664 माईनर केस वापस लेकर लोगों को इन्सेन्टिव भी दिया है। इन केसों में हमारे 17-18 साल के माईनर बच्चे थे। वे 50-100 रुपये की दिहाड़ी के चक्र में आकर गलत काम में फंस गए थे। सरकार ने इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुये कि वे गल्त रास्ते पर न जाएं उनके केस वापिस लिए हैं। जो बड़े-बड़े देशद्रोह के जुर्म कर जाते हैं वे बच जाते हैं तो फिर हम इन नादान बच्चों को क्यों नहीं माफ कर सकते ? इसलिए हमने 48664 केस वापस लेकर इन बच्चों को राहत प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, जो थोक के व्यापारी थे जिनको संरक्षण मिला हुआ था उनके केस वापस नहीं लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ जांच के लिए सिटिंग जज का एक आयोग बैठाया गया है जो इन केसों की सुनवाई कर रहा है। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक साथी ने बोलते हुए जिक्र किया कि अम्बाला के एक पैट्रोल पम्प मालिक की हत्या कर दी गई। यह सही बात है कि उस पम्प मालिक की हत्या हुई है। यह व्यक्ति 8 तारीख को 9.30 बजे पैट्रोल पम्प पर गया था। यह पैट्रोल पम्प मालिक दयाल बाग, महेश नगर का था, जब वह अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके न आने पर अगले दिन सुबह रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बाद में 9-3-2000 को उसकी डैड बाडी मिली। जिस एरिया से वह गायब हुआ और जिस एरिया में उसकी डैड बाडी मिली उन दोनों एस०एच०ओ० के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। सरकार कातिलों को ढूंढने के पूरे प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कैदियों के हिसार जेल से भागने की बात कही गई। मेरे लिए यह कहना कि पहले भी तो कैदी भागते रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सन् 1996 में 14 कैदी, 1997 में 12 कैदी, 1998 में 19 कैदी, 1999 में भी 22 कैदी जेल से फरार हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हिसार जेल से चार कैदी फरार हुए थे। उनमें से तीन को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक कैदी जो बचता है उसको भी पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। उसकी तफतीश चल रही है, उसको बताना अब ठीक नहीं होगा। भागने वाले कैदियों के सम्बन्ध पोलिटिकल लोगों के साथ भी हैं। एक आदमी जो 302 के केस में जेल में बन्द है उसके भाई ने उसको जेल से छुड़वाने के लिए यह ड्रामा किया और उसे राजनैतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है। यदि मैं अभी इन सारी बातों का जिक्र कर दूंगा तो फिर जांच प्रभावित होगी। जब जांच पूरी हो जायेगी तो उस वक्त सारे तथ्य हम लोगों के सामने रख देंगे। साल्हावास क्षेत्र के बारे में अनिता यादव जी ने भी जिक्र किया कि वहां पर कोसली थाने में जो घटना घटी थी उसमें सिर्फ एक महिला को ही गिरफ्तार किया गया है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जितने भी उस केस में दोषी थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन लोगों से चार देसी पिस्तौल, कारतूस और कुछ दूसरे हथियार प्राप्त किए गए हैं। अनिता यादव जी ने जिक्र किया कि साल्हावास में वोट डालने के नाम पर औरतों को धमकाया जा रहा है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने रिवाड़ी और झज्जर जिले से रिपोर्ट मंगवाई है। वहां पर इस तरह की कोई शिकायत किसी थाने में दर्ज नहीं हुई है। आज तो लोगों को इतनी छूट दी हुई है कि यदि किसी को कोई धमकाता है तो भी उसकी शिकायत थानों में दर्ज होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। (विघ्न) इस तरीके से हम इस पर काबू पा रहे हैं इस पर कंट्रोल कर रहे हैं। स्पीकर सर, हम पब्लिक इन्वाल्वमैंट भी करते हैं जैसे पुलिस की कान्फ्रैंस की बात है, उसमें मुख्य मंत्री जी भी जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ओपन दरबार लगाते हैं खुला दरबार लगाते हैं। खुले दरबार में जहां पब्लिक ग्रिवैंसिज आती हैं वहीं पब्लिक की तरफ से सुजैशन्ज भी आते हैं। अगर सरकार रिसपोन्सिव हो, सरकार अगर असैसिबल हो तो स्वाभाविक है कि काम ठीक चलता

रहेगा। सरकार अगर रिसपोंसिव न हो, असैसिबल न हो तो गड़बड़ होती है और एक गैप आ जाता है। पहले तीनों चीजों में कमियों की वजह से गैप आ गया था but to-day Government is very much responsive, responsible and accessible. इन वजहों से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम क्राईम पर जरूर काबू पा लेंगे। इसके साथ ही सिंचाई विभाग का जिक्र आया। मैं इस बारे में दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा बाकी तो एस०वाई०एल० और दूसरे इशूज़ पर मुख्यमंत्री महोदय जब जवाब देंगे उस समय बता देंगे। स्पीकर सर, जहां तक हरियाणा प्रदेश में सिंचाई का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी है। इस कमी का मेन रीज़न एस०वाई०एल० का कम्पलीशन न होना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे लेकिन हमारी तरफ से पूरे प्रयास किये जा रहे हैं, चाहे वह डब्ल्यू०आर०सी०पी० का प्रोजैक्ट है चाहे भाबार्ड का है और चाहे स्टेट की योजनाएं है। वर्ष 1998-99 में 258 करोड़ रुपये खर्च किये गए, वर्ष 1999-2000 में 317 करोड़ रुपये खर्च किये गए और वर्ष 2000-2001 में अभी 440 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। स्पीकर सर, इस तरह से हम पैसा बढ़ा रहे हैं ताकि इनकी मॉडर्नाइज़ेशन हो सके। इसी तरह से कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है तथा रिपेयर वगैरह हो सकती है और नहरों की सफाई का जहां तक सवाल है वह भी करवाई गई है। टेल एण्ड के बारे में मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि सिंचाई में केवल मात्र पान्साली के आंकड़ों का न माना जाए बल्कि बाकायदा वहां पर एक रजिस्टर रखवाया जाए ताकि वहां पर जो सरपंच, नम्बरदार और टेलएण्डर के बैनिफिशरीज़ हैं वे उस पर दस्तखत कर सकें। अगर ऐसा होगा तभी इस बात को माना जाएगा। स्पीकर साहब, इस तरह से पब्लिक की डायरैक्ट इन्वॉल्वमैंट होती है और ऐसे मामलों में पब्लिक का इन्वॉल्वमैंट होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, चाहे हम अपने हैडवर्क्स बना लें। हमने यमुना के ऊपर निर्माण कर लिया लेकिन जब तक इसकी कैपेसिटी न बढ़े तब तक इसका फायदा नहीं हो सकता है। इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, यमुना नहर में इसको जोड़ने के लिए एक नई डब्ल्यू० जे०सी० लिंक चैनल का निर्माण किया जा रहा है और अब इस तरह से 20 हज़ार क्यूसिक पानी इसमें और आ जाएगा। पानी आ ही नहीं जाएगा बल्कि अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है कि हम इसको पूरा कर चुके हैं। (**इस समय मैजें थपथपाई गई**) स्पीकर सर, इसी तरह से हुड्डा कॉम्पलैक्स था मेन हाईड्रोलिक प्रोजैक्ट पर पहली सरकार ने काम नहीं किया था। लेकिन हमने ये छोटे-छोटे काम कर दिये हैं और अब इनको पूरा कर लिया गया है। पथराला बांध का काम भी चल रहा है और नवम्बर, 2001 तक पूरा हो जाएगा। पिछली सरकार ने ओटू वियर को तो छेड़ा ही नहीं था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका फाउंडेशन रख दिया है और इस पर काम शुरू हो चुका है तथा अक्तूबर, 2001 तक यह पूरा हो जाएगा। स्पीकर सर, इसी तरह से ऑगुमैंटेशन नहर का पुनर्वास जरूरी था। इसकी कैपेसिटी पहले 2000 क्यूसिक थी, इसका पुनर्वास हो चुका है और इसकी कैपेसिटी 4500 क्यूसिक रिस्टोर कर दी गई है। स्पीकर सर, इसी तरह से भाखड़ा मेन नहर का जिक्र आया। नरवाना ब्रांच और बी०एम०एल० की कैपेसिटी की रिस्टोरेशन के लिए काम चल रहा है और अब तक 16 करोड़ 5 लाख रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। (विघ्न) यह 10 करोड़ नहीं है। स्पीकर सर, इसी तरह से हम पंजाब सरकार के साथ फिर से इसको टेक अप कर रहे हैं ताकि जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर सकें। इसी तरह से रेजिंग ऑफ बी०एम०एस०कैनाल की बात है इसका 92.25 किलोमीटर तक का काम हो चुका है और 49.82 किलोमीटर रह गया है। जहां तक नरवाना ब्रांच की रेजिंग का सवाल है इसका 33.27 किलोमीटर तक

15.00 बजे

काम हो चुका है और 15.74 कि० मी० काम रह गया है। इसके लिए हमने पंजाब सरकार को खुले मन से कह रखा है कि पैसे की कमी हम नहीं आने देंगे। आप जल्दी से जल्दी इस काम

[श्री सम्पत सिंह]

को करें ताकि इसकी कपैसटी को रैस्टोर किया जा सके। जिस बात के लिए कैप्टन साहब चिन्तित हैं कि साऊदर्न हरियाणा में और पानी जाए तो कैप्टन साहब हम इस काम पर लगे हुए हैं। इसी तरह से यहां पर कुछ बातें और भी उठाई गई हैं। स्पीकर सर, ड्रेनेज का जो बर्क है इस पर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने प्रोजैक्ट बना लिया है। वर्ल्ड बैंक की टीम पिछले दिनों आई थी उनके साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। हम बाकायदा लोन को सैंक्शन करवा कर मास्टर प्लान पर काम शुरू करवाएंगे। स्पीकर सर, धर्मबीर जी ने तोशाम एरिया की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का जिक्र किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 20 सालों में इसकी एफीसिएंसी में गिरावट आई है और कपैस्टी कम हुई है। मैं इनकी इत्तलाह के लिए बताना चाहता हूं कि हमने इसमें काम के लिए भी पैसा सैंक्शन करवाया है और स्कीमें एप्रूव हो चुकी है। नाबार्ड से आर०आई०डी०एफ०5/1 स्कीम के अण्डर हम इसमें खर्च कर सकते हैं। इन्क्रीज कैपेसिटी ऑफ पॉवर हाउस नम्बर 1 टू 5 सिवानी कैनाल सिस्टम 3 करोड़ 18 लाख 69 की स्कीम है, इन्क्रीज कैपेसिटी ऑफ पॉवर हाउस नम्बर 1 टू 2 निगाना कैनाल सिस्टम की 1 करोड़ 8 लाख की स्कीम है, इसी तरह से इन्क्रीज कैपेसिटी ऑफ पॉवर हाउस गुजरानी माईनर आर०डी० 28 यह स्कीम भी 45 लाख की मंजूर हो चुकी है, इन्क्रीज कैपेसिटी ऑफ पॉवर हाउस नम्बर 1 टू 7 जूही कैनाल की 99 लाख की स्कीम पास हो चुकी है। इसके इलावा स्कीम अप्रूवड अण्डर आर०आई०डी०एफ० 5/2 में इन्क्रीज कैपेसिटी ऑफ लोहारू कैनाल एण्ड बड़वाला डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम ऑफ पम्प हाउस 4 करोड़ 27 लाख की स्कीम मंजूर हो चुकी है। इन्क्रीज कैपेसिटी ऑफ जे०एल०एन० कैनाल सिस्टम पम्प हाउस 2 करोड़ 75 लाख की, इन्क्रीज कैपेस्टी ऑफ महेन्द्रगढ़ कैनाल सिस्टम पम्प हाउस 2 करोड़ 12 लाख की स्कीमें भी हम मंजूर करवा चुके हैं। इन स्कीमों पर काम जल्दी करवा दिया जाएगा। इस बात के लिए आप चिन्तित थे और इसके बारे में सरकार भी चिन्तित है। आप बार-बार साऊदर्न हरियाणा की बात करते हैं कि यहां पर एस०वाई०एल० का पानी आधा था। कभी 1.8 समथिंग और कभी 1.7 समथिंग पानी का जिक्र किया जाता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम लगभग 1.668 एम०ए०एफ० पानी ले रहे हैं। 1271 क्यूसिक पानी आज के दिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पानी में से जहां तक साउदर्न हरियाणा का सवाल है वहीं नरवाना ब्रांच से पानी जाता है। आगे जो चैनल है उसकी कपैस्टी नहीं है। हम यह बहाना नहीं करते हैं कि हम इसलिए पानी नहीं दे रहे है। हम पानी दे रहे हैं और बी०एम०एल० से ही दे रहे हैं। बी०एम०एल० .908 एम०ए०एफ० और नरवाना ब्रांच से .75 एम०ए०एफ० पानी दे रहे हैं। कुल मिलाकर 1.668 एम०ए० एफ० पानी बनता है। इस प्रकार 1244 क्यूसिक भाखड़ा मेन लाईन से और नरवाना ब्रांच से 1027 क्यूसिक पानी दे रहे हैं यह टोटल 2271 क्यूसिक पानी बनता है। भाखड़ा मेन लाईन की कपैस्टी 10700 क्यूसिक है। पहले यह कपैस्टी 8600, 8700 क्यूसिक तक पहुंच गई थी लेकिन अब यह 9600 क्यूसिक तक पहुंच गई है। जब भाखड़ा मेन लाईन की कपैस्टी की रैस्टोरेशन हो जाएगी उस दिन इसकी कपैस्टी 11000 क्यूसिक हो जाएगी उसमें और पानी आ जाएगा। उसमें से आपको भी पानी मिलेगा। यह सरकार पूरी तरह से इस बारे में चिन्तित है। सर, ये बातें मैंने इनको नहर के बारे में बतानी थीं बाकि मुख्यमंत्री जी बताएंगे। इन्होंने ठीक फर्माया था कि सरप्लस स्टेट यू०पी० ने बनवा लिए थे, हरियाणा ने नहीं बनवाए हैं। उस बारे में पिछले दिनों फल्ड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इस मामले को हम टेकअप कर रहे हैं। (विघ्न) इसी तरह से राम किशन जी सुन्दर ब्रांच की बात कर रहे हैं। रात में इन्होंने टेलीफोन किया कि पानी की दिक्कत है कमी है तो मैंने यह कहा था कि हम आपकी यह कमी दूर करवाएंगे। हम इस बारे में सैशन के बाद इंजीनियर्ज की मीटिंग बुलाएंगे। यह ठीक है कि बवानीखेड़ा हल्के के बीस-बाईस गांवों में वास्तव में पानी की दिक्कत

है। हालांकि चौधरी बंसी लाल जी उस जिले की नुमाइंदगी करते रहे हैं लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं हम ध्यान देंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ। अभी यहां पर जिक्र आया कि जैनरेशन के जो प्रोजैक्टस थे जिन पर आलरेडी काम चल रहा था, उनको छोड़कर सरकार ने किसी नये प्रोजैक्टस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि जैनरेशन की यूनिटस एक दिन में तैयार नहीं होती है इनको पूरा होने में 6 या 7 साल लग ही जाते हैं क्योंकि कई बार कोल वालों से टाईअप नहीं हो पाता है, कई बार रेलवे वालों से टाईअप नहीं हो पाता है और कई बार फाईनैंसिज फंडिंग की भी दिक्कत आती है। इस तरह से कई बार इन चीजों की कमी हो ही जाती है। आप यमुनानगर के पॉवर प्लांट को ही देख लें सारी सरकारें चली गयीं। भजन लाल जी भी इसको बनाकर चले गए और बंसी लाल जी भी इसको बना कर चले गए। स्पीकर सर, इस प्लांट की पहले हमने सैंक्शन करवायी थी और लैंड एक्विजिशन का काम भी किया था, कुछ वर्क्स भी करवाए थे तथा कुछ क्वार्टर वगैरह भी बनवाए थे लेकिन बाद में कुछ काम नहीं हुआ। अब हमने अपनी सरकार आने के बाद उसको दोबारा टेकअप किया है। ग्लोबल लेवल पर टैंडर्ज इंवाइट किये गये हैं लेकिन इन चीजों में टाईम लगेगा। परन्तु अगर एक काम पूरा न हो और यदि दूसरे के लिए टैंडर इन्वाइट करें तो यह ठीक नहीं होगा। पॉवर जैनरेटिंग कम्पनीज तो लिमिटेड ही हैं। पहले वाले टेकअप किए हुए ही काम पूरा करवा पाएं तो यह ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में कोल हैड के ऊपर एक पॉवर प्लांट बनना है। हरियाणा सरकार ने उससे 500 मैगावाट बिजली लेने के लिए साईन किए हैं क्योंकि कोल हैड से जो पॉवर बनेगी वह चीप पड़ेगी। यदि हम कोल लेकर आएं, मिट्टी लेकर आएं और उसके बाद बिजली पैदा करें तो वह मंहगी पड़ेगी। यदि वहीं से लाईन के थ्रू बिजली लाते हैं तो उसमें लौसिज कम हो जाते हैं। इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि जो ओन गोइंग प्रौसैस हैं उन पर ही काम किया जा रहा है और नये प्रौजेक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर सर, कुछ ऐसे सौदे हैं जिन पर ऐसे ऐग्रीमैंट हो गये हैं जिनसे हमारे इंट्रस्ट धीरे-धीरे सेक्रीफाइज होते हैं। चौधरी बंसी लाल जी बैठे हैं ये बार-बार कहते थे कि 110 मेगावाट की पानीपत थर्मल प्लांट की जो चार यूनिट्स हैं उनकी साल के अंदर अंदर रि-फर्निशमैंट पूरी हो जाएगी और इतने लाख यूनिट बिजली बढ़ जाएगी। जब एक यूनिट पूरा करवाना था और उसका टारगेट 6 महीने का था तो उसमें तो डेढ़ साल हो गये हैं लेकिन वह पूरा नहीं हुआ क्योंकि उस कम्पनी के साथ ऐसी शर्तें रख दीं जिससे हमारे सारे इंट्रस्ट खत्म हो गये । आज वह कम्पनी हावी है और सरकार नीचे हैं लेकिन हमें तो उनके साथ भी निपटना पड़ेगा। इस तरह से बाकी तीन यूनिट तो अभी अलग ही हैं क्योंकि अभी तो एक यूनिट ही पूरी नहीं हो पा रहा है। उन तीन यूनिटस की जो रि-फर्निशमैंट है उनमें अभी टाईम लगेगा। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पॉवर जैनरेशन की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। ईवन प्राईम मिनिस्टर साहब से मिलकर, पॉवर मिनिस्टर से मिलकर मुख्यमंत्री जी उन दिनों पावर पैकेज लेकर आये थे जिन दिनों बिजली का घोर संकट आ गया था। इसी तरह से एंटा का पॉवर प्रौजैक्ट भी राजस्थान को दे दिया गया था लेकिन उसको भी हमने रैस्टोर करवाया है। इसी तरह से ईस्टर्न ग्रिड के बारे में भी बात की। लेकिन उससे बिजली लेने के लिए ट्रांसमिशन लाईनें लिंकेज नहीं हो पाती हैं इसलिए उससे बिजली नहीं मिली। इसी तरह से अन अलोकेटेड शेयर 19 परसैंट कर दिया गया था जिसको 27 परसैंट करवाया गया। इस तरह से अपनी तरफ से तो हमने पूरा प्रयास किया है। इस तरह से गवर्नमैंट पावर के बारे में पूरी तरह से जागरुक है विशेषकर ऐसे हालात में जब बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई जबकि खेती तो निर्भर ही पानी और बिजली पर है। अगर बरसात हो जाती है तो बिजली की कमी आधी रह जाती है और बिजली की खपत नहीं होती लेकिन यदि बरसात नहीं हुई तो पावर का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना पड़ेगा। but the

[श्री सम्पत सिंह]

availability of power will increase at the cost of domestic consumption or at the cost of commercial houses or at the cost of industriares.

इन सब की कोस्ट पर हमें फार्मर्ज को पावर देनी पड़ी बाकी क्षेत्रों में हमें कट करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, हर आदमी इस बात को ऐप्रीशिएट करेगा कि जीरी की पकाई का काम और गेहूं की बुआई करवाने का काम इस सरकार ने किया है। अगर पावर नहीं होती तो यह काम नहीं हो सकता था। लेकिन पावर दी गयी। स्पीकर सर, इसके आंकड़े में सदन को बताना चाहता हूं। अगस्त, 1998-99 को जो पॉवर दी गयी वह 422 लाख यूनिट थी लेकिन इस बार हमने 1999-2000 को इसी महीने में 488 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई की यानी 66 लाख यूनिट बिजली महीने में फालतू दी गयी। सितम्बर के महीने में 378 लाख यूनिट बिजली दी गयी थी लेकिन उसी कोरसपोंडिंग महीने में हमने 106 लाख यूनिट बिजली फालतू दी। इसी तरह से अक्तूबर के महीने में 316 लाख यूनिट बिजली दी गयी थी लेकिन हमने 378 लाख यूनिट बिजली दी यानी 82 लाख यूनिट बिजली फालतू दी। नवम्बर के महीने में 335 लाख यूनिट बिजली दी थी लेकिन हमने इसी महीने में 379 लाख यूनिट बिजली दी यानी 44 लाख यूनिट बिजली फालतू दी। इसी तरह से दिसम्बर में 26 लाख , जनवरी में 32 लाख, फरवरी में 47 लाख फालतू बिजली दी गयी और मार्च में एक सौ लाख यानी एक करोड़ यूनिट बिजली फालतू दी गयी है। स्पीकर सर, ओन एन एवरेज यह हर महीने 58 लाख यूनिट बिजली पड़ जाती है तभी तो रिकार्ड तोड़ फसल पैदा हो पायी है वरना किसान तो मर जाता। अगर उसको बिजली न मिलती तो उसकी जीरी की पकाई और गेहूं की बुवाई नहीं होती। इसी तरह से जहां तक जैनरेशन की बात है जैसे फरीदाबाद का एन०टी०पी०सी० का गैस बेस्ड पावर प्लांट है उसके दो यूनिट 143-143 मेगावाट के जनरेशन में आ गए हैं और तीसरी जो यूनिट वह जून तक जेनरेशन में आ जाएगी। इनके आने से 60-65 लाख यूनिट पावर बढ़ गई है तीसरी यूनिट के आने से 30-35 लाख और बढ़कर लगभग एक करोड़ यूनिट यानी 100 लाख यूनिट पावर हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यह जो एन०टी०पी०सी० का गैस बेसड थर्मल पॉवर प्लांट है उसमें स्टेट का शेयर कितना है ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद के बारे में भी जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पानीपत की पांचवीं यूनिट का काम चौधरी देवीलाल जी ने शुरू और पूरा करवाया था उस पर जो पी०एल०एफ० है वह 100.1 परसैंट है यह अपने आप में एक रिकार्ड है मेहनत न करते तो यह कैसे आता ? यह यूनिट 109 दिन चला है जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है पहले यह 63 दिन चला था इसी तरह से ऑयल कंजम्पशन है that was recorded at .26 per KWH, i.e. is the lowest. जहां तक छठीं यूनिट का सवाल है यह दिसम्बर, 2000 तक पूरा हो जाएगा और इससे 50 लाख यूनिट पॉवर और बढ़ जाएगी। जहां तक फरीदाबाद का सवाल है उसका भी रिकार्ड पी०एल०एफ० लिया है यह 70.84 लिया है और अक्तूबर, 1999 में लिया है which is the highest so far. ऑयल कंजम्पशन 3.35 एम०एल० के डब्ल्यू०एच० है जो कि लोवेस्ट है और इससे 20 करोड़ का फायदा हुआ है। तेल की लागत कम हो तो उससे सेविंग होना स्वाभाविक है। इसी तरह से जो सब-स्टेशन हैं, लाइन के काम हैं सभी पर काम चल रहा है। दक्षिण हरियाणा का जिक्र आया था। रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ सबसे ज्यादा डैजर्ट का इलाका है उसमें जहां तक बिजली की सप्लाई का सवाल है मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ कि अक्तूबर, 1998 में वहां 569 लाख यूनिट बिजली दी गई थी और हमारी सरकार के समय में जुलाई 1999 में 697 लाख यूनिट दी गई है। अगस्त, 1998 में 592 लाख यूनिट पॉवर दी गयी थी

जबकि अगस्त 1999 में 672 लाख यूनिट बिजली दी गई। सितम्बर 1998 में 487 लाख यूनिट बिजली दी गयी थी जब कि हमारे समय में सितम्बर, 1999 में 704 लाख यूनिट यानि की लगभग दुगुनी बिजली सप्लाई दी गई है। हमने इतनी पॉवर दक्षिण हरियाणा को दी है अक्तूबर, 1998 में 569 लाख यूनिट दी थी अक्तूबर, 1999 में 820 लाख यूनिट बिजली दी गई यह भी लगभग डयौढ़ी है नवम्बर, 1998 में 752 लाख यूनिट दी गई थी और हमने नवम्बर, 1999 में 1082 लाख यूनिट बिजली दी है। इसी तरीके से दिसम्बर, 1999 जनवरी, 2000 और फरवरी, 2000 में भी फालतू बिजली दी गई है। हमारे माननीय साथी ने फरीदाबाद का जिक्र किया था। जहां तक फरीदाबाद का सवाल था सिस्टम न होने की वजह से पॉवर नहीं दे पा रहे थे अब कुछ तो लिंकेज कर दिया गया है और कुछ हो रहा है वहां से जो टोटल पॉवर आएगी वह फरीदाबाद जिले को दी जाएगी। इसके अलावा अब तक जो काम हमने किये हैं वह आपको बताना चाहता हूँ। पॉवर स्टेशन की लिंकेज हुई है उससे 400 के०वी० समयपुर और 200 के०वी० बल्लभगढ़ को लिंक कर दिया गया है। Haryana State has already commissioned new 220 KV sub-station at Palla. इसी तरीके से दो ट्रांसफार्मर 100 एम०वी०ए० के इंस्टाल कर दिये गये हैं और इनसे पॉवर मिलनी शुरू हो गई है और इनसे 10 परसैंट का असर पड़ा है। इसी तरह से एच०वी०पी०एन० का 220 के०वी० का सब-स्टेशन बादशाहपुर से पाली और पाली से समयपुर का तैयार हो गया है और इस सब-स्टेशन से यह लिंकेज पूरा हो जायेगा। जैसा कि चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि 16 जुलाई को उन्होंने 516 लाख यूनिट की हाईएस्ट सप्लाई दी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 16 जुलाई को 472.94 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई दी गई थी और 25-9-1999 को सबसे ज्यादा बिजली 518.40 लाख यूनिट दी गई थी। जहां तक वर्ल्ड बैंक के लोन की बात है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह लोन बन्द होने जा रहा है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से बातचीत चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय से चल रही है और चौधरी भजन लाल जी की जब सरकार थी उस समय 6-7 करोड़ रुपये कंसल्टेशन पर खर्च किये गये थे। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय हरियाणा सरकार, हरियाणा बिजली बोर्ड और वर्ल्ड बैंक के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि हरियाणा बिजली बोर्ड की कम्पनी बनाई जाएं। जिसके कारण हरियाणा बिजली बोर्ड की तीन कम्पनियां जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन बनाई गई। जहां तक लोन की बात है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें लगाई थीं और इस बारे हर सरकार की भारत सरकार के माध्यम से वर्ल्ड बैंक से बातचीत होती रही है। बर्ल्ड बैंक ने क्लीयर-कट यह बात कही थी कि इन कम्पनियों को ज्वायंट वैंचर को देना पड़ेगा जिसका सीधा मतलब है कि निजी हाथों में इनका काम जायेगा। इस सरकार ने अभी तक उस एग्रीमेंट पर साईन नहीं किया है। क्योंकि सिर्फ बिजली की सप्लाई की क्षमता बढ़ाने का सवाल नहीं है। सवाल उपभोक्ता का भी है उसकी समस्या को भी सरकार को देखना पड़ेगा। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा उस भार को तो उपभोक्ता वहन नहीं कर पायेगा। हमने किसी प्रोजैक्ट का काम नहीं रोका है और न ही रुकने देंगे।

श्री बंसी लाल : टैरिफ तो रेगूलेटरी कमीशन ही बढ़ायेगा। इस बात को वर्ल्ड बैंक भी मानता है।

श्री सम्पत सिंह : सर, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये अंडर कंसीडेशन हैं। आज हम कोई ऐसे फैसले न लें जो कल को हमें वापिस लेने पड़ें और कंज्यूमर्ज के इंट्रस्ट में न हो, यह अच्छा नहीं है। हम बिजली के बारे में कंज्यूमर्ज से, एम्पलाइज से, इंजीनियर्ज से और भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उड़ीसा में बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, हम उसको भी देख रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की टीम इस महीने के लास्ट-वीक में आ रही है, उस समय उनसे टर्म्स एण्ड कंडीशंज के बारे में बातचीत की जाएगी। हम

[श्री सम्पत सिंह]

चाहते हैं कि रिफोरमिंग और रिस्ट्रक्चरिंग हों। हम इस तरफ ध्यान देंगे कि टर्म्ज एण्ड कंडीशंज ऐसी हों जिसमें स्टेट का इंट्रस्ट हो और विशेषकर कंज्यूमर्ज का इंट्रस्ट प्रोटैक्ट हो।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो 240 करोड़ की पहली किस्त दी है उसमें से अब तक कितना रुपया आ चुका है ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी किसी माननीय सदस्य ने यहां पर जिक्र किया था कि जहाजगढ़ का 33 के०वी० का सब-स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि उस सब-स्टेशन का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और वह पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा होने में अभी टाइम लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वह काम 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसी तरह से बागबानी के बारे में शायद धर्मबीर जी ने कहा कि एग्रीकल्चर सैक्टर की बिजली लाइनों पर 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली किसानों को दे दें। सर, बागबानी क्रोप्स कमिशयल क्रोप्स है और इसका खाद्यान्न उत्पादन से कोई वास्ता नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा था कि आप एक दिन का व्रत रखिये क्योंकि खाद्यान्न के उत्पादन में कमी थी। ज्यो-ज्यों किसानों को प्रोत्साहन दिया गया त्यो-त्यों खाद्यान्न उत्पादन बढ़ते गए इसलिए बागबानी में 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देना सम्भव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी का क्या जिक्र करूं। इनके समय में जिस आदमी ने बिजली के कनैक्शन ले रखे थे और बिल की पेमैंट नहीं की थी उन्होंने उनके कनैक्शन काटने की बजाये पूरे ट्रांफार्मर को ही बदलना छोड़ दिया था जब कि होना यह चाहिए था कि इनको उन्हीं के कनैक्शन काटने चाहिएं थे जिन्होंने बिजली के बिल पेमैंट नहीं किये थे। मान लो ट्रांसफार्मर जल गया और उस ट्रांसफार्मर से 100 कंज्यूमर्ज बिजली लेते हैं उन 100 में से जिन 5 आदमियों ने बिजली के बिल भर दिये हैं, उनका क्या कसूर है ? इसलिये हमारी सरकार ने आते ही उन जले हुए ट्रांसफार्मर चाहे उन पर कोई भी कांड रहा हो, चाहे दर्जनों किसानों को मारा गया हो, को बदलवाने का काम किया।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अब ये किसानों के पिछले बिल माफ करेंगे या वसूल करेंगे ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि बिल माफ करने की बात तो हमने कही ही नहीं है। हम फ्रैश मैण्डेट लेकर आए हैं, सरकार फ्री पावर देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप लोग हमारा मैनिफैस्टो देख लें, आप हमारे स्पीचिज देख लें। हमने पंजाब से एक्सपैरीमैंट लिया है, पंजाब फ्री बिजली, पानी देकर अब पछता रहा है। आज हम आपके सामने बैठे हैं, हम फ्रैश मैण्डेट लेकर आए हैं, यह मैण्डेट फ्री पावर देने का नहीं है। हम पावर की क्वालिटी लेकर आए हैं। हम पूरी बिजली देंगे, बिजली की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हर सैक्टर के अन्दर पावर पूरी दी जाएगी। इस बारे में हम मैण्डेट लेकर आए हैं इसलिए फ्री पावर देने की इस सरकार की कोई स्कीम नहीं है। हमारी सरकार ने आते ही लोगों के घरों में रोशनी की, उनके ट्यूबवैलों में रोशनी की। आज जहां तक बिजली के कनैक्शन काटने की बात है तो इंडीविज्युल जिसने बिजली के बिल नहीं भरे उनके कनैक्शन काटने की बात तो ठीक है लेकिन पूरे ट्रांसफार्मर न बदलने से तो कोई बात नहीं बनती, यह तो उन लोगों के साथ अन्याय था जिन्होंने अपने बिलों की पेमेंट की थी।

श्री दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर्ज बदलने की क्या नीति बना रहे हैं ?

श्री सम्पत सिंह : जैसे ही कोई शिकायत आती है ट्रांसफार्मर्ज बदल दिये जाते हैं चाहे वहां पर किसी ने बिल भर रखे हों या न भरे हों। क्योंकि बिल भरना अलग चीज है, ट्रांसफारमर्ज बदलना अलग चीज है। जिस व्यक्ति ने बिजली का बिल न भरा हो उनके कनैक्शन काट देने चाहिएं लेकिन ट्रांसफारमर्ज न बदलना ठीक बात नहीं है, यह तो अथोरेटियरन रीजीम की बात होती है इसलिए पापुलर गवर्नमैंट ऐसा नहीं करती। यदि कोई सरकार ऐसा करने की कोशिश करती है तो लोग उनको जमीन दिखा देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने बिजली के बिल की पेमैंट नहीं की थी इनको उनके बिजली के कनैक्शन काटने चाहिए थे, हमारी सरकार ने भी काटे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बिल पे नहीं करेगा उसके कनैक्शन तो काटेंगे ही, इस तरह से कोई फ्री बिजली नहीं ले सकता।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो यह मैण्टेड लेकर आए हैं, वह ठीक है लेकिन इससे पहले ये बोलते रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे इसलिए उस समय लोगों ने बिल नहीं भरे थे। अब वह बिल की राशि 1-1, डेढ़-2 लाख रुपये हो गई और किसान वह बिल दे नहीं सकता। अब यह सरकार ऐसे किसानों के लिए क्या समाधान करेगी ? किसान आज वह बिल नहीं दे सकता। इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जिन लोगों ने बिल नहीं भरा उनको हमारी सरकार जेलों में नहीं डाल रही बल्कि उनको प्रोत्साहित करके, उनका सर चार्ज माफ करके उनसे यह पेमैंट लेने की कोशिश कर रही है। स्पीकर सर, इसी तरह से ट्यूबवैल्ज कनैक्शंज का जिक्र आया था। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार के वक्त में ही नहीं बल्कि 1991 के बाद से शायद एक-दो ट्यूबवैल कनैक्शन किसानों को दिये होंगे। हमारी सरकार ने स्कीम बनाई है कि इसी साल 9850 ट्यूबवैल्ज कनैक्शन दिये जाएंगे। इन पर 23.58 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इसके अतिरिक्त स्पीकर सर, हमारी सरकार ने 30,000 ट्यूबवैल्ज कनैक्शंज के लिए लोन एप्लाई किया है। यह लोन मिलने पर 30,000 ट्यूबवैल कनैक्शंज और देंगे। स्पीकर सर, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों और दूसरे कंजूमर्ज पर ध्यान दे रही है। (विघ्न)

श्री धर्मबीर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के तोशाम में सिंगल फेस की मोटर थोड़ी सी बिजली से ही चल जाती है। क्या वहां पर सिंगल फेस की मोटर्ज को कनैक्शन दिया जायेगा ?

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं अपने माननीय साथी धर्मबीर जी को कहना चाहूंगा कि ये अपने हल्के की समस्या हमें लिखित में दे दें। हम उनको सुलझा देंगे। (विघ्न)

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के रिवाड़ी में 11 के०वी० के सब-स्टेशन लगने थे। उस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं कैप्टन साहब को कहना चाहूंगा कि हमने इनके किसी भी काम के बारे में ना नहीं की। यह काम भी कर देंगे।

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Chief Minister will speak.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यगणों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बड़ी ही गरिमामय ढंग से चर्चा की और यदि मैं यह कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि सभी सदस्यों ने इसकी सराहना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन के सभी सदस्यों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि पहली मर्तबा उन्होंने हरियाणा

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

विधान सभा के महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बड़े ध्यान से सुना। यह अपने आप में एक मिसाल है और इससे प्रदेश की ख्याति और छवि निखरी है। एक तरफ जहां मैं सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूं वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने सदन के हर सदस्य को पूरी तरह से यह छूट प्रदान की कि वह अपनी बात कह सके। यह पहला अवसर है कि एक दिन में 32 सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिला। इसी महान सदन में अध्यक्ष महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं इस पर आपसे पहले और लोग भी बैठते रहे हैं। जनता के रक्षार्थ अपनी बात कहने का हमने पूरा प्रयास किया लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार विदेश गया था। वहां पर किसी को छींक आ गई तो सुनने वाले ने उसे कहा कि "गोड ब्लैस यू" । लेकिन यहां पर पहले अगर किसी को छींक आ जाती थी तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, यह भी ठीक है कि जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिली। हमने उस वक्त कहा था कि यह सदन होगा, हमारे जैसे सदस्य भी होंगे। लेकिन सदस्यों के साथ अलोकतांत्रिक सदस्य नहीं होंगे और ऐसा ही हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमें यदि केवल मात्र बोलने का अवसर मिलता था तो सिर्फ श्रद्धांजलि समारोह में बोलने का अवसर मिल जाता था। हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने में तो छूट मिल जाती थी अन्यथा तो हम पर बहुत भारी अंकुश लग जाया करता था। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा अवसर है। आपने बहुत खुला समय दिया और यहां तक भी आपने कहा कि किसी सदस्य को अगर दोबारा भी बोलना है तो वह भी बोल सकता है। यह बात अलग है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने में अभी उनको समय लगेगा। विपक्ष की भूमिका निभाने में अभी उनको कुछ दिक्कतें और अड़चनें आई हैं क्योंकि बहुत से सदस्यों के लिये यह पहला अवसर था। स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली में अच्छे ढंग की नुक्ताचीनी भी की जाती है। हैल्दी क्रिटीसीज्म होनी चाहिए, यह प्रजातंत्र की मजबूत पहचान है और रचनात्मक सुझाव भी दिये जाने चाहिएं। यहां कुछ नये सदस्य आये हैं उनको ज्ञान नहीं है। वे शायद इस बार पूरी तरह से अपनी बात को बोल नहीं पाए। लेकिन मैं समझता हूं कि समय रहते वे सीख जाएंगे और विपक्ष के नेता उन्हें राहे-रास्ते लाने में काफी हद तक सफल होंगे। विपक्ष के नेता के सामने कुछ दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि उनकी पार्टी के नेता भी नये विधायकों में से एक हैं और उनके दिमाग में भी यह वहम् रहेगा कि वे पार्टी के नेता हैं और विपक्ष में सदन के नेता के दिमाग में यह रहेगा कि मैं सदन में विपक्ष का नेता हूं। टकराव की स्थिति स्वाभाविक है। शुक्र है कि अभी तक यह स्थिति प्रैस गैलरी तक सीमित है। परमात्मा करें कि सदन में ये लोग इस तरह का नज़ारा पेश न कर दें। प्रैस में विपक्ष के नेता पहले दिन जाकर ब्यान देते हैं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के जो प्रत्याशी चुनावों में खड़े हुए थे उनमें इतनों की जमानत जब्त हो गई और दूसरे दिन जा कर कहते हैं कि विपक्ष का नेता बनाने के लिए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मेरे नाम की तजवीज की थी। दूसरी ओर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा चुनावों के समय किलोई क्षेत्र में गए, रोहतक जिले में भी गये और सोनीपत जिले में भी गए उस समय तो वे यह कहकर वोट मांग रहे थे कि मैं मुख्य मंत्री बनने जा रहा हूं और किसी कीमत पर भजन लाल को नेता बनने नहीं दूंगा। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पार्टी का आन्तरिक मामला है। इस बारे में मुख्य मंत्री जी यहां व्याख्यान न करें तो अच्छे प्रजातंत्र के हित में होगा। ये भी इस पार्टी के सदस्य रहे हैं और इनको भी इसका काफी तजुर्बा है कि कौन पार्टी का नेता होता है और इसका फैसला कौन करता है। हमारी पार्टी की नेता सोनिया गांधी है यह सबको मालूम है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि यह इनकी पार्टी का आन्तरिक मामला है और मुझे किसी के आन्तरिक मामले में दखल देने की आदत नहीं है। मैं अनाधिकृत चेष्टा करने में विश्वास नहीं रखता हूँ लेकिन मैं इन दोनों नेताओं को बता देना चाहूंगा कि मैं और चौधरी सम्पत सिंह भी यहां बैठे हुए हैं। हमारी भी यही स्थिति थी। मैं पार्टी का अध्यक्ष था और सम्पत सिंह जी सदन में विपक्ष के नेता थे। मैंने बड़े हौंसले के साथ इस बात को तसलीम किया था और यह भी कहा था कि बाहर मैं नेता हूँ और सदन में सम्पत सिंह जी नेता हैं। मैं इनसे भी यही कह रहा हूं कि ये दोनों भी उसी सोच पर चलें और प्रैस लाबी में जाकर मुख्तलिफ या अलग किस्म की बात न कहें। अगर ये इस बात को सीख जाएंगे तो फिर इनका झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मुझे तो यही कहना था। अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि सदन में पहली मर्तबा इतना अच्छा माहौल कायम करने का जो प्रयास किया गया उसके लिये मैं जहां पूरे सदन की सराहना करूंगा वहां विपक्ष की और विपक्ष के नेता की भी सराहना करूंगा। यह एक अच्छी ट्रैडीशन है। हमारी तरफ से भरपूर प्रयास होगा कि सदन में इस तरह का माहौल बराबर बना रहे और हरियाणा प्रदेश का नाम अच्छे हिसाब-किताब से जाना जाए। यह ठीक है और वक्त की बात है कि जनतांत्रिक प्रणाली में प्रजातंत्र सर्वोपरि है, जनता की आवाज सर्वोपरि है लेकिन कई जगह उसके विपरीत बातें हो जाती हैं। मेरी कुर्सी पर चौधरी बंसी लाल जी बैठा करते थे हम तब भी बहुत कहा करते थे कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। ये उस समय कटाक्ष किया करते थे और कहते थे कि मैं यह कुर्सी छोड़ दूंगा मैंने कहा कि कुर्सी कोई नहीं छोड़ता । अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता की कुर्सी ऐसी चैन की तरह है जो कभी किसी के हाथ में चली जाती है तो कभी किसी के हाथ में। चौधरी बंसी लाल जी यहां पर कहा करते थे कि मैं आजीवन मुख्यमंत्री रहूंगा लेकिन जब हाउस में बहुमत सिद्ध करने का समय आया तो ये यहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए हों। उसके बाद अब ये दिखाई दिए हैं। ये विपक्ष की भूमिका में बहुत कम रहे हैं। ये वैसे तो हमारे बुजुर्ग हैं अगर यहां पर बैठे रहेंगे तो हम इनको ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये पहले रह चुके हैं उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत अधिक अन्तर आ गया है। यदि ये इस अन्तर को समझ जायेंगे तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा के अवसर पर बोलते हुये मैं कहना चाहूंगा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर नई सरकार द्वारा संविधान की मर्यादाओं को बनाये रखने तथा राज्य की समस्त जनता के कल्याण तथा समृद्धि के लिए कार्य करने की शपथ ली गई यह शपथ वहां ली गई ताकि हरियाणा प्रदेश को अच्छे रास्ते पर लाकर यहां की बहुमुखी प्रगति हम कर सकें। मैं समझता हूं कि इससे सही स्थान और कोई हो नहीं सकता था, यह मान कर हमें चलना भी चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस गरिमा को बनाये रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हम हरियाणा की जनता के प्रति जवाब देह हैं और रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता ने जो हमें सहयोग और समर्थन दिया है उसके लिए हम हरियाणा की जनता के आभारी हैं और जो वायदे हमने किए हैं उन पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम खरा उतरने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि यदि हमने गलत काम किये तो जो सामने बैठे भाईसों का हश्र हुआ है कहीं वह हश्र हमारा न हो जाये, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने की भरसक कोशिश करेंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हरियाणा के हितों पर किसी प्रकार की चोट न आने पाये।

अध्यक्ष महोदय, 24 जुलाई, 1999 को संयोगवश मुझे मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने का अवसर मिला। मैंने इन पिछले 7 महीनों में हर संभव प्रयास किया कि हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ जन

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

कल्याणकारी योजनाएं चला कर उनके माध्यम से हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाएं। हमने विकास के काम को गति देने की भरपूर कोशिश की है। हम यह मान कर चले कि जनता को कष्ट न हो इसलिए "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत हम जनता तक पहुंचे। सरकार स्वयं जनता के द्वार पर चल कर गई। इस कार्यक्रम के तहत 90 के 90 विधान सभा क्षेत्रों में हम गये और जितना संभव हो सका हमने वहां के लिए काम किये। मैं समझता हूं कि जो वायदे हमने किए उन सभी पर काम हुआ। कुछ सदस्य साथी कह रहे थे कि सरकार आपके द्वार प्रोग्राम सफल नहीं रहा। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि जहां-जहां पर भी हमने जो वायदे किए थे, वहां पर फौरन काम चालू करवाये। यहां पर बोलते हुए भाई नरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत इतनी घोषणाएं कर दी गईं कि वे सारी की सारी सिरे नहीं चढ़ पाईं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा कहना यह है कि शायद ही कोई ऐसी योजना या काम रहा हो जो सिरे न चढ़ा हो। नरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि वोट लेने के नाम पर सरकार ने ये काम करवाये हैं। वे स्वयं कह रहे थे कि कहीं पर गलियां पक्की हो रही हैं, कहीं पर स्कूलों के लिए कमरे बनवाये जा रहे हैं, कहीं पर सड़कों की मुरम्मत हो रही है और कहीं पर वाटर सप्लाई की स्कीमों पर काम हो रहा है। एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणाएं कर दी गईं लेकिन काम नहीं हुए और दूसरी तरफ स्वयं कह रहे हैं कि वोट लेने के नाम पर काम करवाये जा रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार विकास के कार्य कर रही है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि सरकार ने चुनावों के दौरान कार्य करवा कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया। भाई नरेन्द्र सिंह जी ने यहां पर बोलते हुए कहा कि चुनावों के समय सी०एम० साहब कह रहे थे कि अब तुम्हारे इलाके के लोगों को नौकरियां दी जाएंगी क्योंकि तुम्हारे एरिया के राव भान सिंह को एच०एस०एस०सी० (बोर्ड) का चेयरमैन लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, स्टाफ सिलैक्शन कमीशन का सिलैक्शन करने का अपना एक तरीका है। पहले वह परीक्षा लेता है और उसके बाद इन्टरव्यू आदि लेकर किसी पद पर किसी उम्मीदवार की सिलैक्शन की जाती है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। यदि सरकार काम नहीं करती तो उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि सरकार विकास के कोई काम नहीं कर रही। यदि सरकार विकास के काम करती है तो चुनाव आयोग को शिकायत की जाती है कि सरकार विकास के कार्य कर रही है जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। यह बात समझ में नहीं आती है कि जब सरकार विकास के कार्य करे तो फिर कोई शिकायत क्यों करे ? मेरे कहने का मतलब यह है कि काम नहीं करते तो कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती और अगर सरकार काम करती है तो चुनाव आयोग को शिकायत की जाती है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनकी तो आदत इस तरह है। इस बात को मैं समझता हूं क्योंकि इन्होंने तो कभी विकास के काम किए नहीं। चौधरी भजन लाल के नाम पर कितने ही पत्थर पड़े हैं। शायद अभी कुछ साथी कह रहे थे कि पत्थर उठा नहीं लेना। पत्थर इतने लगे हुए हैं कि उनकी संख्या ही हजारों में है। किसी भी हिस्से में चले जाइये आपको भजन लाल जी के नाम के पत्थर जरूर दिखाई देंगे। (विघ्न) एक नहीं, दो नहीं, सैंकड़ों, हजारों पत्थर लगे हुए हैं। चौधरी बंसी लाल जी भी इस बात से सहमत होंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी यह आदत नहीं है। हमारी एक सोच है कि हमने जो कहा है वही किया है। चौधरी बंसी लाल जी का एक तकिया कलाम है। ये कहा करते थे कि मेरा आदेश यूं चलता है जैसे 303 की राईफल से कारतूस चलते हैं। बंसी लाल जी, यही कहा करते थे ना, अभी इनकी कारतूस की टोपी शायद मिस हो गई है। (हंसी) मुझे इसका नहीं पता। (विघ्न) लेकिन हमने जो कहा है वही हुआ भी है।

पूरे हरियाणा प्रदेश में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे काम हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी को खुला निमंत्रण दे रहा हूँ। किसी कारण वश कहीं पर कोई काम अधूरा है तो आप लोग मुझे बताएं मैं उन कामों को पूरा करवाऊंगा। उसे पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, यह सोच किसी व्यक्ति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है किसी पार्टी विशेष के लिये नहीं है, हरियाणा प्रदेश के 6745 गांवों को विकास के कामों का बराबर अधिकार मिला है। हमारी एक सोच है, इस सोच में थोड़ा अन्तर यह हो सकता है कि जो क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता प्रदान करेंगे और मेरा ख्याल है कि इस मामले में आप सब लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे, हमें आपकी सहमति की भी आवश्यकता है क्योंकि कई क्षेत्र पता नहीं किस कारण वश विकास होने से रह गए होंगे। इस बारे में बात मैं फिर कभी समय आने पर बताऊंगा। हमने लोगों की बातों को सुना है और उनकी बातों को और कामों को पूरा करवाने का हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। स्पीकर सर, वृद्धावस्था पैंशन चौधरी देवी लाल के दिमाग की उपज थी। वे व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर इस बात को मान कर चलते हैं कि आदमी जब बूढ़ा हो तो चाहे वह कितना ही सम्पन्न क्यों नहीं हो, कुछ फर्क पड़ जाता है। यह कदम इसीलिए उठाया गया था। यह कदम आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने के लिए नहीं था। यह तो एक सम्मानित शहरी के लिए पैंशन थी। इस सम्मान पैंशन को हमने बढ़ाने का निर्णय किया है। माननीय साथी धर्मपाल जी बोलते हुये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कितने आंकड़े हैं, कितने लोगों को पैंशन मिली है या नहीं मिली है। स्पीकर सर, आज मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि 40-45 साल के लोगों ने पैंशन ले ली हो और मैं यह भी मान सकता हूं कि 70 और 80 साल के लोग भी बचे रह गए होंगे जिनको पैंशन नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है, लिखित रूप में दरख्वास्त दे दे सरकार 200 रुपये प्रति माहबार उसको पैंशन देगी, इस बात के लिए हम वचनबद्ध हैं। (विघ्न) **(इस समय मेजें थपथपाई गईं)** हम विकलांगों तथा विधवाओं को भी पूरी पैंशन देंगे यह हमारा फैसला है और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। समाज कल्याण के हिसाब से तो कई बातें और भी हैं। स्पीकर साहब, अनीता जी नयी सदस्या चुनकर आई हैं, इन्होंने एक जिक्र किया कि 5100 रुपये की धनराशि की जो योजना बनाई गई है वह ढोंग है, ढकोसला है क्योंकि यह किसी को दी नहीं गई मैं इनके क्षेत्र सालहावास के बारे में ही इनको बताना चाहूंगा कि वहां 18 हरिजन कन्याओं की शादी में यह राशि दी गई है। यह लिखित रूप में दे दें उनकी पूरी जानकारी इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। 18 वर्ष की जो भी हरिजन कन्या है उसकी शादी के लिए हमने यह राशि दी है, यह सरकार का फैसला है और सरकार की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय साथी ने तो यहां तक भी कह दिया था कि 18 साल की उम्र की सीमा न रखी जाए। शायद वे भारतवर्ष के संविधान से अनभिज्ञ हैं, उनको शायद यह जानकारी नहीं है कि 18 साल की शर्त रखी जानी जरूरी है। (विघ्न) यह बात शायद राव नरेन्द्र सिंह जी ने कही थी, वह तो बुद्धिमान आदमी माने जाते हैं। हमारे संविधान के मुताबिक 18 साल से कम आयु की कन्या की शादी नहीं हो सकती। ऐसी शादी करना एक अपराध है और हम अपराधी बनने के लिए तैयार नहीं है लेकिन जो निर्णय लिया गया उसके मुताबिक हम यह राशि देंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी कृषि के मामले पर बहुत चर्चा की गई। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश में लोगों का गुजारा खेती पर ही होता है। हरियाणा प्रदेश में उद्योग भी लगे हुये हैं लेकिन जो उद्योग लगे हैं उनमें से 91 प्रतिशत उद्योग कृषि पर बेसड हैं। इसलिए खेती को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेवारी है। अध्यक्ष महोदय, डीजल के जो भाव केन्द्र सरकार ने बढ़ाए थे उस का प्रचार इन्होंने चुनावों में बहुत किया था, इस बात को इन्होंने बहुत उछाला था। इन्होंने यह भी कहा था कि इण्डियन नेशनल लोक दल और भारतीय जनता पार्टी की सांझा सरकार है और इन्होंने ही

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

डीजल के भाव बढ़ा दिए जिससे किसान बर्बाद हो गया है। ऐसी बातें इन्होंने चुनावों में उठाली थीं। यह बात अलग है कि लोगों ने इनकी बात को सुना नहीं था लेकिन मैं इन की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, खासतौर पर भूपेन्द्र सिंह को कहना चाहूंगा कि जिस दिन केन्द्र की सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए थे उस दिन लोक सभा के मतों की गिनती होने जा रही थी। संयोग से उस दिन मैं चण्डीगढ़ में टेलिविजन के एक प्रोग्राम में था । मेरे साथ इनका एक दिग्गज नेता भी था। इनकी नजर में बड़ दिग्गज नेता होगा लेकिन जनता ने तो उसको धूल चटा दी है। शमशेर सिंह सुर्जेवाला जो आपकी पार्टी के किसान सैल के संयोजक हैं, शायद राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ होंगे, हमें तो पता नहीं है। (विघ्न) आप तो भजन लाल को भी कुछ नहीं मानते हैं। वहां पर मजबूरी में इनको उन्हें नेता मानना पड़ रहा है। आप तो अब भी उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। प्रेस में जाकर कहते हैं कि नहीं इसके साथ तो 6 ही विधायक थे (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे कृषक समाज के नेता है और कृषक समाज एक अलग संगठन है। वह नॉन पॉलिटिकल आर्गेनाईजेशन है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उसे नॉन पॉलिटिकल आर्गेनाईजेशन कहा जाता है। लेकिन वह आपकी पार्टी का नेता तो है। वह मेरे साथ उस दिन टी०वी० के एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था। भारत के 100 करोड़ लोगों में से मैं पहला व्यक्ति था जिस ने अपना विरोध जताया था कि केन्द्र सरकार ने डीजल के जो भाव बढ़ाए हैं इससे किसानों को आर्थिक नुक्सान होगा। देश की ग्रोअर पालिसी को भी नुक्सान होगा। इससे बसों के भाड़े बढ़ेंगे और रेलों का किराया बढ़ेगा। उपभोक्ता मंहगाई का शिकार हो जाएगा । इसलिए हम केन्द्र की सरकार से अनुरोध करते हैं कि डीजल के बढ़ाए हुए दामों को वापिस किया जाए। इसके अलावा मैंने आगे कहा था कि मेरी पार्टी के जो सांसद चुनकर जाएंगे। वे सदन में उसका विरोध करेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझसे गठबन्धन करने में पहले तो कई दफा गल्तियां हुई थी लेकिन बंसी लाल और कांग्रेस गठबन्धन हुआ और टूटा उससे मुझे वही बात याद आ गई जो कि एक भांड कहा करता था "नाना जी मरनो देखकर मरनो मन भाग गयो" । जो आपका गठबन्धन टूटा उससे मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि किससे गठबन्धन किया जाए किससे न किया जाए। इस मामले में मैं बहुत सूझबूझ से निर्णय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि चौधरी शमशेर सिंह सुर्जेवाला उस दिन मेरे पास बैठे थे उनको सांप सूंघ गया वे एक लफ्ज भी उस बारे में अपने मुंह से नहीं बोल पाए। (शेम-शेम) आप इस बारे में उनसे पता कर लें उनसे पूछें। अगर आपकी जगह मैं होता और मेरी पार्टी का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस प्रकार की कोताही करता तो मैं उसके खिलाफ डिसिप्लनरी ऐक्शन लेता। लेकिन आप तो * * * * * दिखाई दे रहे हैं। आप में यह हिम्मत नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अप्रजातांत्रिक व्यंग किया है इसको कार्यवाही से निकलवा दें। यह हमारी पार्टी का मामला है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह जो शब्द कहा है वह रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, वह शब्द रिकार्ड न किया जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर वह शब्द अनपार्लियामैंटरी है तो शायद मैंने कहने में गलती की होगी। वह शब्द तो अच्छा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, जिस शब्द से आपको ऐतराज था वह तो कार्यवाही से निकाल दिया गया है इसलिए अब आप बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो परिपाटी और परम्परा हमारे द्वारा शुरू की गयी थी अगर उसको बरकरार रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारी तरफ से कहीं भी कोई टोकाटाकी नहीं होगी। (विघ्न) मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझता हूँ और हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे। लेकिन जो बात जायज है, उपयुक्त है वह तो मैं जरूर कहूंगा। (विघ्न)

श्री रणवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप बैठ जाएं। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अभी चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने खुद कहा था कि किसान की जीरी के दाम बहुत कम हैं। केन्द्रीय सरकार यह भाव निर्धारित करती है। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने 15 दिन पहले उस वक्त के खाद्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला को टेलीफोन करके कहा था कि चूंकि इस बार किसान की जीरी जल्दी आ गयी है इसलिए इसकी खरीददारी जल्दी शुरू की जानी चाहिए। लेकिन उस समय केन्द्र सरकार ने यह कहकर जीरी को खरीदने से मना कर दिया कि उस समय जीरी में 12 परसैंट मोयशचर था। किसान को उसकी जीरी का पूरा दाम मिल सके इसके लिए हमने अपने जितने भी अदारे थे जैसे हैफेड वगैरह, उन सबको हमने बाजार में भेजा। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि पिछले साल के मुकाबले में हमने 6 गुणा ज्यादा जीरी खरीदी। मैं भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दिल्ली जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है की नरेला एवं नजफगढ़ आदि की जीरी भी हरियाणा में आकर बिकी। इसी तरह से राजस्थान जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, की जीरी भी हमारे प्रदेश में आकर बिकी है। यह जीरी हमारे प्रदेश में आकर इसलिए बिकी क्योंकि प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से किसान को उसकी जीरी का पूरा दाम देने की कोशिश की। (विघ्न) इस तरह से तो अध्यक्ष महोदय, काम नहीं चलेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर ये इसी तरह से हमें बार-बार इंट्रप्ट करते रहे तो हम दूसरा तरीका भी जानते हैं लेकिन उसको हम अख्तियार नहीं करना चाहते। जब मैं दूसरा तरीका अख्तियार करूंगा तब ये यहां पर नहीं टिकेंगे। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा यहां पर नाम लिया गया है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर ये इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। चौधरी भजन लाल जी, आप इनको समझाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। दलाल साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) कसान साहब, आप भी बैठें।

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से हाउस के नेता से यह कहना चाहता हूं कि वे इस तरह की ग्रेट न दें क्योंकि यह इनको शोभा नहीं देता है। हाउस ठीक चल रहा है। हाउस ठीक चलाने की जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही अपोजीशन की भी है। अच्छा हाउस तभी चलेगा जब अपोजीशन आपको पूरा कोओपरेट करेगा। अगर आप हंगामा करवाना चाहते हों तो वह तो अभी कर देंगे लेकिन उसका फायदा क्या है। इसलिए इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी मैम्बर की आत्मा को ठेस पहुंचे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम इनकी बात से सहमत हैं लेकिन इनको अपनी तरफ के लोगों को काबू में रखना चाहिए। इनको अपने सदस्यों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए। ये इनको संयम में रखें। हुड्डा साहब ने जो बात कही है उसका तो मैं जवाब दूंगा। इन्होंने जीरी के बारे में कहा लेकिन अब अगर ये बार-बार खड़े होंगे तो इस तरह की इंट्रप्शन बर्दाश्त नहीं होगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपने जो सरकार के बारे में कहा है उसके बारे में मैंने आपके प्वायंट नोट किये हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता खड़े हैं आप सभी बैठ जाइए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैंने आपके प्वायंट नोट किये हैं। जो बातें आपने कहीं हैं मैं उनका जवाब तो दूंगा ही। इस सदन में जिस किसी सदस्य ने सरकार के प्रति कोई बात कही है मुझे उसकी बात का जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मुख्य मंत्री जी ने कोई अनपार्लियामैन्ट्री बात नहीं कही है। इस बारे में आपने कहा था। रिफ्लाई आपके नाम से है इसलिए कहा गया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमैंट के अखित्यार में गन्ने के दाम मुकर्रर करना था। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व और फख्र महसूस होता है कि हमने सबसे ज्यादा गन्ने के भाव किसान को इस साल दिये हैं। हमने तो हरियाणा प्रदेश में ऐसे वक्त भी देखे हैं कि जब आठ आने प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम बढ़ाये जाते थे और जब किसान इसका विरोध करते थे, आन्दोलन करते थे तो घोड़ा पुलिस और ठंडे पानी के फव्वारे उन पर मारे जाते थे।

श्री अध्यक्ष : यमुनानगर में किसनों पर ठंडे पानी के फव्वारे मारे गए थे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में किसानों को गन्ने के जो भाव दिए गए उनसे किसान हमेशा संतुष्ट थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने किसान को 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के भाव दिये। भूपेन्द्र हुड्डा जी ने कह दिया कि महाराष्ट्र में किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम दिये गए लेकिन इन्होंने किसी एक मिल का भी उल्लेख नहीं किया कि फलां मिल में किसानों को गन्ने के 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम दिये गये। इनको ऐसी अनर्गल बातें इस सदन में नहीं कहनी चाहिए। इस सदन में सम्मानित सदस्यों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएं

जिनका कोई सिर पैर न हो। ये बताएं कि कौन सी मिल ने 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम दिये हैं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई कॉआपरेटिव मिल्ज ने किसानों को ये दाम दिये हैं मैं उनके नाम आपको बता दूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप उन मिलों के नाम बताएं। हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम पता करवाएंगे। आप सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए। मेरी जिम्मेदारी आप सभी को आराम से बिठाने की है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : किसानों के प्रति हमारी पार्टी कितनी हित चिंतक है इसका सबूत इसी बात से मिल जाएगा कि चौधरी देवी लाल ने ट्रैक्टरों पर सबसिडी देने का निर्णय लिया था। हमने हर संभव मदद करने का काम किया था। पारिवारिक संपति की डिक्री की प्रणाली के मुद्दे पर चौधरी बंसी लाल ने भाई बहिन के पवित्र रिश्ते में कटुता पैदा करने की कोशिश की थी और रजिस्ट्रेशन फीस 15 प्रतिशत लगा दी थी। फिर शराबबंदी की और शराबबंदी से होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए गलती पर गलती करते चले गए। अब हमने रजिस्ट्री की प्रथा को समाप्त किया है और डिक्री की प्रथा को शुरू किया है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री का रेट था जो कैबिनेट ने तय किया था। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने भाई बहन के रिश्ते में रिफुट पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने तो यह वायदा भी किया था कि बंसी लाल ने जो भाई बहन के बीच होने वाली डिक्री बंद की, मेरी सरकार आते ही मैं इसे खोल दूंगा लेकिन इन्होंने उसे खोला तो नहीं ?

श्री धीरपाल सिंह : सरकार आते ही डिक्री खोल दी थी।

श्री बंसी लाल : बिल्कुल नहीं खोली। शोर मचाने का कोई इलाज नहीं है। डिक्री कोई नहीं खोली क्योंकि डिक्री बंद हुई थी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत।

श्री अध्यक्ष : इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रियां होती है पन्द्रह रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर रजिस्ट्री की जाती है।

16.00 बजे **श्री ओम प्रकाश चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है और आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। इस बारे में इस सदन में जब बिल लाया जायेगा उस समय सारे सदन को भी मालूम हो जायेगा। हमने तो उससे भी दो कदम आगे जाकर दादी-पोती, नानी-दोहती तक कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाई किसानों के बड़े हितैषी बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री होते थे उस समय किसान जब बिजली मांगते थे तो उनको कादमा में गोलियों का शिकार बनाया जाता था, जब पानी मांगते थे तो नीसिंग में उन पर गोलियां चलाई जाती थी, नरवाना और टोहाना में किसानों को मरवाया गया। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आई तो उन्होंने उससे ज्यादा किसानों को मरवाया। इन दोनों में होड़ लगी हुई थी कि कौन किसानों को ज्यादा मरवाये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद के दाम बढ़ाने की बात है। हमारे स्टेट की सरकार के अख्तियार में जो था वह हमने किया। हमने दस रूपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद का दाम और डी०ए०पी० का दाम घटाया। केन्द्र सरकार ने जो खाद के दाम बढ़ाये हैं हमने निरन्तर उसका विरोध किया है और

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

लोकसभा में भी इसका विरोध करेंगे। किसानों के हितों पर जहां भी कुठाराघात होगा हम उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी यह नीयत नहीं है कि सदन में कुछ कहें और बाहर कुछ कहें। हम किसानों की भलाई के लिए ज्यादा ध्यान देने के पक्षधर हैं। हरियाणा में जमीन की होल्डिंग निरन्तर कम होती जा रही है और आमदनी के साधन घट रहे हैं खर्चा बढ़ता जा रहा है। किसानों को पशुधन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से पूरे पैसे उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसी अच्छी सोच हमारी सरकार की है। जैसे इजराईल में हमारे प्रदेश जैसा क्लाईमेट है और वहां की गाय 35 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। हमारी सरकार की सोच है कि किसानों का एक शिष्टमंडल इजराईल भेजा जाये जो वहां जाकर इस बारे पता लगाये। पहले चुनाव हो गये थे इसलिए यह काम नहीं हो सका था। अब इस शिष्टमंडल को भेजा जायेगा उसके बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी। फलॉरीकल्चर पर भी यह सरकार ज्यादा ध्यान देने की इच्छुक है ताकि फूलों की पैदावार को बढ़ावा मिल सके। इसलिए गन्ने की मिलें ज्यादा लगाने का इरादा हमने छोड़ दिया। एक साथी कह रहे थे कि सिरसा में गन्ने की मिल लगाने की क्या जरूरत है। उस साथी को सिरसा के इलाके के बारे में शायद अच्छी तरह से मालूम नहीं है इसीलिए वे यह बात कह रहे हैं। हम शुगर मिलें वहां लगाएंगे जहां शुगर मिल के लिए सारी चीजें उपलब्ध हों। हम केवल सिरसा गोहाना में ही नहीं बल्कि और जगहों पर भी शुगर मिलें लगाएंगे और जहां हम शुगर मिलें लगाएंगे वहां निश्चित रूप से गन्ना पैदा करने के लिए किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी देंगे।

श्री रघुबीर सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। भूना की शुगर मिल में 70 फीसदी गन्ना बाहर से आता है और वहां पर 40-40, 50-50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया जाता है। भूना की शुगर मिल को बने आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं, वहां आज तक किसानों को कोई ऐसी सहूलियतें नहीं दी गई कि गन्ने का एरिया बढ़ाया जा सके। उसी हिसाब से मैं कह रहा था कि सिरसा में चीनी मिल लगाने का कोई औचित्य नहीं है दूसरी तरफ आज बेरी के अन्दर 20 खांडसारी यूनिट्स हैं। जहां किसानों का शोषण होता है इसलिए बेरी में शुगर मिल लगाना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने हल्के बेरी की बात करें। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने जो निर्णय लिया था वह बहुत सोच समझ कर लिया था। चूंकि वह इलाका कॉटन पैदा करने वाला इलाका है। नरमा और कपास की फसल 3-4 साल से पूर्ण रूप से बरबाद हो गई है, खराब हो गई है। किसान को लाभ मिल सके इसके लिए हम चाहेंगे कि वह गन्ना पैदा करें। भूना की शुगर मिल में गन्ने की कमी का कारण यह नहीं था कि उस इलाके में गन्ना पैदा नहीं होता बल्कि उसका मुख्य कारण यह था कि बीच में जो कांग्रेस की सरकार आई उसने किसान के गन्ने के मामले को लेकर के ऐसा वातावरण खराब करने की कोशिश की कि किसान के 200 करोड़ रुपये बकाया पड़े रहे। पिछली सरकार के 21 करोड़ 38 लाख रुपये हमने दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी पानीपत और रोहतक की शुगर मिलों के बकाया राशि के लिए धरने में बैठने वालों में से एक थे। भजनलाल जी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आप मुख्यमंत्री थे। डॉ० रघुबीर सिंह जी तो उस सदन के सदस्य नहीं थे। इसलिए जो किसान दुःखी थे उन्होंने गन्ना बोना बन्द कर दिया था, गन्ना बिल्कुल उखाड़ दिया था। केवल पानीपत और रोहतक में ही नहीं बल्कि करनाल में भी किसानों ने गन्ना उखाड़ दिया था। यमुनानगर जिला जो सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करता है, में भी गन्ना कम पैदा हुआ था। अब हमने किसानों को प्रोत्साहित किया है, आप अगली दफा देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में गन्ने की फसल दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि किसानों को लाभ मिले इसके लिए हम

किसानों को सस्ती ब्याज पर ऋण भी देंगे। उनको अनेक प्रकार की और भी सुविधाएं देंगे। हम किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज समेत पैसा नहीं वसूल करेंगे। जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे तब वे एक बिल लेकर आए थे कि अगर किसान या दूसरा कोई भी किसी बैंक से 1,000 रुपये का ऋण लेता है तो उससे ज्यादा से ज्यादा 2,000 रु० तक ही वसूल किए जा सकते हैं लेकिन उससे चक्रवृद्धि ब्याज समेत पैसा नहीं वसूल किया जाएगा। वह बिल इस सदन में पास हुआ था लेकिन बदकिस्मती इस प्रदेश के लोगों की यह रही कि वह सरकार चली गई और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उस वक्त कांग्रेस की सरकार के मंत्री जिनको अब की बार लोगों ने सबक सिखा दिया है, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जो कि अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं जो अपने आप को स्वर्गीय दीन बन्धु सर छोटूराम का वारिस कहते हैं, कांग्रेस की सरकार के समय वही बिल लेकर आए थे कि किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज समेत पैसा वसूल किया जाए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में हमने बिल पास किया था कि जितनी राशि किसान बैंक से लेगा, उस किसान से डबल से ज्यादा वह राशि वसूल नहीं की जा सकती। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हां, भजन लाल जी आपकी बात भी ठीक है, चौधरी देवी लाल की जब सरकार थी, बदकिस्मती से उसमें भी आप वजीर थे। फिर जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपकी सरकार के मंत्री बीरेन्द्र सिंह ये बिल लेकर आए। आप तो जोकर हो, हर जगह फिट हो जाते हो। (हंसी)

श्री भजन लाल : मैं हर सरकार में मंत्री नहीं बनता। एक बार गल्ती और इत्फाक से चौधरी देवी लाल जी की सरकार में मंत्री बन गया था। जब मैंने देखा कि वे ठीक नहीं हैं तो मैं मंत्री की कुर्सी छोड़कर चौधरी देवी लाल की कुर्सी पर बैठ गया। हरियाणा का इतिहास यह कहता है कि बंसीलाल से राज लेता है चौधरी देवी लाल या देवी लाल के बेटे, चौधरी देवी लाल जी से राज लेता है भजन लाल और वह लेगा। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरे से तो राज किसी ने नहीं लिया, मैं तो दोबारा मुख्य मंत्री बनकर आया हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। कर्जा मुक्त बिल 1989 में पास किया गया था ताकि किसानों और कृषि मजदूरों से मूल से ज्यादा ब्याज न लिया जाये। (विघ्न) बाद में भजन लाल जी, आप मुख्य मंत्री बने और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी यह बिल वापिस लेने के लिए लाए थे। (विघ्न) मैं उस समय हाउस का सदस्य था इसलिए मैं इसे क्लैरीफाई कर रहा हूं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है। आप चैक करवा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, उस समय मैं उस बिल पर बोलने वाला था और आपने मुझे कहा कि वापिस ले लिया है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे इन भाईयों का कसूर नहीं है। जनता इतनी करारी मार मारती है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने तो करारी मार बहुत खा रखी है। उसके बाद भी ये ऐसी बातें बोलते हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि हम शुगर मिल ही नहीं लगा रहे बल्कि किसानों को पानी की पूरी व्यवस्था करायेंगे। ताकि किसान ज्यादा गन्ना पैदा करें। हम किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो घग्गर डैम काफी समय से बंद पड़ा था उसका काम भी शुरू कर दिया है। सैनी साहब ने दादूपुर नलवी नहर का जिक्र किया था जो लोगों की नजरों से दूर हो गई। स्पीकर सर, हम केन्द्र सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो सीमित साधन हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। पीछे वर्ल्ड बैंक की टीम हमारे यहां आई थी उसके साथ हमारी बात हुई थी। इस बारे में चौधरी संपत सिंह जी ने काफी बताया भी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी रिक्वैस्ट को उन्होंने नहीं माना। तब तक के लिए बिजली के एग्रीमैंट को सस्पैंड कर दिया गया और विपक्ष के भाईयों ने यह प्रचार कर दिया कि हमें लोन नहीं मिलेगा। हमारी सरकार ने लोन सील कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जब परमाणु बम विस्फोट हुआ था उस समय भी बहुत से देशों ने हमारा सब कुछ सस्पैंड कर दिया था और बाद में सब कुछ बहाल हो गया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे ध्यान में सभी बातें हैं और यह सब विचाराधीन हैं। हम अपने हक की बिजली और पानी लाने का पर्याप्त प्रावधान करेंगे। नये माईनर निकालेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सेम की समस्या को भी समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। उसको दूर करने के लिए हम ड्रेन्ज निकालेंगे, नालियां निकालेंगे ताकि किसान अपने खेतों में फसल बीज सकें। अध्यक्ष महोदय, जे०एल०एन० के दोनों तरफ रोड़ी, सिरसा, रोहतक और जुलाना का जो इलाका है उसमें सेम की बहुत भारी समस्या है। हमारी सरकार यह बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए हम जल्दी ही इस समस्या को दूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका दोबारा न आ सके इसके लिए भी हम उचित प्रबंध कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ आने से नहरें, सड़कें, किसानों की फसल आदि बरबाद हो जाती है, घर के घर बरबाद हो जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है और दोबारा से काम करने के लिए हजारों करोड़ों रुपये फिर लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब 1995 में बाढ़ आई थी उस समय चौधरी भजन लाल जी कहते थे कि इनकी सरकार केन्द्र से 600 करोड़ रुपये लेकर आई है जबकि वास्तव में 13 करोड़ रुपये ही आये थे। भजन लाल जी तो * * बोलने में गोबल्ज के भी बाप हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी तो * * * बोलने में सबको पीछे छोड़ गये।

श्री अध्यक्ष : जो अनपार्लियामैंटरी शब्द बोला गया है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जो पैसा मिलता है वह सब रिकार्ड में होता है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी मुख्य मंत्री हैं वे अपने वित्त मंत्री से कहें कि वे इनको फाईल लाकर दिखायें कि ऐसा कितना पैसा भारत सरकार से मिला है जिससे हमने किसानों की मदद की। जिन किसानों की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गईं हमने उनको तीन हजार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया। यह सब रिकार्ड की बातें हैं और फाईल मंगा कर मुख्य मंत्री जी देख सकते हैं। मुख्य मंत्री जी कम से कम फाइल देख कर तो बात करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह सारा लोन का पैसा था जबकि चौधरी भजन लाल जी कहते थे कि हम ग्रान्ट लेकर आये हैं। केन्द्र सरकार से ग्रान्ट के रूप में तो केवल 13 करोड़ रुपया मिला था। वह पैसा भी जिस तरीके से बांटा गया उसके बारे में इनकी पार्टी के ही एक सदस्य डा०

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

रघुबीर सिंह कादियान जिक्र कर रहे थे कि किसानों को मुआवजे के रूप में पैसा नहीं मिला। हमारी सरकार के आने के बाद जिन किसानों को फ्लड का मुआवजा नहीं मिला, उनको हमने 2 करोड़ 47 लाख रुपया और दिया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यही अधिकारीगण हमारे पास थे और यही अधिकारीगण इनके पास हैं। हमने इस काम के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई थीं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप परमिशन मांग कर खड़े हुआ करें। जब मर्जी आए, आप खड़े हो जाते हैं। आप पूछ कर खड़े हुआ करें। अपनी मर्जी से न खड़े हो जाया करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम कोई भी अनर्गल बात नहीं कहते। अध्यक्ष महोदय, असली मुद्दा जो था वह एस०वाई०एल० नहर का था जिस पर ज्यादा चर्चा हुई। एस०वाई०एल० नहर का जब जिक्र आता है तो चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि सारी मैंने बनवाई और चौधरी भजन लाल जी कहते हैं कि सारी मैंने बनवाई। पहली दफा चौधरी भजन लाल ने परसों बहस शुरू करते हुए एक बात कही थी कि अगर ओम प्रकाश चौटाला एस०वाई०एल० नहर का पानी ले आयें तो मैं उन्हें देवता मानूंगा। पहली दफा इन्होंने एक अच्छी सी शर्त रखी है। वरना ये तो यह कहा करते थे कि यह नहीं होता तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, नाक कटवा लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। आज तक तो इनकी इस तरह की भाषा रही है। लेकिन अब भी इनकी बात पर मुझे यकीन नहीं होता। यकीन इसलिये नहीं होता क्योंकि ये लोकसभा चुनावों में भी यह कहते थे कि अगर आदमपुर से हमारी पार्टी का उम्मीदवार हार जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और ओम प्रकाश चौटाला को अपना गुरू मान लूंगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं किये कि आदमपुर से हमारी पार्टी का उम्मीदवार हार जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने तो यही कहा कि मेरे हल्के के लोगों ने यह महसूस किया कि सुरेन्द्र सिंह हारना चाहिए और सुरेन्द्र सिंह को कौन हरा सकता था, सुरेन्द्र सिंह को अजय चौटाला हरा सकता था इसलिये आदमपुर के लोगों ने उस समय अजय चौटाला को वोट डाल दिये इसलिये इनको तो आदमपुर के लोगों को दाद देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमपुर हल्के के लोगों ने दो महीने पहले 32 हजार वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया हो, उसी आदमपुर हल्के से भजन लाल 47 हजार वोटों से जीता है। क्या देश में ऐसा कोई लीडर हो सकता है ? अगर कोई ऐसा लीडर है तो किसी एक का नाम ये बता दें। ऐसी मिसाल देश में कहीं नहीं मिलेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब हम कौन से नेता को मान कर चलें। जो नेता लोकसभा चुनावों में एक साल पहले करनाल से एक लाख वोटों से जीता हो उसी नेता की पी०एच०डी० की डिग्री करनाल के लोगों ने फाड़कर फैंक दी। क्या ये नेता वही है या कोई दूसरा नेता है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, नेता वही है लेकिन इलाका नया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो करनाल से एम०पी० बनना नहीं चाहता था। अगर मैं वहां से एम०पी० बनता तो एम०एल०ए० का चुनाव कैसे लड़ता और एम०एल०ए० का चुनाव न लड़ता तो उस कुर्सी पर कैसे बैठूंगा ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनके हल्के से गणेशी लाल जी भी नए थे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एस०वाई०एल० का जिक्र किया गया। चौधरी बंसी लाल जी इस सारे मामले से जुड़े हुए हैं। पंजाब राज्य के गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में एस०वाई०एल०

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

का जिक्र किया और विशेष रूप से राइपेरियन स्टेट के राईटस का जिक्र किया। यह पानी हिमाचल से निकलता है और राजस्थान तक चला जाता है। जिस स्टेट से पानी निकलता है उसी स्टेट के अन्त तक पानी जाये तो उसे राईपेरियन स्टेट्स कहा जाता है। जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ तो इन नदियों में जो पानी था उस हिसाब से हमारा भी हक उस पानी के अन्दर बनता है। जब भारत और पाकिस्तान बने तब ये नदियां अन्तर्राष्ट्रीय बन गई थीं तो उस समय भी भारत और पाकिस्तान में भी पानी का बंटवारा हुआ था। उसी तरह से पंजाब और हरियाणा जब अलग-अलग स्टेट्स बनीं तो हमारा भी पानी पर हक बनता है। इस संबंध में जितने भी फैसले हुए थे वे बंसी लाल जी व भजन लाल जी की सरकारों के समय में हुए थे। हम चाहते हैं कि जो उस वक्त फैसले हुए थे वे इम्पलीमैंट हों। उसको इम्पलीमैंट करने के लिए हमने जमीन का अधिग्रहण भी किया और पंजाब को भी एक करोड़ रुपये इस नहर को बनाने के लिए दिए। उस पर काम भी हुआ। बाद में एक चीफ इन्जीनियर की उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई, जिस कारण बाद में उस नहर का काम रुक गया था। बीच में जब मैं मुख्य मंत्री बना था तो उस वक्त के प्रधानमंत्री से मिलकर मैंने इस काम को करवाने के लिए बी०आर०ओ० के सुपुर्द करवा दिया था। बाद में जब केन्द्र में आप लोगों की सरकार आई तो आपने यह काम वापस ले लिया।

श्री बंसी लाल : अब तो केन्द्र में आपके प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलकर चन्द्रशेखर जी वाले फैसले को इम्पलीमैंट करवा लो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को लैटर लिखा जा चुका है। हम इस मसले का जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एस०वाई०एल० हरियाणा के लिए एक जीवन रेखा है। हम इस मामले में जनता को बरगलाना नहीं चाहते, एस०वाई०एल० बननी चाहिए। यह किसी एक दल का मुद्दा नहीं है। यह सारी स्टेट का मुद्दा है और सभी दलों का एक ही मुद्दा है कि यह एस०वाई०एल० नहर अवश्य बननी चाहिए। हम सभी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए कि यह नहर जल्दी से जल्दी बने। बंसी लाल जी, आपको याद होगा कि जब आपने इस इशू पर आल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें हम सभी शरीक हुए थे और आपने जो सहयोग और समर्थन हमसे मांगा था, वह हम देने को तैयार थे। आज भी हम सब इस मामले में एक हैं और एक ही रहना हरियाणा के हित में होगा। इस विषय पर सभी विवादों को भुला कर हमें एक रहना चाहिए। (विघ्न) भजन लाल जी, जब राजीव लौंगोवाल एकोर्ड हो रहा तो उस वक्त आपको तो पूछा ही नहीं गया, बल्कि आपको एक चपड़ासी की तरह बाहर बैठने के लिए कह दिया गया था। (विघ्न)

श्री भजन लाल : चौटाला साहब, आप बोल तो ठीक लें। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मेरे नीचे चपड़ासी लगे हों।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या आप उस बैठक में थे ?

श्री भजन लाल : मैं आपको व सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब इस विषय पर बातचीत चल रही थी तो राजीव जी ने बाकायदा मुझ से इस विषय पर डिस्कस किया था। जिस समय लौंगोवाल से बातचीत चल रही थी उस वक्त मैं साथ लगते राजीव जी के कमरे में ही बैठा था तथा मीटिंग समाप्त होने से पहले भी मेरे से राजीव जी ने बात की थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हितों का फैसला हो रहा हो और उस फैसले में हरियाणा का मुख्य मंत्री मौजूद न हो और उस फैसले पर इनके दस्तखत न हों तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितनी पूछ इनकी रही होगी ? (विघ्न) बंसी लाल जी, आपने तो हरियाणा को 70 हजार एकड़ जमीन के बदले में बेचने का निर्णय ले लिया था। चौधरी बंसी लाल जी, इराडी ट्राईब्यूनल का एक सदस्य जो कम हो गया था आप तो उस सदस्य को भी मुख्य मन्त्री होते हुए नहीं लगवा सके थे। उस मैम्बर की जगह पर दूसरा मैम्बर भी हमने लगवाने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि इनके पास सारा रिकार्ड है ये देख लें। हमने उसके लिए बाजपेयी जी को चिट्ठियां लिखी तथा होम मिनिस्टर जी को भी चिट्ठियां लिखीं थीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सारा रिकार्ड है इसीलिए तो मुझे इस बात का ज्ञान है। हमारी यह जिम्मेदारी है और हरियाणा के हित हमारे लिए सर्वप्रथम हैं। हम इस प्रदेश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इस प्रदेश के हितों की रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है इसके लिए मैं हाउस के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हम सब लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि बिजली, लॉ एण्ड आर्डर, हुड्डा, सड़कों के बारे में तथा दूसरे मामलों के बारे में इससे पहले मेरी कैबिना के सदस्यों ने काफी विस्तार से चर्चा की है इसलिए मैं इनके बारे में और कुछ कह कर सदन का समय बरबाद करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब प्रजातान्त्रिक प्रणाली को बरकरार रखें क्योंकि यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर जनतन्त्र समाप्त हो जाएगा तो उसका जो विकल्प है वह बहुत ही भयानक है इसलिए प्रजातान्त्रिक तरीके से स्वस्थ क्रिटिसिज्म किया जाए और स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली को बरकरार रखा जाए। हरियाणा के हितों की रक्षार्थ हम सब को मिल कर काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कई मामले ऐसे हैं जिनकी अगर मैं चर्चा करूंगा तो अच्छा सा नहीं लगेगा लेकिन हमारी जो नई औद्योगिक नीति है उसकी मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। हमारी इस नई औद्योगिक नीति को न केवल हरियाणा प्रदेश के उद्योगपतियों ने, न केवल इस देश के उद्योगपतियों ने, न केवल एन०आर०आई० ने बल्कि विदेशों की बड़ी कम्पनियों ने भी बहुत पसन्द किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां चौधरी बंसी लाल जी के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश से उद्योग धन्धे पलायन कर गए थे वहीं आज उद्योगपति हरियाणा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनके शासनकाल में जब मानेसर में नई औद्योगिक स्टेट कायम की गई थी तो केवल तीन प्लाट वहां पर बिके थे लेकिन हमारी नई औद्योगिक नीति को लोगों ने इतना पसन्द किया है कि 394 प्लाट बिक चुके हैं। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं)** अध्यक्ष महोदय, 1600 करोड़ रुपये के नये उद्योग मानेसर में आ गए हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मानेसर का फैसला पहले जापान वालों के साथ था और चौधरी भजन लाल जी के शासनकाल से नैगोसियेशन चल रही थी। जापानी चाहते थे कि मानेसर में हम कौड़ियों के भाव पर उनको जमीन दे दें और फिर वे उस जमीन को ऊंचे दामों पर बेचें लेकिन हम ने इस बात से इन्कार कर दिया था। (विघ्न)

श्री धर्मपाल : चौधरी बंसी लाल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी धर्मपाल जी आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह चेयर को एड्रेस करके कहें, उनसे सीधे बात नहीं करें। मैंने आपको बोलने के लिए समय दे दिया है।

श्री धर्मपाल : अध्यक्ष महोदय, वे लोग 12 लाख रुपये पर एकड़ के भाव पर जमीन लेना चाहते थे लेकिन इनकी सरकार ने साढ़े छः लाख रुपये एकड़ जमीन दे कर किसानों को मरवा दिया। (विघ्न एवं शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वह जमीन ऐक्वायर करके लेना चाहते थे। हमसे ऐक्वायर करके फिर जमीन लेना चाहते थे और कीमत का तो कभी कोई सवाल ही नहीं था। लाख दो लाख या 12 लाख का तो कभी कोई सवाल ही नहीं था। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस नई नीति के घोषित होने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में छः गुणा बढ़ौतरी हुई है। केवल प्लाट-प्लाट की बात नहीं है यह बढौतरी जनवरी, 1999 से जनवरी, 2000 तक की अवधि में हुई है और यह आगे बढ़ कर 305 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। इस नई नीति के कारण आज 54,800 लोगों को रोजगार मिला है और 1600 करोड़ रुपये के नये प्रोजैक्ट्स हरियाणा में आए हैं। हॉण्डा कम्पनी ने 500 करोड़ रुपये का एक नया प्रोजैक्ट यहां पर लगाया है जो स्कूटर और थ्री व्हीलर बनाएगा। इस तरह से और भी दूसरी कम्पनियां आ रही हैं। हमारी जो नयी उद्योग नीति है उसमें कोई भी नया इन्सैंटिव नहीं देना पड़ेगा फिर भी लोगों ने हमारी उद्योग नीति को इसलिए पसन्द किया है क्योंकि हमने उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली दी है और उद्योगों तक पहुंचने के लिए सड़कों की मरम्मत की है। पहले तो जब बाहर से लोग आते थे तो उनके सिर गाड़ी की छत से टकराते थे और वे कहते थे लो आ गए बंसी लाल के राज में। हमने कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। लोगों की जानमाल की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। बंसी लाल जी, आपने तो माफिया ही खड़ा कर दिया था। (विघ्न) उस समय भी मैं आपको सदन में यही बातें कहा करता था लेकिन आपने शराबबंदी करने की वजह से हरियाणा में माफिया खड़ा कर दिया था।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी नीयत तो 16 आने ठीक थी।

कृषि मंत्री (श्री जसविन्द्र सिंह संधू) : लेकिन छोरे की नीयत तो ठीक नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि हम नई शिक्षा नीति भी लागू करने जा रहे हैं। उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से इन्फर्मेशन टैक्नौलोजी को भी बढ़ावा देने जा रहे हैं। इसके सिलसिले में कई बार बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और प्रदेश प्रगति के पथ पर चले। आपके द्वारा जो विवाद और बखेड़े खड़े किए गए थे उनको समाप्त करने का काम हमने किया है। जब अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट का जिक्र आ रहा था तो गुप्ता जी बड़े तैस में आ रहे थे। वे कह रहे थे कि भजन लाल जी ने ये ग्रान्ट बंद नहीं की है। 11 जुलाई, 1995 का लैटर है जिस बारे में बंसी लाल जी ने भी बताया है, प्रैस कांफ्रेंस में कहा था। गुप्ता जी, आप कह रहे थे कि हमने ग्रान्ट बंद नहीं की तो मैं आपको यह बता दूं कि उस लैटर में आपके भी हस्ताक्षर हैं। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इनसे कहें कि ये वह लैटर दिखा दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप उस मीटिंग में थे कि नहीं थे ? (विघ्न) अग्रोहा मैडिकल कालेज को बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ है, दोनों बराबर के भागीदार हैं। दोनों ने ग्रांट बंद की थी। पता नहीं आपकी व्यापारियों से क्या लड़ाई थी ? मुझे तो हैरानी यह है कि गुप्ता जी इन दोनों की भी सराहना

कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं जो इनके प्रति जहर से भरे हुए हैं। गुप्ता जी, आप उनके लिए यह बात कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं इनको आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास रिकार्ड है कि 1995 में भजन लाल ने ग्रांट बंद करी है तो ये कृपया करके दिखाने का कष्ट करें। हमने तो वह ग्रांट चालू करी है। हमने उससे अगले साल में बजट में दो करोड़ रुपए मैडिकल कालेज के लिए रखे थे।

श्री सम्पत सिंह : चौधरी साहब, तीन ग्रांटस थी रैकरिंग, नॉन रैकरिंग और अपरेट्स के लिए। उसमें से एक ग्रान्ट तो आपने बंद कर दी थी जिससे आप मुकर रहे हैं। दूसरी ग्रान्ट बंसी लाल जी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद बंद कर दी। अब आप मुकर रहे हैं यह रिकार्ड की बात है हम ये लैटर सदन की टेबल पर रख देंगे। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, मैंने हाउस में पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि 31 मार्च सन, 1996 तक हम सभी ग्रांट्स देकर गए हैं। (विघ्न) 1996-97 का बजट भी हमने ही पास किया था उसमें हम अगले साल के लिए दो करोड़ रुपया उस मैडिकल कालेज के लिए ग्रांट के रूप में छोड़कर गए थे। इसलिए यहां पर गलत बात कहने का क्या फायदा है। (विघ्न) स्पीकर साहब, 1991 से लेकर 1996 तक लगातार मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि जितनी ग्रांट्स हमने अपने पांच साल के शासन काल में दी हैं उतनी किसी ने नहीं दीं। धौटाला साहब ने कहा है कि सात करोड़ रुपये की ग्रांट उस मैडीकल कालेज को अनाऊंस की है लेकिन जहां तक मुझे पता है इन्होंने केवल एक करोड़ रुपये ही दिए हैं।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ग्रांट का पैसा एक बार में इकट्ठा नहीं मिलता। हर काम के लिए अलग-अलग पैसा मिलता है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सात करोड़ रुपये ग्रान्ट देने के बारे में तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी लिखा है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गुप्ता जी की बात को क्लैरिफाई कर दूं। सात करोड़ रुपये का सप्लीमैंट्री बजट हमने इसके लिए पास किया है। गुप्ता जी, आप तो वित्त मंत्री रहे हैं इसलिए आपको तो मालूम ही है कि पैसा एक साथ इकट्ठा नहीं दिया जाता। जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा वैसे वैसे उनको पैसा मिलता जाएगा। जो तनख्वाहों का पैसा पैंडिंग था वह हमने सारे का सारा दे दिया। इसी तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए भी टैंडर्ज वगैरह हो गये हैं। अगर बिल्डिंग बनाने पर पैसा खर्च होगा वह भी हम देते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट का जो पैसा होता है उसको सरकार इकट्ठा रिलीज नहीं कर सकती। जैसे-जैसे उस कालेज का काम चलता रहेगा वैसे-वैसे हम उसको पैसा देते रहेंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि कल इन्होंने बजट पेश करना है कृपया करके ये कल हमें बता दें कि हम उस मैडीकल कालेज के लिए दो करोड़ रुपये का अपने बजट में प्रावधान करके गए थे या नहीं ? हमने 1991 से 1996 तक उस मैडिकल कालेज के लिए 6 करोड़ रुपये दिए हैं या नहीं। उसकी ग्रांट को बंद किसने किया और शुरू किया तो किसने किया ? ये बातें हमें बता देना।

श्री सम्पत सिंह : कल आपको सारी बातें बता देंगे और वह लैटर भी हाउस की टेबल पर रख देंगे। हमने उस वक्त भी कहा था कि दो करोड़ रुपये उसके लिए कांग्रेस की सरकार मंजूर करके गई थी लेकिन भजन लाल जी, इस तरह की तीन ग्रांट्स थी। ये हैं—रैकरिंग, नॉन-रैकरिंग एवं अपरेट्स के लिए। एक मैचिंग ग्रांट थी और एक 99 परसैंट वाली ग्रांट थी इसमें से एक ग्रांट आप बंद करके गए थे और बाकी ग्रांट्स चौधरी बंसी लाल जी ने बंद कर दी थी। एक ग्रांट को आपने कंटीन्यू रखा जिसको हम भी कहते हैं लेकिन एक ग्रांट आपने बंद की थी यह रिकार्ड की बात है और वह रिकार्ड हम आपको ला कर दिखा देंगे। हम तो कहते हैं कि दो करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में था लेकिन एक ग्रांट तो आपने बंद कर दी थीं। (विघ्न) 1995 तक ऐज पर ऐग्रीमैंट काम चलता रहा। (विघ्न)

श्री भजन लाल : लेकिन आप तो कहते हैं कि आपने उस मैडिकल कालेज को सात करोड़ रुपये दिए।

श्री सम्पत सिंह : हमने यह नहीं कहा कि हमने सात करोड़ रुपये दिए बल्कि हमने यह कहा कि हम सात करोड़ रुपया देंगे। बाकी पैसा हम सैंक्शन कर रहे हैं। पिछले जो सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स थे वह भी सैंक्शन करवाने पड़ते हैं हम पब्लिक के खजाने के कस्टोडियन हैं इसलिए विद अप्रूवल ऑफ दि हाउस खर्चा किया जाता है। सात करोड़ रुपये का प्रावधान सप्लीमैंट्री बजट में रखा गया है। ज्यों ज्यों पैसा खर्च होता जाएगा हम और पैसा देते जाएंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इनको तो यह भी पता नहीं है कि कौन सी ग्रांट बंद कर दी थी। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बारे में एक लेटर है मैं गुप्ता जी की तसल्ली के लिए इसको यहां पर पढ़कर सुना देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 11-7-1995 को मीटिंग हुई उसमें अग्रोहा सोसायटी की तरफ से श्री बी०डी० गुप्ता, श्री एल०सी० गुप्ता, आई०ए०एस० (रिटायर्ड), श्री जी०डी० गोयल, श्री राम कुमार गुप्ता, श्री एफ०सी० सिंघल, श्री पी०डी० अग्रवाल और गवर्नमैंट की तरफ से श्री मांगे राम गुप्ता, श्री धनेन्द्र कुमार, आई०ए०एस०, श्रीमती सुधा शर्मा स्पैशल सैक्रेटरी फाइनैंस, श्री धनपत सिंह, आई०ए०एस०, श्री शिव रमन गौड़ थे। जो यह चिट्ठी है जिसकी आप बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हो उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं—

"The meeting was held on 11-7-95 at 11.30 A.M. under the chairmanship of Hon'ble C.M. Haryana in his Office Room.

The list of participants is enclosed.

Shri Banarsi Dass Gupta, Ex. C.M., Haryana and Patron of Society requested Hon'ble C.M. that the recurring expenditure to the tune of 9% be given by the Govt. to run the Medical College as provided in the agreement vide condition No. 9. The Hon'ble C.M. told Sh. B.D. Gupta and other office bearers of the Society that the State Govt. had spent an amount of Rs. 1.12 crore for acquisition of 267 acres and 14 marlas of land for the institute. Apart from this, another 4.94 crores have been given as matching grant by the State Govt. for construction of Medical College building. No other private institute in the state has been given so much financial assistance. The

agreement was incquitable and not just further keeping in view the decision of Hon'ble Supreme Court in the Writ Petition (C) No. 317/ 93 TMA Pai Foundation and other Vs. State of Karnataka and others, decided on 13-5-1994 whereby the Medical College was free to charge upto Rs. 1.10 lacs per annum from the students seeking admission against payment seats. The Medical College was also entitled to charge any amount from those seeking admission under NRI quota. Therefore, the Society should run the Medical College and Hospital on its own without seeking any Govt. help for recurring expenses. A decision to this effect was taken by the Govt. and conveyed to the society.

Shri L.C. Gupta, IAS (Retd.) Advisor of the Society requested that until the college become fully functional after getting recoguition from Medical Council of India, the society will not be able to meet the recurring expenses from the capitation fee taken for payment seats. He requested on behalf of the Society that for the current year, the Govt. may bear recurring expenses in the ratio of 99 : 1 from the existing budget provision as lot of medical equipments are to be purchased and salary of the staff working in the Medical College is to be provided. All other members of the Society also made similar request for sympathetic consideration.

After detailed discussion, it was agreed that the recurring expenditure for the current financial year i.e. upto 31-3-1996 will be borne by the State Govt. in the ratio of 99 : 1 from the existing budget provision. Matching grant for construction will be given to the society against the amount to be deposited by the society for construction work. This arrangement would be valid only for the current financial year."

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो लैटर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा है। मैं यह मानता हूं कि मैं उस कमेटी की मीटिंग में मौजूद था जिसमें यह फैसला लिया गया था। लेकिन कमेटी के दूसरे मैम्बर जैसे श्री बी०डी० गुप्ता, श्री बी०डी० गोयल उन सबकी रजामंदी से ही यह फैसला हुआ था। उस समय यही फैसला लिया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें यह इजाजत दे दे कि एन०आर०आई० से एडमिशन के समय हम पेड शीट्स के लिए दस-दस लाख या 20-20 लाख रुपये मेडीकल कालेज अग्रोहा में दाखिले के लिए ले लेते हैं तो सरकार का काफी खर्चा कम हो सकता है क्योंकि हमारे लड़के भी महाराष्ट्र और बंगलौर में मेडिकल कालेजों में दाखिला लेने के लिए दस-दस लाख या 20-20 लाख रुपये देते हैं। इसलिए 31-3-1996 तक तो हम ग्रान्ट दे ही रहे थे। हमारी सरकार ने तो अग्रोहा मेडिकल कालेज की ग्रान्ट बन्द नहीं की।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बैठिये। आपने काफी कुछ कह दिया है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, 1996 में शराबबंदी के नाम पर चौधरी बंसी लाल जी ने विधायकों की ग्रान्ट बन्द कर दी थी। उसके बाद शराबबंदी तो खोल दी गई परन्तु विधायकों की ग्रान्ट को पुनः बहाल नहीं किया गया जबकि उसके बाद टैक्स भी लगाये। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जो देवता स्वरूप हैं से अनुरोध है कि विधायकों की ग्रान्ट पुनः बहाल की जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्पोर्टस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। खेलों के मामले में हमारी सरकार की तरफ से काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि खेलों में हमारे खिलाड़ी काफी नाम कमायें। उनको बसों में 75 प्रतिशत किराये की छूट देने का इस सरकार ने निर्णय किया है। इसके इलावा और ज्यादा से ज्यादा सुविधायें खिलाड़ियों को देने के लिए यह सरकार प्रयत्न कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पानी देने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए 50 करोड़ रुपये नये सिरे से खर्च करने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के प्रति व्यक्ति को 70 लीटर पानी प्रतिदिन के हिसाब से मिले। हमारी सोच यह है कि प्रदेश के हर गांव में पीने का स्वच्छ पानी पहुंच सके उसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि गांवों में जो पुराने वाटर वर्क्स हैं उनके इलावा हम अलग से और वाटर वर्क्स बनाने की योजना बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले। इसके लिए हम चाहेंगे कि वाटर वर्क्स को जाने वाले जो नाले हैं वे कवर्ड हों ताकि उनसे स्वच्छ और साफ पानी जाए क्योंकि खुले नाले में पानी खराब हो जाता है। चौधरी बंसी लाल ने निर्देश दिए थे कि जो पक्के खाले टूट जाएंगे उनकी किसान स्वयं मरम्मत करेगा लेकिन हमने बंसी लाल जी के उस फैसले को बदल दिया। अब उन टूटे हुए खालों की मुरम्मत भी सरकार करेगी क्योंकि हम लोगों के प्रति जवाबदेही हैं। पक्के खालों की मुरम्मत करना किसान के बस की बात नहीं है। हमने एक और फैसला यह भी किया कि जहां पर रास्ते के साथ लगते खाले हैं उन खालों की साइडों को 9 इंची बनाएंगे क्योंकि 3 इंची होने से वहां से गाड़ी या ट्रैक्टर जाते हैं तो वे खाले बैठ जाते हैं। हम चाहेंगे कि वे खालें पुख्ता बनें ताकि सिंचाई ठीक ढंग से हो सके। इस सदन में सैनिकों के सम्मान के बारे में बहुत चर्चा हुई है। कई लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। हमारी एक सोच है कि जो कौम और मुल्क अपने बुजुर्गों को, महापुरुषों को या शहीदों को भूल जाती हैं वह प्रदेश और मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपने साथियों को यह बताना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रैंक का सैनिक मरा हो और यदि सैनिक बोर्ड की तरफ से उसको शहीद घोषित किया गया है तो हमने उनको उसी हिसाब से 10 लाख रुपये की अनुदान राशि दी है। इस बात का फैसला तो सरकार करेगी कि किसने शहादत दी है। हमने कई तहसीलें भी बनाई हैं और इसके बारे में भी हमने एक फैसला किया है। पहले भी जब हमारी सरकार थी तब भी हमने एक निर्णय लिया था। हम चाहते हैं कि प्रशासन ठीक हो और प्रशासन से लोगों को सुविधाएं मिलें तथा लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ न बढ़े। इन्साफ हासिल करने के लिए लोगों को लम्बा सफर न तय करना पड़े। अभी जो विधान सभा के चुनाव हुए हैं इसमें आप भी सरकार की सराहना करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्ण हुए हैं। इन चुनावों में एक-आध इन्सीडैन्ट जरूर हुए हैं जिनकी आप लोगों ने यहां पर चर्चा की है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुख्यमंत्री महोदय अभी चुनावों की चर्चा कर रहे हैं परन्तु आप आज का दैनिक ट्रिब्यून अखबार पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि हरिजनों को वोट ही नहीं डालने दिए गए और उनको पीट कर बुथों से भगा दिया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहते हुए फख्र महसूस करूंगा कि हमने अपनी तरफ से निष्पक्ष चुनाव करवाने का भरपूर प्रयास किया है। किसी ने कटाक्ष की दृष्टि से कुछ कहना है तो वह अलग बात है लेकिन मेरी बात से आप सभी सहमत होंगे कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। अगर मैं अखबारों की कटिंग के हिसाब से पुराने चुनावों के किस्से सुनाने लगूंगा तो 17-12-94 को जो चुनाव हुए उसमें बूथ कैपचरिंग रोकने के लिए उपायुक्त पर पथराव और चुनाव मतदान में हिंसा में एक मरा। इसी तरह से एकली गांव के सरपंच की हत्या से चुनाव स्थगित हुआ। उस

समय चुनाव के दौरान करनाल में 252 मुकद्दमें दर्ज हुए और 400 लोग गिरफ्तार हुए। पंचायत चुनावों में बूथों पर गड़बड़ी व हिंसा भी हुई और पंचायत व पार्षद चुनावों में हिंसक घटनाएं एवं भलोट में मतदान भी नहीं हो पाया। वायलैंस मास हरियाणा पोल। दन कील्ड इन पोल वायलैंस। मैं मानता हूं कि इस बार भी 2 मर्डर हुए हैं परन्तु ये दोनों मर्डर चुनावों से सम्बन्धित नहीं हैं। ये आपसी दुश्मनी की वजह से हुए हैं। आप सबको यह मानकर तो चलना चाहिए कि छुटपुट घटनाएं तो जरूर हुई होंगी जैसे कहीं किसी ने कोई बक्सा उठाकर जोहड़ में फैंक दिया होगा तो कहीं किसी ने किसी को एक आध थप्पड़ मार दिया होगा। जो दो कत्ल हुए हैं वे दोनों कत्ल चुनाव से सम्बन्धित नहीं हैं। वे दोनों कत्ल पुरानी दुश्मनी के आधार पर ही हुए हैं। इसलिए आपको यह मानना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, फोर्मल हुए हैं, आज मैं आप सब लोगों को यह आश्वासन देना चाहूंगा और मैं अपनी सरकार की तरफ से आप सबको विश्वास दिलाऊंगा कि इन चुनावों के बाद जब पंचायतों और सरपंचों, समितियों और जिला परिषदों का गठन हो जाएगा उसके बाद हर गांव की पंचायत से हम लिखित रूप में रैजोल्यूशन मांगेंगे कि जो ग्रामीण पंचायतों के लोग लिखकर के रैजोल्यूशन देंगे कि हम फलां थाने में, फलां ब्लाक में, फलां तहसील में, फलां सब डिवीजन में और फलां जिले में शामिल होना चाहते हैं हम उनकी इच्छाओं के मुताबिक उनको एडजैस्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि जिले बढ़ें या घटें यह लोगों की इच्छाओं के मुताबिक होना चाहिए। हम इस फर्क को मिटाना चाहेंगे कि लोगों को एक जिले को पार करके दूसरे जिले में इन्साफ मांगने के लिए जाना पड़े। हम लोगों को उनकी इच्छाओं के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ-साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रजातंत्र में यकीन रखने वाली सरकार है। हम प्रजातांत्रिक प्रणाली को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे क्योंकि यह हमारी जिम्मेवारी है। इसमें विपक्ष के भाईयों को भी हमारा साथ देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी जगह जब चौधरी बंसी लाल जी थे और मैं चौधरी भजन लाल जी की जगह बैठा था तब बंसी लाल जी ने मुझे विपक्ष का नेता तो मान लिया क्योंकि मेरे साथ 24 सदस्य थे। लेकिन विपक्ष के नेता को जो कार मिलती है वह इन्होंने मेरे से छीन ली। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कार्य छोटे लोग करते हैं। जो छोटे कुल में पैदा हुए हों वे ही ऐसा काम करते हैं। (विघ्न) लेकिन हमने चौधरी भजन लाल जी को विपक्ष के नेता होने के नाते कोठी भी अलाट कर दी और कार भी दे दी। (विघ्न)

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, पहले तोशाम सब-डिविजन को तोड़ दिया गया था। क्या मुख्यमंत्री महोदय इसे दोबारा बनवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम वह बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हरियाणा की 36 बिरादरियों के भाईयों ने जो सद्भावना का वातावरण बनाया है हम सब उसे कायम रखें और मेरी प्रार्थना है कि राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव को यह सदन सर्वसम्मति से पास करे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

> "That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 9th March, 2000."

The motion was carried.

1999-2000 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किश्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1999-2000.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1999-2000.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Ram Pal Majra, Chairman, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1999-2000.

Shri Ram Pal Majra (Chairman, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary estimates (Second Instalment) 1999-2000.

1999-2000 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates (Second Instalment) will take place.

As per the past practice and to save the time of the House, the demands on order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand. But they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 1.000* for revenue expenditure and *Rs. 2,35,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 2—General Administration.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 10,54,20,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 3—Home.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 47,81,52,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 4—Revenue.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 9,18,07,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 5—Excise and Taxation.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs.3,26,26,28,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 6—Finance.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 75,92,29,350* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 9—Education.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 18,81,97,000* for revenue expenditure and Rs. 8,07,23,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 10—Medical and Public Health.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 25,75,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 12—Labour and Employment.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 73,26,01,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 1,17,80,000* for revenue expenditure and *Rs. 1,72,63,62,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No.—14 Food and Supplies.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 5,39,00,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 15—Irrigation.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 10* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 16—Industries.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 2,86,69,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 18—Animal Husbandry.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 86,52,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 19—Fisheries.*

[Mr. Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 51,71,46,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 21—Community Development.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 18,89,46,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 23—Transport.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 51,11,32,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.*

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कट-मोशन दी थी लेकिन आपने उसे डिस-अलाउ कर दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मैंने आपकी कट-मोशन रूल के हिसाब से डिस-अलाउ कर दी है। इसकी सूचना आपको मिल भी गई होगी। अगर आप सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं डिमाण्ड नं० 10 पर बोलना 17.00 बजे चाहूंगा। यह डिमाण्ड पब्लिक हैल्थ के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस सप्लीमैंट्री डिमाण्ड के तहत जितना पैसा पास करवा रही है उस हिसाब से सुविधाएं भी तो दी जानी चाहिएं। खास तौर पर नगरों को पीने का स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जाना चाहिए। मेरे हल्के रिवाड़ी के अन्दर मैंने खुद जाकर देखा है कि वहां पर कई पुरानी सीवरेज की लाइनें हैं और सीवरेज का पानी स्वच्छ पानी के साथ मिक्स होकर आ रहा है जिसकी वजह से आम नागरिकों में अनेकों बिमारियां फैल रही हैं। मेरे हल्के में गायसवाड़ा मौहल्ला है, छिबड़वाला मौहल्ला है और भी ऐसे दर्जों मौहल्ले हैं। इन मौहल्लों के लोग कहते हैं कि अगर उस पीने के पानी को बोतल में भर कर रखें तो उस पानी को आप देख नहीं सकते क्योंकि वह बहुत गन्दा पानी होता है। वहां के लोगों ने इस बारे में कई दफा प्रशासन से शिकायत की है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी में नई आबादी मौहल्ला है वहां पर स्टोन वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तथा सीवरेज लाइनें जो बनी हुई हैं वे इतनी खराब हैं कि बरसात के दिनों में बरसात का सारा गन्दा पानी इस कालोनी में इकट्ठा हो जाता है और एक तरह से इस कालोनी में बाढ़ आ जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के सीवरेज भी रुके पड़े हुए हैं। कई दफा लोग जाकर प्रशासन से मिल चुके हैं लेकिन आज तक वहां सीवरेज सिस्टम जो ठीक नहीं करवाया गया है। हाऊसिंग बोर्ड कालोनी जोकि सरकार द्वारा खुद बनाई गई उसमें भी बहुत बुरा हाल है क्योंकि सीवरेज का पानी लोगों के घरों में वापिस जा रहा है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा चेयर पर पदासीन हुए)** इसी तरह आजाद नगर में एक नाला है जिसका पानी बरसात होने पर आजाद नगर, महावीर नगर और अन्य कई नगरों में घुस जाता है इसलिये वहां पर पक्के नाले का प्रबन्ध करना चाहिए। वहां पर कोई ट्रीटमैन्ट प्लांट की भी व्यवस्था नहीं है। इसी

तरह रिवाड़ी शहर में उमावास और नयावास गांव हैं जहां पर बरसात के दिनों में ही नहीं बल्कि आज के दिनों में भी रिवाड़ी शहर का गन्दा पानी खड़ा रहने के कारण इतने मच्छर पैदा हो जाते हैं कि आम आदमी वहां बैठ नहीं सकता। इसके अलावा किसानों को जो पानी सिंचाई के लिये आप दे रहे हैं वह इतना गन्दा है कि उसमें अनेकों किस्म की बिमारियां हैं उसके लिये भी सरकार को बकायदा ट्रीटमैन्ट प्लांट लगाने की कोई पोलिसी बनानी चाहिए। सभापति महोदय, हमारी सरकार के दौरान कनाल बेस स्कीम के तहत वहां पर करीब 7 करोड़ रुपया लगाया गया था लेकिन वह ट्रीटमैन्ट प्लांट बहुत डिफैक्टिव हो चुका है क्योंकि उसके अन्दर ठीक तरह से दवाइयां नहीं डाली जाती हैं और जो पानी नगरों को भेजा जाता है वह सही तरीके से साफ भी नहीं है। इसलिये पानी की पूरी तरह से सफाई करवा कर और ठीक प्रकार से दवाईयां वगैरा डालकर स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया कराया जाना चाहिए। सभापति महोदय, गांवों में जो कनाल बेस स्कीम के तहत ट्रीटमैन्ट प्लांट है उनका भी काफी बुरा हाल है। वहां पर लोग खारा पानी पीना पसन्द करते हैं लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रीटमैंट प्लांट के तहत जो पानी सप्लाई किया जाता है उसको पीना पसन्द नहीं करते। (विघ्न)

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : कैप्टन साहब, मैं आपके बोलने पर कोई एतराज नहीं कर रहा। अभी बजट आना है, उस पर अपनी सारी बातें कह सकते हैं। ये जो सप्लीमैन्ट्री डिमांडज हैं इनके बारे में आप 1999-2000 के सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स (सैकेण्ड इंस्टालमेंट) के 24 नं0 पेज को पढ़ कर देखें। इसमें लिखा है कि ये क्यों अराईज हुई। Against the original provisions of Rs. 38.00 crore for payment of Energy Charges under Rural Water Supply Schemes of Public Health Department, a provision of Rs. 59.15 crore has to be made in Revised Estimates 1999-2000. जो एनर्जी चार्जिज बढ़े हैं उनकी वजह से ये डिमांड्ज अराइज हुई हैं। आप यदि डिमांड को पढ़ कर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पीकर साहब ने आपको बोलने का पूरा समय दिया है और बजट पर भी आपको पूरा समय मिलेगा। उस वक्त आप अपनी बात कह लेना।

श्री सभापति : कैप्टन साहब, ये सारी डिमांड एस्टिमेटस कमेटी में एग्जामिन हो चुकी हैं और कमेटी द्वारा ये सारी डिमांड्ज पहले ही पास हो चुकी हैं।

श्री सम्पत सिंह : कैप्टन साहब, एस्टिमेट्स कमेटी में सभी पार्टीज के मैम्बर थे। उन द्वारा ये डिमांड्ज पहले ही पास हो चुकी हैं। आप खुल कर गवर्नर एड्रैस पर बोले हैं और आगे बजट पर खुल कर बोल लेना। अब भी आप बोलना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये डिमांड्ज तो पहले ही कमेटी द्वारा पास हो चुकी हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप बजट पर अपनी बातें कह लें।

Mr. Chairperson : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Chairperson : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 1,000* for revenue expenditure and *Rs. 2,35,00,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 2—General Administration.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 10,54,20,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 3—Home.*

[Mr. Chairperson]

That a Supplementary sum not exceeding Rs. *47,18,52,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 4—Revenue.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 9,81,07,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 5—Excise and Taxation.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 3,26,26,28,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 6—Finance.*

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 75,92,29,350* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 9—Education.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 18,81,97,000* for revenue expenditure and Rs. 8,07,23,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 10—Medical and Public Health.*

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 25,75,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 12—Labour and Employment.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 73,26,01,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 1,17,80,000* for revenue expenditure and *Rs. 1,72,63,62,000* for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 14—Food and Supplies.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs.5,39,00,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 15—Irrigation.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs.10* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 16—Industries.*

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 2,86,69,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 18—Animal Husbandry.*

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 86,52,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 19—Fisheries.*

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 51,71,46,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 21—Community Development.*

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 18,89,46,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 23—Transport.*

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding *Rs. 51,11,32,000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2000 in respect of *Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.*

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 14th March, 2000.

*17.10 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 14th March, 2000).

31839—H.V.S.—H.G.P., Chd.